



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2017/अग्रहायण 22, 1939

No. 330]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2017/AGRAHAYANA 22, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन-रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कारिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-(टीडीआई) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच।

सं. 14/36/2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यतः मेसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट'-(संक्षेप में टीडीआई) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरूआत करने और पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 5.10.2016 की अधिसूचना संख्या 14/36/2016-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जिसके द्वारा पाटन-रोधी नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की गई है, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

4. प्राधिकारी ने 28.03.2017 की अधिसूचना संख्या 14/36/2016-डीजीएडी के साथ पठित दिनांक 10.04.2017 के शुद्धीपत्र द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान जांच में अनिन्तम पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ऐसी सिफारिशों के आधार पर दिनांक 04.06.2017 की अधिसूचना संख्या 25/2017-सीमा-शुल्क द्वारा अनन्तम पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सीमा-शुल्क की एक अधिसूचना जारी की थी।

क. प्रक्रिया

5. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- (1) आवेदन की प्रारंभिक जांच से कतिपय कमियों का पता चला जिन्हें बाद में आवेदक द्वारा सुधार दिया गया। अतः आवेदन को उचित ढंग से दस्तावेजी माना गया। प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जांच की शुरुआत करने का निर्णय लिया।
- (2) प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- (3) संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के प्रावधानों के अतिरिक्त कोरिया गणराज्य की सरकार को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 2.14 के उपबंधों के अनुसार संबद्ध आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में उनके दूतावास के माध्यम से सूचित किया गया।
- (4) जांच की शुरुआत के बाद, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों से दूतावासों, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार उनसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया। इन अनुरोधों को प्रस्तुत करने के लिए जहां आवश्यक हो प्राधिकारी द्वारा समय-सीमा को बढ़ाने की अनुमति दी गई।
- (5) प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6 (3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भेजी थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी। भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को विहित समय-सीमा के भीतर उनके उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।
- (6) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं : -

- (क) यनताइ जुली फाइन कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (ख) चांगझू दहुआ ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (ग) शंघाई बीएसएसएफ पालीयूरेथेन कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (घ) बायर मैटेरियल साइंस (चाइना) कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
- (ङ) मितसुई कैमिकल्स एंड एसकेसी पालीयूरेथेन्स, जापान
- (च) निप्पोन पालीयूरेथेन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, जापान
- (छ) हानवा फाइन कैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
- (ज) ओसीआई कार्पोरेशन/ओसीआई कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
- (झ) बीएसएसएफ कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

- (7) जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने उत्तर दिया है:

- (क) हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
- (ख) टीजे एएल मुलुक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई
- (ग) पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य
- (घ) आईएमएस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
- (ङ) एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य
- (च) बीएसएफ कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य

- (8) उक्त कंपनियों के अतिरिक्त चीन जनवादी गणराज्य की निम्नलिखित कंपनियों ने जांच में भाग लेने में रुचि दिखाई, यद्यपि उन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं करने का दावा किया।

- (क) वेनहुआ कैमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- (ख) चेंगडू दहुआ होलिंग कंपनी लिमिटेड

- (9) निम्नलिखित निर्यातकों ने भी जांच शुरूआत के बाद कतिपय अनुरोध प्रस्तुत किए हैं :

- (क) केवेस्ट्रो (हांग कांग) लिमिटेड
- (ख) मितसुई कैमिकल्स एंड एसकेसी पालीयूरेथेन्स आईएनसी

- (10) आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

1. शीला ग्रुप कंपनी
2. तिरुपति फोम
3. कर्लोन लिमिटेड
4. स्प्रिंगवैल मैटरेस
5. सनराइज फोम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6. एम. एच. पालीमर्स
7. प्यारेलाल फोम (साउथ)
8. जिंदल फोम
9. अलाइड फोम
10. ड्यूरा पफ
11. कैन्सी फोम
12. हिंदुस्तान पालीफोम
13. श्री मालानी फोम्स
14. प्राइम कम्फर्ट्स
15. स्प्रिंगफील पालीयूरेथेन्स
16. आदि पालीमर्स

- (11) प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर देते हुए जवाब दिया है :

- (क) शीला फोम लिमिटेड

- (12) उपरोक्त पक्षकारों के अतिरिक्त मेसर्स इंडियन पोलिएस्टर एसोसिएशन ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं की एक एसोसिएशन होने का दावा किया है और मेसर्स हेन्केई एडहेसिव्स टेक्नोलोजी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक-सह-प्रयोक्ता होने का दावा किया है, लेकिन जांच शुरू होने की तारीख से छः महीनों के बाद वर्तमान जांच में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। इन दोनों पक्षकारों ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं। तथापि, मेसर्स हेन्केई एडहेसिव्स टेक्नोलोजी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने यथा निर्धारित आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इन पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया है कि जांच शुरू होने की तारीख से अत्यधिक समय बीज जाने के बाद वर्तमान जांच में उनकी सहभागिता पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अत्यधिक विलंबित चरण में जांच में भाग लेने और निवेदन करने को सीधे खारिज कर दिया जाना चाहिए और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी घोषित कर दिया जाना चाहिए। तथापि, भाग लेने के अनुरोध की तर्कसंगतता के गुण-दोष और की गई आपत्तियों पर विचार किए बिना प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर जितना वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक था, विचार किया है और इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर उनका निदान किया है।
- (13) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- (14) घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएफपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा उसकी बिक्री करने की ईष्टतम लागत ज्ञात की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं।
- (15) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- (16) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन किया गया था। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना जहां लागू हो, पर वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- (17) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई थी।
- (18) जांच की कार्रवाई के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों और प्रदत्त सूचना को जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और वर्तमान जांच के लिए उन्हें जितना प्रासंगिक पाया गया है, प्राधिकारी द्वारा उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (19) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए 11.08.2017 और 17.10.2017 को सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने निवेदनों और साथ ही उनके उत्तरों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें और इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ ऐसे निवेदनों पर भी विचार किया गया है।
- (20) प्राधिकारी ने पीओआई के रूप में 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, (12 महीने) की अवधि पर विचार किया है ताकि बिल्कुल हाल के आकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। यह जांच 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 (पीओआई) की अवधि में की गई थी। तथापि क्षति विश्लेषण में प्रवृत्तियों की जाँच में अप्रैल 12 - मार्च 13, अप्रैल 13 - मार्च 14, अप्रैल 14 - मार्च 15 और जांच की अवधि को शामिल किया गया है।
- (21) आवेदक द्वारा आवेदन में द्वितीयक स्रोत (आईबीआईएस) के अनुसार आयात संबंधी सूचना प्रदान की गई है और जाँच शुरुआत के स्तर पर उसे स्वीकार किया गया है। तथापि, अन्तिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने विगत वर्षों और जांच अवधि के दौरान देश में संबद्ध वस्तुओं की मात्रा और मूल्य के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस से एकत्रित किए गए कारोबार-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है और उन पर इस अंतिम जांच परिणाम में भी विश्वास किया है।

- (22) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जांच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।
- (23) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2017 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उन पर अपनी टिप्पणिया 5 दिसंबर, 2017 तक अवश्य दे दें। प्रकटन विवरण पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (24) इस अंतिम जाँच परिणाम में *** चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- (25) सीमाशुल्क आकड़ों के अनुसार जांच अवधि के लिए अमरीकी डालर से भारतीय रुपये में परिवर्तन की विनिमय दर को 65.91 भारतीय रुपये प्रति अमरीकी डालर माना गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया के मूल का अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-टीडीआई है।
7. टोलीन डि-आइसोसायनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र सीएच₃सी₆एच₃ (एनसीओ) 2 है। छह संभव आइसोमर्स में से दो वाणिज्यिक रूप में महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (91-08-7)। 2, 4-टीडीआई को शुद्ध रूप में उत्पादित किया जाता है, परंतु टीडीआई को प्रायः 2,4 और 2,6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रणों में बेचा जाता है। वर्तमान जांच में पीयूसी उस टीडीआई से संबंधित है जिसकी आइसोमर मात्रा का अनुपात (80:20) है और कोई अन्य ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।
8. टीडीआई एक स्वच्छ तरल होता है और उसका प्रयोग फ्लेक्सिबल पालीयूरेथेन फोम, फर्नीचर कुशन, औद्योगिक गैस्केट, खेल और चिकित्सा प्रयोग के लिए सुरक्षा पैडों, आटोमोबाइल:सीटों, फर्नीचर, लाइनिंग, सन वाइजर आदि, मैकिंग: इलेक्ट्रॉनिक मदों, शीतित खाद्यों, दवाइयों, आडियो-वीडियो कंप्यूटर सीडी आदि में होता है।
9. चूंकि टीडीआई एक कार्बनिक रसायन है इसलिए इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत और आगे उपशीर्ष 29291020 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है, जो टोलीन डि-आइसोसायनेट से संबंधित है। तथापि जैसा आवेदक ने बताया है इस शीर्ष में आइसोमर (80:20) से इतर कतिपय ग्रेड भी शामिल हैं और इसलिए वर्गीकरण केवल सांकेतिक है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के आयात कुछ अन्य उपशीर्षों जैसे 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 और 39095000 के अधीन भी किए जाने की सूचना मिली है। डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आकड़ों की जाँच से पता चलता है कि पीओआई के दौरान आयात प्राथमिक रूप से उपशीर्ष सं. 29291020 के अधीन हुए हैं और उपशीर्ष 29291010 और 29291090 के अधीन भी काफी आयात हुए हैं। इस प्रकार, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के दायरे पर और अनुशंसित किए जाने वाले किसी उपाय, यदि कोई हो, पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
10. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-
“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
11. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर

प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अधीन इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- (क) इस जांच में विचाराधीन उत्पाद टोलीन डि-आइसोसायनेट (टीडीआई) है, जिसकी आईसोमर मात्रा 80:20 अनुपात में है और किसी भी अन्य ग्रेड के टीडीआई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। इस प्रकार एडहेसिव में प्रयुक्त होने वाले टीडीआई, जिसका बाद में प्रयोग खाद्य की पैकेजिंग के लिए किया जाता है, को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया प्रतीत होता है। फूड सेफ एडहेसिव का विनिर्माण करने के लिए आयातित 80:20 आईसोमर मात्रा युक्त फूड सेफ टीडीआई को विशेष रूप से वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। हेनकेल ने निवेदन किया है कि उन्होंने खाद्य आधारित उद्योग में प्रयुक्त करने के लिए उसका आयात किया है। अधिकतर भागीदार फोम विनिर्माता हैं और उनका अंत-उपयोग, आयातित वस्तुओं के हेनकेल के अंत-उपयोग से स्पष्टतया भिन्न है।
- (ख) हेनकेल ने अपने प्रारंभिक निवेदनों में "फूड सेफ एडहेसिव का विनिर्माण करने के लिए आयातित 80:20 आईसोमर मात्रा युक्त फूड सेफ टीडीआई" को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। तथापि, कंपनी ने "खाद्य की 0.01 एमजी/कि.ग्रा. की विशिष्ट माईग्रेशन सीमा युक्त टीडीआई" के बहिष्करण और खाद्य संबंधी अनुप्रयोग के निमित्त एडहेसिव को प्रयुक्त करने के लिए यूरोपीय यूनियन के विनियम 10/2011 के अनुपालन में अपने अनुरोध को वापिस ले लिया है।
- (ग) हेनकेल दो वर्षों से फूड सेफ टीडीआई को अधिप्राप्त करने के लिए याचिकादता से बात-चीत कर रहा है, जिसे फूड सेफ एडहेसिव का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तथापि, जीएनएफसी खाद्य की सुरक्षा और अपेक्षित टीडीआई विनिर्देशनों के संबंध में विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इससे यह स्पष्ट है कि हेनकेल द्वारा आयातित उत्पाद जीएनएफसी द्वारा विनिर्मित नहीं है।
- (घ) जीएनएफसी द्वारा विनिर्मित टीडीआई, फूड सेफ एडहेसिव के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारणवश हेनकेल को ऐसे फूड सेफ टीडीआई का आयात करना पड़ा है। जैसा कि दावा किया गया है, हेनकेल ने फूड सेफ टीडीआई के बहिष्करण की मांग करते समय कुछ विगत निर्णयों का भी उल्लेख किया है।
- (ङ) मित्सुई केमिकल एंड एसकेसी पोलिरिहेन्स इंक (एमसीएनएस) ने प्राधिकारी से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या इन दो उत्पादों नामतः "टीएम" और "एमटी" को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है अथवा नहीं। एमसीएनएस ने यह निवेदन किया है कि "टीएम" 50% अथवा उससे अधिक टीडीआई और पोलिमेरिक (पोलीमेथिलेनेपोलीफेनी/पोलीइसोकीनरेट अथवा पीएमडीआई) का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त "एमटी" 50% से कम टीडीआई और संशोधित मोनोमेरिक एमडीआई, 4.4'-(डाईफनील मेथेनिस्कोनेट) का मिश्रण है। एमसीएनएस ने यह निवेदन किया है कि टीडीआई और टीएम/एमटी के रसायनिक मिश्रण में व्यापक अंतर है और वास्तव में टीडीआई का उपयोग टीएम और एमटी की उत्पादन/विनिर्माण प्रक्रिया में किया जाता है।

घरेलू उद्योग के विचार

- (क) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में और साथ ही अन्तिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है और इसे अंतिम जांच परिणाम के लिए भी अपनाया जा सकता है।
- (ख) हेनकेल ने फूड सेफ टीडीआई को, जिसके आयात होने का दावा किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। तथापि, कंपनी फूड सेफ टीडीआई को बाहर रखने की आवश्यकता को प्रमाणित नहीं कर सकी है। इस तरह फूड सेफ टीडीआई को बाहर रखने का अनुरोध पूर्णतया गैर-प्रमाणित है और अत्यधिक अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त आयात भी फूड सेफ टीडीआई से संबंधित आंकड़े नहीं दर्शाते हैं। केवल इस आधार पर उक्त उत्पाद का बाहर रखने का अनुरोध तर्कसंगत नहीं है।
- (ग) हेनकेल ने बीजकों सहित अपने आयातों के पूरे व्यौरे भी प्रस्तुत नहीं किए हैं, ताकि प्राधिकारी द्वारा फूड सेफ टीडीआई के आयातों के तथ्यों की जांच की जा सके। हेनकेल ने निर्यातक प्रश्नावली का भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, ताकि उनके द्वारा आयातित टीडीआई और वर्तमान जांच में यथा वर्णित विचाराधीन उत्पाद के बीच अंतर की प्राधिकारी द्वारा जांच की जा सके।
- (घ) मात्र यह दावा कि घरेलू उद्योग उसका उत्पादन नहीं कर रहा है, वैध नहीं है क्योंकि जीएनएफसी समझता है कि उसके द्वारा उत्पादित टीडीआई, फूड ग्रेड टीडीआई की सभी रासायनिक और तकनीकी गुणवत्ताओं को पूरा करता है। हेनकेल ने जीएनएफसी से टीडीआई खरीदने में कभी रुचि नहीं दर्शाई है। ऐसे बहिष्करण की अनुमति देने के फलस्वरूप ऐसे बहिष्करण का दुरुपयोग होगा और बहिष्कृत मद के वेश में शुल्कों की प्रवंचना हो सकती है।

- (ड) इसके अतिरिक्त हेनकल ने फूड सेफ टीडीआई का कोई तकनीकी, रासायनिक और वाणिज्यिक ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके बहिष्करण की उसने मांग की है। हेनकल द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि सीमा-शुल्क विभाग के सामने फूड सेफ टीडीआई को कैसे अभिज्ञात किया जाएगा और आयात के समय प्रयुक्त इस किस्म की मद का नाम क्या था। आयात के आंकड़े फूड ग्रेड टीडीआई के किसी भी विनिर्देशन को नहीं दर्शाते हैं।
- (च) हेनकल ने फूड ग्रेड टीडीआई नामक उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की मांग करते समय पर्याप्त तकनीकी कारण नहीं बताए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हेनकल का संकेन्द्रण सामग्री को पाटित कीमतों पर प्राप्त करना है और उसके लिए ग्रेड का मुद्दा बनाया गया है। हेनकल तथ्यों के आधार पर ऐसा कोई सटीक कारण नहीं बता सका है कि फूड सेफ टीडीआई घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीडीआई से कैसे भिन्न है।
- (छ) जीएनएफसी के उत्पाद अर्थात् टीडीआई की तकनीकी तुलना के बारे में घरेलू उद्योग के प्रेक्षण नीचे दिए गए हैं, जिसके बारे में ऐसा समझा गया है कि हेनकल ने मांग की है:-
- (1) टीडीआई की परिशुद्धता: 99.9% (यह हेनकल द्वारा पूछी गई 99.5% निम्नतर तट सीमा से अधिक है)।
 - (2) जीएनएफसी की टीडीआई में इसोमर का % इस प्रकार है: 80+/-1:20+/-1:
 - (3) हाईट्रोलिजेबल कलोराईड 30 पीपीएम से कम है, जो कि मेसर्ज हेनकल की आवश्यकता के समान है।
 - (4) एचसीआई की एसिडिटी 400पीपीएम से कम बनी हुई है जो कि मेसर्ज हेनकल की आवश्यकता के समान है।
 - (5) रंग: सामान्यतया 15 एपीएचए+5 बना रहता है।
 - (6) एनसीओ 48.13 (% डब्ल्यू/डब्ल्यू) पर बना रहता है, जो कि मेसर्ज हेनकल की निम्नतर सीमा से अधिक है।
 - (7) भारी धातु: मार्च, 2016 में मेसर्ज हेनकल के साथ बैठक करने के बाद जीएनएफसी ने अपनी प्रयोगशाला में भारी धातु का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। जीएनएफसी इस विश्लेषण में कोई भारी धातु नहीं पा सका था। इसके अतिरिक्त इस संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि मेसर्ज हेनकल अपने द्वारा विश्लेषण करने के लिए टीडीए के नमूने के लिए कहेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा।
- (ज) भारी धातुओं के पहलु के संबंध में जीएनएफसी मेसर्ज हेनकल को टीडीआई का नमूना देने के लिए तैयार है और हेनकल तदनुसार अपने दावे कर सकता है। मेसर्ज हेनकल ने विगत में जीएनएफसी से टीडीआई खरीदने में कभी भी रुचि नहीं दर्शाई है। किसी भी स्थिति में फूड ग्रेड टीडीआई नामक कोई उत्पाद नहीं है और सामान्यतया उत्पादित और बेचे जाने वाला टीडीआई स्वभाविक रूप से अत्यधिक विषैला है।
- (झ) उपर्युक्त विश्लेषण से साफ पता चलता है कि ऐसा कोई तकनीकी कारण नहीं है, जिससे हेनकल फूड ग्रेड टीडीआई नामक उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने की मांग कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हेनकल का संकेन्द्रण सामग्री को पाटित कीमतों पर प्राप्त करना है और उसके लिए ग्रेड का मुद्दा बनाया गया है। जीएनएफसी अपना टीडीआई, हेनकल द्वारा किसी भी नमूना परीक्षण के लिए दे सकता है और हेनकल को तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर एक सटीक कारण के साथ सामने आना चाहिए कि वे अपने द्वारा उल्लिखित टीडीआई किस्म के उत्पाद के बहिष्करण की मांग को कैसे यथोचित समझते हैं और ऐसे आधार पर किसी भी बहिष्करण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (ञ) जीएनएफसी टीडीआई का एक उत्पादक है। टीडीआई की खरीद देश में की जाती है अथवा हेनकल द्वारा उसका आयात किया जाता है, जिसे हेनकल द्वारा बाद में और संसाधित किया जाता है, ताकि वह उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मेसर्ज हेनकल टीडीआई को एडहेसिव में परिवर्तित कर रहा है, जिसे प्लास्टिक पेकेजिंग में प्रयुक्त किया जाता है।
- (ट) हेनकल ने हेनकल फूड ग्रेड टीडीआई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। तथापि, एक आयातित उत्पाद के बहिष्करण की मांग करते समय हेनकल ने अपने द्वारा आयातित उत्पाद के ब्यौर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं। न ही उसने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उत्पाद के आयात की मात्रा, कीमत और अन्य ब्यौरे आदि भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और केवल बहिष्करण का अनुरोध किया गया है। वास्तव में हेनकल ने विगत में भी “फूड सेफ एडहेसिव्स का विनिर्माण करने के लिए आयातित 80:20 ईसोमर युक्त मात्रा के फूड सेफ टीडीआई” के बहिष्करण का अनुरोध किया था और बाद में उसे बदल दिया था और “खाद्य की 0.01 एमजी/कि.ग्रा. की विशिष्ट माईग्रेशन सीमा युक्त टीडीआई” के बहिष्करण का अनुरोध किया था और खाद्य संबंधी अनुप्रयोग के निमित्त एडहेसिव्स को प्रयुक्त करने के लिए यूरोपीय यूनियन के विनियम 10/2011 का अनुपालन किया था। प्राधिकारी आयातक के दावों की ऐसी असंगतियों को नोट कर सकते हैं।

- (ठ) इसके अतिरिक्त मेसर्ज मित्सुई केमिकल एंड एसकेसी पोलियरेथेन्स इंक के निवेदन भी कोई योग्यता नहीं रखते हैं और उनमें उठाया गया मुद्दा निराधार है। केवल टीडीआई को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया है और उसको जांच शुरू करते समय और अनन्तिम परिणाम में उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-टीडीआई है।

13. टोलीन डि-आइसोसायनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका सूत्र सीएच₃सी₆एच₃ (एनसीओ) 2 है। छह संभव आइसोमर्स में से दो वाणिज्यिक रूप में महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (91-08-7)। 2, 4-टीडीआई को शुद्ध रूप में उत्पादित किया जाता है, परंतु टीडीआई को प्रायः 2,4 और 2,6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रणों में बेचा जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद उस टीडीआई से संबंधित है, जिसकी आइसोमर मात्रा का अनुपात (80:20) है और कोई अन्य ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

14. चूंकि टीडीआई एक कार्बनिक रसायन है इसलिए इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत और आगे उपशीर्ष 29291020 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है, जो टोलीन डि-आइसोसायनेट से संबंधित है। तथापि जैसा आवेदक ने बताया है इस शीर्ष में आइसोमर (80:20) से भिन्न कुछ अन्य ग्रेड भी शामिल हैं और कोई अन्य ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

15. प्राधिकारी ने दावों की जांच की है और नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमतनिर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी विरोधी पक्षकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी अन्तिम रूप से यह मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

16. मेसर्ज हेन्केल एडहेसिव टेक्नोलोजीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के इस अनुरोध के संबंध में कि फूड सेफ टीडीआई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाए, हेन्केल और घरेलू उद्योग के निवेदनों पर विचार करने के बाद इस मुद्दे की जांच की गई है। जबकि हेन्केल का मूल प्रश्न यह है कि जीएनएफसी फूड सेफ टीडीआई का उत्पादन और आपूर्ति नहीं कर रही है, जिसका मुख्यतया उपयोग हेन्केल द्वारा किया जाता है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उसको शामिल किया जाना यथोचित नहीं है। जीएनएफसी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किया जा रहे टीडीआई उत्पाद में फूड सेफ टीडीआई की समस्त अनिवार्य गुणधर्मताएं निहित हैं, जिनकी हेन्केल को आवश्यकता है, हालांकि हेन्केल ने हाल ही में उसके लिए कोई आर्डर नहीं दिया है। जीएनएफसी के अनुसार टीडीआई प्रकृति से विषैला है और जब प्रयोक्ताओं द्वारा इसका खाद्य अनुप्रयोग करने के लिए इसे एडहेसिव सहित अतिरिक्त रसायनों में विलयन किया जाता है, तो उसका विषैला संघटक निष्प्रभावी हो जाता है और ऐसी विषैली गुणधर्मता जो कि इस उत्पाद की मूल प्रकृति है, के बिना टीडीआई का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की जा सकती है। जीएनएफसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुरोध किया है कि इस प्रकार के उत्पाद के बहिष्करण के फलस्वरूप उसका व्यापक दुरुपयोग होने लगेगा, जिससे लगाए गए शुल्क निष्प्रभावी हो जायेंगे। यह भी नोट किया जाता है कि हेन्केल ने प्रारंभ में फूड सेफ टीडीआई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखे जाने का अनुरोध किया था। लेकिन बाद में अनुरोध को "0.01 एमजी/कि.ग्रा. की विशिष्ट प्रव्रजन सीमा वाले टीडीआई फूड और फूड कंटेक्ट अनुप्रयोग के निमित्त एडहेसिव में प्रयुक्त करने के लिए ईयू पंजीकरण 10/2-011 के अनुसरण में" बदल दिया था। यह नोट किया जाता है कि ऐसे दावों को सिद्ध करने के लिए हेन्केल द्वारा किए गए निवेदन में इस संबंध में रिकार्ड पर कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है और जिनसे प्राधिकारी उनके ऐसे अनुरोधों पर विचार करने में सक्षम हो सकें। निवेदनों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य यह नहीं दर्शाते हैं कि हेन्केल द्वारा किए गए दावे के अनुसार फूड सेफ टीडीआई, घरेलू उद्योग द्वारा तकनीकी और वाणिज्यिक प्राचलों के रूप में उत्पादित और बेचे गए और इस जांच में वर्णित टीडीआई से भिन्न उत्पाद है। तदनुसार, फूड सेफ टीडीआई को बाहर रखने के लिए मेसर्ज हेन्केल एडहेसिव टेक्नोलोजीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

17. मित्सुई केमिकल्स एंड एसकेसी पालीयूरेथेन्स इंक द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इस मामले पर अनन्तिम जांच परिणाम में स्वतः विचार किया गया है, जिसके प्रति उक्त निर्यातक ने कोई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थीं। अनन्तिम जांच परिणाम में व्यक्त किए गए विचार इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भी प्रासंगिक हैं चूंकि मौखिक सुनवाई होने के बाद उन्होंने इसे संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है और उसका नीचे पुनः उल्लेख किया जाता है:-

“एक नियमित अर्थात् मिसुई कैमिकल्स एंड एसकेसी पालीयूरेथेन्स इंक (एमसीएनएस) को छोड़कर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा और दायरे के संदर्भ में कोई अनुरोध नहीं किया है। एमसीएनसी ने प्राधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या दो उत्पादों अर्थात् “टीएम” और “एमटी” को पीयूसी के दायरे में शामिल/उससे बाहर किया गया है अथवा नहीं। एमसीएनएस ने यह अनुरोध किया है कि टीएम 50 प्रतिशत या अधिक टीडीआई और पालीमेरिक एमडीआई (पालीमिथलेनेपालीफिनाइल/पालीआइसोसाइनेट या पीएमडीआई) का मिश्रण है। इसके अलावा, एमटी 50 प्रतिशत से कम टीडीआई और आशोधित मोनोमेरिक एमडीआई, 4.4' - (डिफिनाइल मिथेनआइसोसाइनाइट) का मिश्रण है। एमसीएनएस ने यह भी बताया है कि टीडीआई और टीएम/एमटी के रासायनिक संघटन में काफी अंतर होता है और वास्तव में टीडीआई को प्रयोग टीएम और एमटी की उत्पादन/विनिर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। एमसीएनएस के अनुरोधों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी की परिभाषा और दायरे को जाँच शुरूआत अधिसूचना और पीयूसी से संबंधित अनंतिम जाँच परिणाम में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस प्रकार, यहां उक्त परिभाषा को पूरा करना ही वर्तमान जाँच के दायरे के अधीन आता है और न कि किसी अन्य उत्पाद के लिए।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

18. यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में मेसर्ज गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
19. आवेदक कंपनी ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। इस प्रकार, रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन का समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में ‘प्रमुख हिस्सा’ बनता है; वास्तव में घरेलू उत्पादन में उनका 100 प्रतिशत हिस्सा है।

20. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. यह नोट किया जाता है कि आवेदन जिसके आधार पर वर्तमान पाटन-रोधी जांच शुरू की गई है भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित घरेलू उद्योग के रूप में मेसर्ज गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के दावों के अनुसार मेसर्ज गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक हैं। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में कोई विरोधी अनुरोध नहीं किया है।

22. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। तथापि, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक हैं और वर्तमान जांच के प्रयाजनार्थ नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने का पात्र है।

23. चूंकि आवेदक के उत्पादन का भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा वस्तुतः 10 प्रतिशत हिस्सा बनता है इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है।

घ. गोपनीयता

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्तकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- (1) याचिकादाता ने प्रपत्र-4 “क” में विभिन्न व्यौरों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और कुछ प्राचलों के लिए सूचीबद्ध प्रवृत्ति भी उल्लिखित नहीं की है तथा उनको अनुचित रूप से खंडन किया है जो कि प्रतिवादी के हितों के प्रतिकूल है। प्राधिकारी याचिकादाता की ऐसी सूचना को रोक सकते हैं अथवा एक विकल्प के रूप में उसका एक उपयुक्त अगोपनीय वृत्तान्त याचिकादाता से प्राप्त कर सकते हैं।
- (2) भाग-6 (लागत संबंधी सूचना) की गोपनीयता का दावा किया गया है। प्रपत्र-ख, सी-1 और सी-2, डी और ई में निर्धारित प्राचलों के लिए संपूर्ण गोपनीयता का दावा किया गया है। ऐसे दावे, “स्ट्रेलाईट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (138) ई.एल.टी. 673 (एस.सी.) के मामले में और साथ ही आरआईएल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी {2006 (202) ई.एल.टी. 23 (एससी)} के मामले में लिए गए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है।

- (3) आवेदक उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि वह विधि के प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक सूचना का प्रकटन करे अथवा उसके अगोपनीय वृत्तान्त प्रदान करे, ताकि हितबद्ध पक्षकार अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हो सकें, जो कि वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।
- (4) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के पृथक आंकड़े सॉफ्ट कापी में प्रदान नहीं किए हैं। साथ ही प्रारंभिक जांच परिणाम में भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि किसी पक्षकार ने किसी अन्य विधि के अंतर्गत ऐसे आंकड़ों की गोपनीयता का दावा किया है।

घरेलू उद्योग के विचार

- (1) प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों और आयातों द्वारा काफी अधिक गोपनीयता अपनायी गई है। ईक्यू उत्तरों और आईक्यू उत्तरों के एनसीवी अंश से पाटन और ऐसे प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा देश में किए गए आयातों के संदर्भ में ऐसे पक्षकारों के दावों की तर्कसंगत समझ नहीं बनती है।
- (2) दस्तावेजों के एनसीवी अंश को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग उनका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है।
- (3) क्रमशः उत्पादक/निर्यातक/आयातक द्वारा दी गई इस मूल सूचना की गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है:
 - (क) संबद्ध देशों से निर्यातों/आयातों की कुल मात्रा संबंधी सूचना।
 - (ख) संबद्ध देशों से आयातों की औसत कीमत।
 - (ग) धारक कंपनी का ब्यौरा और निर्यातक/व्यापारी द्वारा उत्तर दिए जाने पर संबंधित उत्पादकों का नाम वास्तव में, किसी भी भागीदार निर्यातक/व्यापारी ने ऐसे संबंधित उत्पादकों के नाम नहीं बताये हैं जिनके उत्पाद को ऐसे पक्षकारों ने निर्यात किया है।
- (4) जबकि नियमावली में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्ष के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तथापि प्रतिवादी पक्षकारों ने उनके लिए सुविधाजनक ढंग से उपयोग किया है और वस्तुतः उनके द्वारा पाटित आयातों के संबंध में याचिकाकर्ता को वास्तविक स्थिति जानने से अवरूद्ध किया है। प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता यूरोपीय संघ – चीन से कतिपय आयरन या स्टील फास्टेनर संबंधी पाटन-रोधी उपायों (डब्लूटी/डीएस 397/एबी/आर दिनांक 15 जुलाई, 2011) में अपीलीय निकाय के निष्कर्षों का उल्लंघन है जिसमें अपीलीय निकाय ने गोपनीयता से संबंधित पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 6.5 और 6.5.1 की व्याख्या की है।
- (5) याचिकादाता ने पर्याप्त कारणों का उल्लेख करके कुछ व्यवसाय की संवेदी सूचना की गोपनीयता का दावा किया है। जिस सूचना की गोपनीयता का दावा किया गया है, जहां कहीं भी संभव हुआ है, उसका एक संक्षिप्त सूचीबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में प्रतिवादियों ने अत्यधिक गोपनीयता बना कर रखी हुई है और घरेलू उद्योग को उनके आंकड़ों का कोई सार्थक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए जीएनएफसी ने मात्रा के प्राचलों के बारे में समस्त सूचना प्रदान की है, लेकिन निर्यातकों और आयातकों ने अपने एनसीवी के प्रत्युत्तर में कोई मात्रा संबंधी सूचना का प्रकटन नहीं किया है, जहां तक कि उसका कोई संक्षिप्त विवरण/सीमा प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाना चाहिए कि जिस पर विश्वास किया गया है, ऐसे डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण भी सार्वजनिक फाईल पर उपलब्ध है, जो कि ऐसे सभी कारोबार पर स्वतः स्पष्ट हैं, जिन पर विचाराधीन उत्पाद और अन्य आदि पर विचार किया गया है।
- (6) याचिका में कमियां होने के तर्क भी निराधार हैं और इनका कोई कानूनी अथवा वास्तविक आधार नहीं है और सभी तर्कों को उनमें कोई योग्यता नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। नियम में ऐसा कुछ भी निहित नहीं है, जो यह कहता हो कि प्रपत्र-4 “क” का प्रकटन सभी हितबद्धकारों के समक्ष किया जाए। यह भी नोट किए जाने की आवश्यकता है कि कंपनी के वित्तीय विवरण और तुलन-पत्र प्रदान किए गए हैं और उत्पाद-वार कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसा कि कुछ पक्षकारों ने मांग की है, क्योंकि उसे बना कर नहीं रखा जाता है और न ही सांविधिक रूप से उसकी आवश्यकता है और ऐसे दावे की कोई योग्यता नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. गोपनीयता के बारे में प्रतिवादी पक्षकारों और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियम (7), (2), नियम 12 के उपनियम (2) (3), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां आवश्यक हो स्वीकार किया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है।

27. जहां कहीं संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निदेश दिया गया। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों का एक सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रखा। इस अंतिम जांच परिणाम में विभिन्न चर्चाएं गोपनीयता के पहलू के संबंध में घरेलू उद्योग की अन्य दलीलों के संबंध में स्वतः-स्पष्ट हैं।

28. डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में किए गए निवेदनों के बारे में यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात संबंधी सूचना के ब्यौरे, जिस पर विश्वास किया गया है, अनन्तिम जांच परिणाम और साथ ही अंतिम जांच परिणाम दोनों में उपलब्ध कराए गए हैं।

इ. विविध मुद्दे

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्तकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- (1) वर्तमान जांच को शुरू करना विधि में अमान्य है और इसलिए इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि जांच शुरू करने को वैध भी माना जाता है, तो भी पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति और कारणात्मक संबंध की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं।
- (2) याचिका में गंभीर कमियां हैं, जो कि जांच को समाप्त कर दिए जाने के लिए पर्याप्त हैं।
- (3) पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से पहले जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि कोई शुल्क लगाना है, तो वह कीमत के आधार के संदर्भ में होना चाहिए।
- (4) याचिकादाता की विशिष्ट तथ्य परक स्थिति और चुनिन्दा जांच अवधि, वर्तमान मामले में पाटन और क्षति की जांच करते समय ऐसे तर्कों पर विचार करने का अधिदेश देती है। जांच अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 याचिकादाता के लिए विशिष्ट और असामान्य अवधि होती है। वर्ष 2014 में बाजार में उतार-चढ़ाव और परिवर्तन होने के कारण याचिकादाता के आर्थिक प्राचलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहां तक कि याचिकादाता के उत्पादन की सामान्य लागत और क्षति रहित कीमत को भी इन तर्कों में शामिल किया जाना चाहिए।
- (5) कंपनी और संबंधित विशिष्ट उत्पाद के संबद्ध वर्ष के तुलन-पत्र और वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं।
- (6) यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा कैसे विचाराधीन उत्पाद और अन्य के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का पृथक्कीकरण और आयात के अपरिष्कृत आंकड़ों की छंटाई की गई है। प्राधिकारी को संपूर्ण कारोबार-वार आयात के आंकड़ों के साथ-साथ छंटाई किए गए आयात के आंकड़े एमएस-एक्सिस फार्मेट में प्रदान करने चाहिए।
- (7) अनन्तिम शुल्क की सिफारिश, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” के बतौर उल्लिखित किया गया है) की धारा 9 ख और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 12 की विशिष्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं है। इस प्रकार प्रारंभिक जांच परिणाम, न्याय-व्यवस्था रहित, गैर-कानूनी, मनमाने और अनुचित हैं तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की स्पष्ट अवहेलना है।

- (8) प्रारंभिक जांच परिणाम लागू करने के लिए पहली शर्त, जांच अवधि के दौरान पाटन, क्षति (आर्थिक क्षति) और कारणात्मक संबंध के बारे में है और दूसरी पूर्व शर्त, जांच की कार्रवाई के दौरान क्षति के संबंध में है, जो कि परिभाषा द्वारा जांच अवधि से परवर्ती है। वर्तमान मामले में प्राधिकारी, अपने प्रारंभिक जांच परिणामों की सिफारिश करते समय ऐसे किसी भी कारक को दर्ज करने में विफल रहे हैं, जिसे “जांच की कार्रवाई के दौरान” “आगे” निर्धारण करना माना जा सकता है, जो कि अनिवार्य आवश्यकता है।
- (9) घरेलू उद्योग विधि में प्रदत्त किसी भी प्राचल में अपनी क्षति के मामले को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं रहा है और इसलिए वह विधि की अपेक्षा के अनुसार अपने मामले को सिद्ध करने में बुरी तरह से विफल रहा है।
- (10) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है और शुल्क लागू करने से आरोपित पाटन के प्रभावों को निष्फल करने के बजाय व्यापार में असंतुलन पैदा होगा।
- (11) घरेलू उद्योग पर्याप्त भारतीय मांग (कोई शुल्क लागू किए बिना) को पूरा कर रहा है और जांच पश्चात अवधि में विश्वभर में टीडीआई की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- (12) घरेलू उद्योग के उत्पादन सुविधाएं अविश्वसनीय हैं और उनके निरंतर बंद होने की संभावना है।
- (13) याचिकादाता की 50,000 मी.टन की नई क्षमताओं, जिसकी प्रचालनात्मक कठिनाई को उसने स्वीकार किया है, के आलोक में प्राधिकारी को इस पर विचार करना चाहिए कि शुल्क कमतर और सीमित अवधि के लिए लागू किया जाए, ताकि याचिकादाता की क्षमताओं को स्थापित होने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो जाए। उचित सीमा से अधिक किसी भी शुल्क को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।
- (14) जापान के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग करने के कारण जापान पर अधिक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
- (15) पाटन-रोधी शुल्क एकाधिकार स्थापित करने का एक प्रयास है।

घरेलू उद्योग के विचार

- (1) आयातकों/प्रयोक्ताओं नामतः मेसर्स इंडियन पोलीरिथीन एसोसिएशन (अल्पांश आईपीए) और मेसर्स हेन्केल एडहेसिव्स टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने बहुत विलंबित चरण में वर्तमान जांच में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी। सार्वजनिक फाईल से पता चलता है कि आईपीए ने पहली बार 4 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक जांच परिणाम पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं और हेन्केल ने 2 मई, 2017 को उत्तर दिया था, जो कि जांच शुरू होने की तारीख 5.10.2016 से लगभग 6 माह बाद है। ऐसा विलंब तब हुआ है, जबकि जांच शुरू करने की अधिसूचना में प्रश्नावली के उत्तरों सहित किसी भी प्रकार का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट रूप से समय निर्धारित किया गया है।
- (2) प्रत्युत्तर देने की अंतिम तारीख, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार तय की गई थी और उक्त नियम जांच में शामिल सभी “हितबद्ध पक्षकारों” पर लागू होता है तथा हितबद्ध पक्षकारों की परिभाषा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 में दी गई है। जो पक्षकार “हितबद्ध पक्षकारों” की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी विशिष्ट पाटन-रोधी जांच में कोई भूमिका नहीं है।
- (3) आईपीए ने निवेदन किया है कि आईपीए जैसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसकी अपनी इच्छा से जांच में किसी भी समय शामिल होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा दावा सही नहीं है और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के प्रावधान किसी जांच में शामिल सभी “हितबद्ध पक्षकारों” पर लागू होते हैं और ऐसा कोई भी पक्षकार जो जांच शुरू होने पर उत्तर देने की समय सीमा के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है, उसे किसी भी स्थिति में एक हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है और उसके किसी भी प्रकार के निवेदनों को रिकार्ड में नहीं लिया जा सकता है।
- (4) जैसा कि नियम में व्यवस्था की गई है, आईपीआई द्वारा 4 अप्रैल, 2017 को किए गए निवेदन, संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं की एसोसिएशन के रूप में उनके प्रत्यायकों को सिद्ध नहीं करते हैं। आईपीए कोई पंजीकरण प्रमाण-पत्र, एमओए अथवा एओए, अपने सदस्यों की सूची और अपने सदस्यों द्वारा आयात प्रश्नावली के उत्तर आदि प्रस्तुत करने विफल रही है, जिससे प्राधिकारी को विलंब से उत्तर देने में विलंब के अतिरिक्त एसोसिएशन के प्रत्यायक भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। केवल इसी तथ्य के आधार पर आईपीए को नियमावली के अंतर्गत वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्हें असहयोगी पक्षकार घोषित कर दिया जाना चाहिए।
- (5) हेन्केल ने भी आयातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। आयातक की प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिए जाने पर हेन्केल के प्रत्यायक और साथ ही संबद्ध वस्तुओं के उनके आयात के व्यौरों की भी जांच की जा सकती है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ केवल इस आधार पर हेन्केल को एक सहयोगी आयातक अथवा हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जाना चाहिए।

- (6) भारत में जनहित पर निर्यातकों के निवेदनों को प्रत्यक्ष मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है। प्राधिकारी ने ऐसे निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के मामले में भी अत्यधिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पाया है। ऐसे पक्षकार ऐसे सभी तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे उन पर लगने वाले पाटन-रोधी शुल्क से बच सकें, जो कि अन्यथा उन पर अब लागू होने वाला है। लगभग 22% भारतीय मांग को पूरा करने से घरेलू उद्योग को लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है क्योंकि पाटित आयातों के कारण कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है और कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है।
- (7) जांच पश्चात अवधि में वैश्विक कीमतों में वृद्धि होने का कोई भी दावा और साथ ही जांच पश्चात अवधि में घरेलू स्थिति अप्रासंगिक है और यह बेहतर होगा कि ऐसे परिवर्तन को समीक्षा का मामला समझा जाए। जन हित के परिप्रेक्ष्य में यह भी निराधार तर्क है कि घरेलू उद्योग के संयंत्र के बंद होने की संभावना बनी रहती है और यह विश्वसनीय नहीं है। जीएनएफसी को टीडीआई का उत्पादन करने का दशकों का अनुभव प्राप्त है और उसका नया संयंत्र भी सभी स्थिरता के साथ चल रहा है। भारतीय प्रयोक्ता टीडीआई के लिए जीएनएफसी पर विश्वास कर सकते हैं।
- (8) कुछ पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि अंतिम जांच परिणाम प्रकाशित करने से पहले जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों पर भी विचार किया जाए। यह निवेदन है कि नई जांच के परिप्रेक्ष्य में जांच अवधि पश्चात आंकड़ों की कोई प्रासंगिकता नहीं है और ऐसे दावे की कोई कानूनी पवित्रता नहीं है। यह बेहतर होगा कि जांच पश्चात अवधि में कोई भी परिवर्तन नियम 23 के अंतर्गत मध्यावधि समीक्षा की विषय वस्तु हो सकता है और नियम 17 और 18 के प्रयोजनार्थ इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी के समक्ष यह निर्णीत मुद्दा है और विगत में अनेक जांच में प्राधिकारी द्वारा इस मुद्दे पर इसी प्रकार से विचार किया गया है।
- (9) अनन्तिम शुल्कों के खिलाफ प्रतिवादी पक्षकारों के तर्क सही नहीं हैं। अनन्तिम शुल्कों को अनिवार्य पाया गया था और प्राधिकारी द्वारा उनकी सिफारिश की गई थी तथा केन्द्रीय सरकार ने उनको लागू किया है। अनन्तिम जांच परिणाम ने वर्तमान मामले के तथ्यों को और आगे जांच होने तक अनन्तिम शुल्क लागू करना क्यों आवश्यक था, व्यापक रूप से प्रतिपादित किया था। प्रारंभिक जांच परिणाम में यह निहित है कि उपयुक्त स्थानों पर “आगे” निर्धारण किया जाए और अंतिम जांच परिणाम के समय प्रारंभिक जांच परिणाम की संपुष्टि करना आवश्यक है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

29. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन निर्धारण करने की कार्य-प्रणालियों और घरेलू उद्योग के क्षति के दावों सहित वर्तमान जांच के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं। जबकि पाटन और क्षति निर्धारण करने संबंधी मुद्दों का समाधान इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर किया गया है, जांच पर पक्षकारों द्वारा उठाए गए सामान्य मुद्दों की जांच और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है:-

- (1) इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच को शुरू करना विधि में अमान्य है और इसलिए इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति और कारणात्मक संबंध की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम में की गई व्यवस्था के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने की संपुष्टि करने वाले प्रथम दृष्टया प्रमाणों पर मामले की जांच शुरू की गई थी। इस जांच परिणाम में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के ब्यौरे दिए गए हैं, जो कि स्वतः स्पष्ट हैं। इस प्रकार ऐसे दावे अप्रमाणिक और योग्यता विहीन हैं।
- (2) इस तर्क के संबंध में कि याचिका में ऐसी गंभीर कमियां हैं, जो कि जांच को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं, यह नोट किया जाता है कि याचिका में दावों को सिद्ध करने वाले समस्त प्रासंगिक ऐसे तथ्य निहित हैं, जिनके आधार पर जांच शुरू की गई थी और जहां कहीं भी आवश्यक था, याचिकादाता से और ब्यौरे मांगे गए थे। इस प्रकार ऐसे दावे अप्रमाणिक और योग्यता विहीन हैं।
- (3) इस तर्क के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से पहले जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि कोई शुल्क लगाना है, तो वह कीमत के आधार के संदर्भ में होना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को, पाटन और क्षति का निर्धारण करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत जांच शुरू करने के समय केवल जांच अवधि और विगत तीन वर्षों के आंकड़ों की जांच करनी आवश्यक होती है। संदर्भ कीमत शुल्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि शुल्क के ऐसे रूप को अपनाया जाता है, जो कि शुल्क के परिकल्पित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होता है।
- (4) इस तर्क के संबंध में कि याचिकादाता की विशिष्ट तथ्य परक स्थिति और चुनिन्दा जांच अवधि, वर्तमान मामले में पाटन और क्षति की जांच करते समय ऐसे तर्क पर विचार करने का अधिदेश देती है, यह नोट किया जाता है कि चुनी गई जांच अवधि हाल

- ही की और उचित अवधि है, जो कि पाटन-रोधी नियमावली में परिकल्पित विभिन्न प्राचलों की जांच करने के लिए उपयुक्त अवधि है और क्षति रहित कीमत का निर्धारण भी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।
- (5) इस तर्क के संबंध में कि कंपनी और संबंधित विशिष्ट उत्पाद के संबंध वर्ष के तुलन-पत्र और वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं, यह नोट किया जाता है कि इस संबंध में याचिकादाता द्वारा तैयार की गई प्रासंगिक सूचना प्रदान की गई है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध है।
 - (6) विचाराधीन उत्पाद और अन्य के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के पृथक्कीकरण के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों को पृथक् किया गया था और विचाराधीन उत्पाद के लिए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है, जो कि अंतिम जांच परिणाम का आधार बना है।
 - (7) अनन्तिम शुल्क की सिफारिश, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” के बतौर उल्लिखित किया गया है) की धारा 9 ख और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 12 की विशिष्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं है। इस प्रकार प्रारंभिक जांच परिणाम, न्याय-व्यवस्था रहित, गैर-कानूनी, मनमाने और अनुचित हैं तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की स्पष्ट अवहेलना है, यह नोट किया जाता है कि अनन्तिम जांच परिणाम, कानूनी और तथ्यपरक पृष्ठ भूमि को स्पष्ट करता है, जिसके फलस्वरूप आगे जांच होने तक अनन्तिम शुल्कों के लिए सिफारिश की गई है।
 - (8) इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी “आगे” निर्धारण करने के साथ अनन्तिम जांच परिणाम को अधिसूचित करते समय उसकी आवश्यकताओं को समझने में विफल रहे हैं, यह नोट किया जाता है कि कानूनी आवश्यकताओं के समनुरूप अनन्तिम जांच परिणाम की सिफारिश की गई थी और यह उपयुक्त पाया गया था कि पाटन, क्षति और उनके कारणात्मक संबंध से संबंधित तथ्यों की अनन्तिम रूप से जांच करने के बाद अंतरिम उपाय की सिफारिश करना उपयुक्त था। अनन्तिम जांच परिणाम से अनन्तिम उपायों की सिफारिश करने के लिए आवश्यक संघटकों के विद्यमान होने का पता चलता है।
 - (9) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग विधि में प्रदत्त किसी भी प्राचल में अपनी क्षति के मामले को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं रहा है और इसलिए वह विधि की अपेक्षा के अनुसार अपने मामले को सिद्ध करने में बुरी तरह से विफल रहा है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच परिणाम स्वतः स्पष्ट हैं चूंकि इसमें सभी संबंध क्षति प्राचलों का उल्लेख किया गया है।
 - (10) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है और शुल्क लागू करने से आरोपित पाटन के प्रभावों को निष्फल करने के बजाय व्यापार में असंतुलन पैदा होगा, यह नोट किया जाता है कि ।
 - (11) इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग पर्याप्त भारतीय मांग (कोई शुल्क लागू किए बिना) को पूरा कर रहा है और जांच पश्चात अवधि में विश्वभर में टीडीआई की कीमतों में वृद्धि हुई है, यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान निर्धारित किया गया पाटन और परिणामी क्षति, वर्तमान जांच का विषय है।
 - (12) इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग के उत्पादन सुविधाएं अविश्वसनीय हैं और उनके निरंतर बंद होने की संभावना है, यह नोट किया जाता है कि अनेक वर्षों से याचिकादाता टीडीआई का उत्पादन कर रहा है और उसने कुछ वर्ष पहले अपनी क्षमता का विस्तार किया है और वह एक नियमित उत्पादक के रूप में अपने सुविधा केन्द्रों से संबंध वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है।
 - (13) इस निवेदन के संबंध में कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुल्क कमतर और सीमित अवधि के लिए लागू किया जाए, अपेक्षित शुल्क की मात्रा पर प्राधिकारी का विचार और उसकी अवधि, इस जांच के समस्त प्रासंगिक तथ्यों और नियम में क्या व्यवस्था है, पर विचार करने के बाद इस जांच परिणाम के अंतिम भाग में उल्लिखित की गई है जो कि स्वतःस्पष्ट है।
 - (14) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के तर्कों के आमने-सामने मेसर्स इंडियन पोलीरिथीन एसोसिएशन (अलपांश आईपीए) और मेसर्स हेन्केल एडहेसिव्स टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के जांच शुरू होने की तारीख से अत्यधिक समय बीत जाने के बाद वर्तमान जांच में विलंब से भाग लेने की इच्छा प्रकट करने पर भी विचार किया है। यह नोट किया जाता है कि इस चरण में उक्त पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने से वर्तमान जांच में किसी भी प्रकार से कोई अडचन नहीं आ सकती है और इसी आधार पर उक्त पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान, इस जांच परिणाम में किया गया है।

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

30. वर्तमान जांच दिनांक 5.10.2016 को शुरू की गई और वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयाजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने का विकल्प खुला था। पाटन-रोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन (वर्तमान मामले में) का (के) निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके

प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- (ग) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

31. यह नोट किया जाता है कि चीन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक, जिसने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, ने ईक्यू उत्तर और एमईटी उत्तर प्रस्तुत करके वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, चीन जनवादी गणराज्य के विरुद्ध एनएमई की धारणा का चीन के उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में खंडन नहीं किया है।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्तकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- (1) पृथक विशिष्ट मार्जिन, हानवा केमिकल कार्पोरेशन के नाम पर स्वीकृत किया जाना चाहिए और न कि हानवा फाईन केमिकल कार्पोरेशन के नाम पर, जो कि एक कानूनी प्रयोज्यता के रूप में अब अस्तित्व में नहीं है।
- (2) इस तथ्य के बावजूद कि स्वतः जांच अवधि के भीतर हानवा फाईन केमिकल कार्पोरेशन के हानवा केमिकल कार्पोरेशन में समामेलित होने के बारे में समर्थक दस्तावेजों के साथ उचित समय पर उसका प्रकटन कर दिया गया था, हानवा केमिकल कार्पोरेशन के बजाए एक कानूनी निर्यातक के रूप में हानवा फाईन केमिकल कार्पोरेशन पर विचार करते हुए प्रारंभिक अनन्तिम शुल्क अधिसूचित किए गए थे, जो कि एक कानूनी प्रयोज्यता के रूप में अब अस्तित्व में नहीं है।
- (3) कोरिया में कंपनी के समामेलित होने के अनुबंध के साथ-साथ अंग्रेजी में अनूदित प्रतिलिपि, कोरिया के वाणिज्यिक अधिनियम के संबद्ध उद्धरण, जिसके अंतर्गत एचएफसीसी को एचसीसी में समामेलित किया गया था, हानवा केमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) की वर्ष 2016 के लिए लेखा-परीक्षित रिपोर्ट, 31.12.2015 तक की स्थिति के अनुसार एचसीसी के शेयरधारकों की सूचना, जांच पश्चात अवधि में भारत को निर्यात के व्यौरे, जैसे साक्ष्य प्रदान किए गए थे।
- (4) हानवा संबंधित पक्षकार से कोई इनपुट प्राप्त नहीं करती है। हानवा संबंधित पक्षकार से केवल स्टीम प्राप्त करती है, जो कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की कुल लागत का मात्र 0.01% भाग होती है।
- (5) प्रारंभिक जांच परिणाम के समय सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए हानवा की उत्पादन लागत पर इस कारणवश विचार नहीं किया गया था कि प्रत्युत्तर में टीडीए और सीडीसी जैसे मध्यवर्ती पदार्थों के विनिर्माण की लागत प्रदान नहीं की गई थी। वर्तमान परिदृश्य में हानवा ने सत्यापन के समय संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के दौरान टीडीए और सीडीसी की वस्तुओं की लागत प्रदान की है, जिसमें मूल कच्चे माल की लागत शामिल है। बाद में प्राधिकारी के विशिष्ट प्रश्नों पर अतिरिक्त दस्तावेज भी प्रदान किए गए थे। उसके बाद संबद्ध वस्तुओं की चरण-वार लागत पत्र की भी मांग की गई थी और वह भी औचित्य के साथ प्रदान कर दिया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया गया था कि हानवा द्वारा प्रदत्त सत्यापित सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारित किया जाए और न कि श्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर, जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में किया गया है।
- (6) हानवा ने चार विभिन्न व्यापारिक माध्यमों से निर्यात किए हैं, जिनका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा स्थल पर जांच के दौरान कर दिया गया था। इनमें से निर्यात के चार कारोबार दुबई के ताज अल मुलुक द्वारा भारतीय ग्राहक के साथ किए गए थे। उसके बाद भारतीय ग्राहक ने ऐसी सभी संबद्ध वस्तुओं को भारतीय सीमा-शुल्क विभाग में प्रविष्ट किए बिना अन्य देशों को भेज दिया था।

चूंकि इन वस्तुओं का उपयोग भारत में नहीं किया गया है, हानवा का अनुरोध है कि पाटन-रोधी शुल्क के परिकलन के प्रयोजनार्थ ऐसी वस्तुओं का बहिष्करण जाए।

- (7) कोरिया सरकार का निवेदन है कि सभी अधिसूचनाओं में एचएफसी के बजाए एचसीसी के नाम को प्रयुक्त किया जाए। कोरिया सरकार ने यह भी निवेदन किया है कि एचसीसी द्वारा प्रस्तुत सूचना को विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार के अनुबंध-2 के पैरा 2 के अनुसार सभी परिकलनों के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाए। साथ ही कोरिया सरकार ने यह भी निवेदन किया है कि टीडीआई पर कोई भी शुल्क भारत में टीडीआई प्रयोक्ताओं को प्रभावित करेगा और अनुरोध किया है कि कोई पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जाए।
- (8) वर्तमान जांच में चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, उनकी घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर इस तथ्य को ध्यान में रख कर किया जा सकता है कि चीन के उत्पादकों की घरेलू कीमतों अथवा लागतों की 15 वर्षों तक अनदेखी की गई है क्योंकि वे बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों को पूरा नहीं करते थे, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन के साथ चीन जनवादी गणराज्य के अधिगमन नयाचार के पैरा 15 (क) (2) में प्रावधान किया गया है, जो कि पैरा 15 (घ) के अनुसार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है और इस समय वह प्रचालन में नहीं है। चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त कोई भी अन्य कार्य-प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत के दायित्व का उल्लंघन होगी।

घरेलू उद्योग के विचार

- (क) चीन जनवादी गणराज्य को वर्तमान जांच के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य पैरा 7 अनुबंध के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (ख) चीन के उत्पादकों को भारतीय प्राधिकारी और ईयू, यूएसए, आस्ट्रेलिया आदि जैसे अन्य देशों द्वारा हाल में समाप्त जांचों सहित अनेक जांचों में एमईटी दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि चीन जन. गण को विभिन्न पाटन-रोधी जांच में गैर बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) माना गया है।
- (ग) एमईटी का दर्जा प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा एमईटी की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही दिया जाना चाहिए अन्यथा नहीं। इस प्रकार पाटन-रोधी नियम के अनुबंध के पैरा 8(3) की अपेक्षाओं को एमईटी दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से पूरा करना होगा।
- (घ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस इस्थिति में नहीं दिया जा सकता है जबकि एक प्रमुख शेयरधारक राज्य स्वामित्व/नियंत्रित कंपनी है।
- (ङ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक यह सिद्ध न करें कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें बाजार मूल्य दर्शाती हैं। यह शब्द कि 'बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाना' की व्यापक रूप से इस अर्थ में व्याख्या की गई है कि इन निविष्टियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए। यह तथ्य कि ऐसी कीमतें चीन में प्रचलित कीमतों से तुलनीय है बिल्कुल सही नहीं है।
- (च) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि उनकी बहियों की लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार की जाती है। बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को ऐसी स्थिति में अस्वीकार किया जाए जबकि चीन के निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर सके हैं कि उनकी बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएस) से संगत हैं।
- (छ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक नियामों के अधीन प्रत्येक निर्धारित मापदंड को पूरा करने के परीक्षण को पास न कर लें।
- (ज) यह दायित्व चीन के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों का है कि वे सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशा में काम कर रहे हैं और पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
- (झ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से यह दावा करें। यदि समूह बनाने वाली एक यह अधिक कंपनी ने उत्तर नहीं दिया तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जे को इस तथ्य कि समूह की अन्य कंपनियों जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में शामिल हैं, ने उत्तर प्रस्तुत किया है, पर विचार किए बिना, अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- (ञ) ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं अपितु उसे किसी अन्य पक्ष से अधिग्रहीत किया है बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध हो।

- (ट) वर्तमान जांच में ऐसा कोई सहयोगी उत्पादक/निर्यातक नहीं है जिसने एमईटी प्रश्नावली के अनुसार समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करके एनएमई दर्जे की धारणा का खंडन किया हो चीन जन गण को केवल इसी तथ्य के आधार पर गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए।
- (ठ) आवेदक ने पाटन-रोधी नियम और नियम के संगत अनुबंध में विनिर्दिष्ट विधि से उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को प्रस्तुत किया है। ऐसी गणनाओं का ब्यौरा एनसीवी आवेदन में दिया गया है जो विस्तृत है और सभी अनिवार्य विनिर्देशनों वाला है। यदि संबंधित उत्पादक/निर्यातक सार्थक रूप से सहयोग न करें तो प्राधिकारी इस जांच के प्रयोजनार्थ सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना पर भरोसा कर सकते हैं।
- (ड) चीन एक्सेसन संधि के उपबंधों के वर्तमान मामले में कोई निहितार्थ नहीं है क्योंकि वर्तमान मामला 5.10.2016 को शुरू हुआ है और चुनी गई पीओआई अप्रैल 2015 – मार्च 2016 तक है।
- (ढ) एचएफसीसी द्वारा दायर किए गए ईक्यू उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह कंपनी अर्थात् हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन (एचएफसीसी) 29 फरवरी, 2016 को हानवा कैमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) के व्यवसाय प्रभाग में समामेलित हो गई है। तथापि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर एचएफसीसी को किसी विधिक या वास्तविक औचित्य के बिना कंपनी के रूप में ब्योरे प्रदान करके दायर किया गया है।
- (ण) पूरे निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर एचसीसी को तथ्य देने वाली कंपनी और न कि एचएफसीसी को मानते हुए दिया जाना चाहिए था जिसका अस्तित्व 29 फरवरी 2016 को समाप्त हो गया। इस परिदृश्य में, प्राधिकारी को एचएफसीसी के पूरे उत्तर को गलत और अधूरा मानना चाहिए और इसकी कोई विधिक साध्यता नहीं है।
- (त) सभी प्रश्नों का उत्तर एचएफसीसी को संगत कंपनी मानते हुए दिया गया है। उदाहरण के लिए एचएफसीसी के शेयर धारकों की सूची, शामिल कारखानों की सूची आदि दी गई है जबकि तथ्यों के अनुसार संगत यह है कि प्रकट तथ्य एचसीसी न कि एचएफसीसी जिसका अस्तित्व 29 फरवरी 2016 को समाप्त हो गया, द्वारा कंपनी के रूप में प्रश्नों के उत्तर हैं, जो पीओआई के बिल्कुल भीतर हैं। प्रदत्त गलत और अनुचित उत्तरों को इस समय नहीं सुधारा जा सकता है और उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- (थ) यह नोट किया जा सकता है कि एचसीसी का कोई भी उत्तर एचएफसीसी के किसी उत्तर से बिल्कुल अलग होगा और एचसीसी के बजाय एचएफसीसी द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर से प्राधिकारी को पाटन की किसी जांच में मदद नहीं मिलेगी। एचएफसीसी का अस्तित्व 29 फरवरी 2016 को समाप्त हो गया और ऐसी स्थिति में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देने वाली संगत कंपनी एचसीसी है और एचसीसी ने इस आशय का कोई निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं प्रस्तुत किया है।
- (द) निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर में पूरे प्रश्नों का उत्तर एचसीसी को देना चाहिए था और एचएफसीसी के बजाय एचसीसी को ही अलग मार्जिन की मांग करनी चाहिए। इस प्रकार, यदि एचएफसीसी को अलग मार्जिन दिया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि एचएफसीसी अस्तित्व में नहीं है।
- (ध) एनसीवी उत्तर में एचसीसी ने अनुरोध किया है कि भारत को पीयूसी के निर्यात में एक श्रृंखला शामिल है तथापि उस निर्यातक का नाम नहीं बताया गया है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस शामिल निर्यातक ने निर्यातक उत्तर प्रस्तुत किया है।
- (न) एचसीसी ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है और श्रृंखला के निर्यातक का नाम नहीं बताया है। निर्यातक का नाम कैसे गोपनीय हो सकता है? क्या यदि अलग मार्जिन दिया भी जाता है तो प्राधिकारी किसी निर्यातक के नाम को गोपनीय मान सकते हैं? इस प्रकार मूल सूचना को गोपनीय रखना गोपनीयता के उपबंधों का घोर उल्लंघन है और गोपनीयता का ऐसा दावा बिल्कुल गलत है जिसे प्राधिकारी को अस्वीकार करना चाहिए।
- (प) टीजे एएल मुलूक द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर से यह स्पष्ट है कि टीजे एएल मुलूक संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को टीजे एएल मुलूक द्वारा निर्यात किया गया?
- (फ) संगत उत्पादक द्वारा पूरे निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर के रूप में सहयोग के बिना टीजे एएल मुलूक के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- (ब) पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर से यह स्पष्ट है कि पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. द्वारा निर्यात किया गया?
- (भ) संगत उत्पादक द्वारा पूरे निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर के रूप में सहयोग के बिना पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

- (म) आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर से यह स्पष्ट है कि आईएमएस कार्पोरेशन संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा निर्यात किया गया?
- (य) संगत उत्पादक द्वारा पूरे निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर के रूप में सहयोग के बिना आईएमएस कार्पोरेशन के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- (र) एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर से यह स्पष्ट है कि एवरलाइट कोरिया कं. लि. संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को एवरलाइट कोरिया कं. लि. द्वारा निर्यात किया गया?
- (ल) संगत उत्पादक द्वारा पूरे निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर के रूप में सहयोग के बिना एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- (व) निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर, पृथक विशिष्ट मार्जिन निर्धारित करते समय प्रकृति से बाध्यकारी हैं। हानवा फाईन केमिकल कार्पोरेशन (एचएफसीसी) ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और न कि हानवा केमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) ने। इस प्रकार एचसीसी को पृथक विशिष्ट मार्जिन स्वीकृत करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। नियम 17 (3) में यह प्रावधान है कि “निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच अधीन वस्तु के संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए पाटन का एक पृथक विशिष्ट मार्जिन निर्धारित करेंगे” और प्रस्तुत किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में संबंधित ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक एचएफसीसी है और न कि एचसीसी।
- (श) मुद्दा मात्र एचएफसीसी का एचसीसी में समामेलित होने की सत्यता का नहीं है, जैसा कि यह आज इस समय है। यदि निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर एचसीसी ने दिए होते, तो यह प्राधिकारी के लिए आवश्यक होता कि वे समामलेन की सत्यता की जांच करें। लेकिन चूंकि निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर एचएफसीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि ऐसा प्रयोज्यता है, जो 29 फरवरी, 2017 से अस्तित्व में नहीं है और न कि एचसीसी द्वारा, निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर स्वतः निष्फल हैं और योग्यता पर कोई जांच नहीं की जा सकती है।
- (स) यह स्वीकार्य तथ्य है कि हानवा ने केवल सत्यापन के समय पर केप्टिवली उत्पादित इनपुट की लागत प्रदान की है, जिसमें ऐसे मूल कच्चे माल की लागत शामिल है, जिसका उपयोग टीडीए और सीडीसी, जैसे कि डीएनटी, एच2, क्लोरीन आदि का विनिर्माण करने के लिए किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने के समय पर प्रस्तुत किया गया उत्तर अधूरा है और केवल इस आधार पर उत्तर को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।
- (ह) हानवा ने यह दावा किया है कि भारतीय ग्राहक ने भारतीय सीमा-शुल्क विभाग में प्रविष्टि किए बिना ताज के माध्यम से सभी ऐसी वस्तुओं को अन्य देशों को भेज दिया है और ऐसी वस्तुओं का उपयोग भारत में नहीं किया गया है। हानवा का समग्र दावा प्रमाणित नहीं है और हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे निर्यातों को बहिष्कृत करने के लिए प्रत्यक्ष मूल्य पर हानवा के अनुरोध को स्वीकार नहीं करें। हानवा जो कि कोरिया में एक उत्पादक है, यह दावा कर रहा है कि ताज के माध्यम से निर्यातित सामग्री को भारतीय ग्राहक द्वारा अन्य देशों को भेज दिया है। लेकिन न तो ताज और न ही संबंधित भारतीय ग्राहक ने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वास्तव में भारत में संबद्ध वस्तुओं के एक निर्यातक के रूप में ताज ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और उसमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि सामग्री भारतीय खपत के लिए नहीं भेजी गई थी। ताज द्वारा निर्यातित वस्तुएं पाटित स्तर पर थीं और उसने अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है और ऐसे निर्यातों को मार्जिन का परिकलन के प्रयोजनार्थ बाहर नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि हानवा ने अनुरोध किया है।
- (क्ष) हानवा द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को खारिज किया जा सकता है और हानवा के लिए उसके उत्तर के आधार पर कोई पृथक विशिष्ट मार्जिन निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, जो कि विकट रूप से अपूर्ण और गलत है।
- (त्र) यह कहने का कोई आधार नहीं है कि चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जनवादी गणराज्य की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, जिसने वर्तमान मामले में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इसलिए सामान्य मूल्य (एनवी) बेहतर उपलब्ध सूचना पर आधारित होना चाहिए और साथ ही उसका निर्धारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करके किया जाना चाहिए।
- (ज) यह तर्क निराधार है कि कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट आने के कारण टीडीआई की कीमत में गिरावट आई है। वर्षों से कच्चे माल की कीमत में गिरावट आने का कोई अभिप्राय नहीं है चूंकि पाटन मार्जिन सकारात्मक पाया गया है। प्रमुख कच्चे

माल की कीमत में ऐसी गिरावट आने के बावजूद भी निर्यातक अपने घरेलू बाजार में अधिक कीमत पर बिक्री कर रहे हैं और वे भारत में कमतर कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं अर्थात् उसकी घरेलू कीमतें पाटन में परिवर्तित हो रही हैं।

- (श्र) टोल्यूने की कीमत में गिरावट, सहयोगी निर्यातकों के मामले में स्वीकृत पाटन मार्जिन और साथ ही देश व्यापी मार्जिन का खंडन नहीं करती है। कच्चे माल की कीमतों ने गिरावट को दर्शाया है लेकिन उल्लेखनीय तथ्य यह है कि निर्यातकों द्वारा घरेलू रूप से पेश की जा रही कीमतों और भारत में जिस कीमत पर निर्यात किए गए हैं, उनमें अंतर होना है। जब तक पाटन का मार्जिन सकारात्मक रहता है, तब तक कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आने का कोई अभिप्राय नहीं होता है और घरेलू उद्योग पहले से ही संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपनाई गई पाटन की पद्धति के खिलाफ खुल कर लड़ रहा है और न कि कच्चे माल की कीमतों में किसी प्रकार की गिरावट आने के कारण टीडीआई की कीमत में कोई गिरावट आई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 'बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार' के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध 1 के अधीन निर्धारित संगत उपबंध निम्नानुसार हैं :

- 8 (1) "गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

- (2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटन-रोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी- को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था- वाला देश नहीं है।

- (3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:

- (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं ;

- (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर - बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ;

- (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ;

- (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं ;

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटन-रोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

[[4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटन-रोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो]

33. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन के शामिल होने के नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है :

गैट 1994 का अनुच्छेद 4, टैरिफों और व्यापार हेतु सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद 4 के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटन-रोधी करार) और एससीएम करार चीन के डब्लूटीओ के सदस्य के रूप में आयात शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित से संगत होने पर लागू होंगे :

(क) गैट 1994 का अनुच्छेद 4 और पाटन-रोधी करार के अधीन कीमत तुलनीयता निर्धारित करने के लिए आयातक डब्लूटीओ देश या तो चीन की कीमतों या जांच के अधीन उद्योग की लागतों या ऐसी पद्धति का प्रयोग करेगा जो निम्नलिखित नियम के अधीन घरेलू कीमतों और चीन में लागतों की कड़ी तुलना पर आधारित हों :

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हों कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पादन उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं, तो आयातक डब्लूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण के लिए जांच के अधीन उद्योग हेतु चीन की कीमतों या लागतों का प्रयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्लूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का इस्तेमाल कर सकता है जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो परंतु यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकता हो कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पादन उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अधीन कार्यवाही में, जब एससीएम करार के संगत उपबंधों के अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14 (घ) में वर्णित सब्सिडी पर विचार करना लागू हो : तथापि यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाई हो, तो आयातक डब्लूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और माप के लिए ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जिसमें इस संभावना पर विचार हो कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें हमेशा समुचित बेंचमार्कों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों के प्रयोग में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्लूटीओ सदस्य को चीन से बाहर प्रचलित नियमों और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित नियमों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्लूटीओ सदस्य पाटन-रोधी प्रथाओं संबंधी समिति के उप पैराग्राफ (क) के अनुसार पद्धतियों को अधिसूचित करेगा और सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति के उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार आयातक डब्लूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अधीन चीन के बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश सिद्ध होने पर, उप पैराग्राफ (क) के उपबंध समाप्त हो जाएंगे परंतु यह कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में शामिल होने की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था के मापदंड शामिल हों। किसी स्थिति में उपपैराग्राफ (क) (ii) के उपबंध शामिल होने की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा चीन को आयातक डब्लूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार यह सिद्ध करना होगा कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं उस उद्योग या क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के उपबंध उस उद्योग या क्षेत्र पर अब लागू नहीं होते हैं।"

34. अनुच्छेद 15 का अर्थ है कि एक उप पैराग्राफ के उपबंध चीन के शामिल होने की तारीख से 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस पैराग्राफ के उपबंध 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए। चूंकि पाटन के घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का तथ्य जांच अवधि के आधार पर सिद्ध हो गया है इसलिए जांच अवधि के दौरान प्रचलित स्थिति ही संगत, समुचित है और वर्तमान जांच के लिए आवश्यक है। वर्तमान समीक्षा के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2015 से मार्च 2016 है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उपपैराग्राफ जांच की अवधि के दौरान मौजूद था इसलिए यदि जांच के अधीन उत्पादक उस उत्पाद के विनिर्माण उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद के उत्पादक उद्योग में स्पष्ट रूप से बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं न दिखा सकते हों कि प्राधिकारी ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जनवादी गणराज्य को भारत और अन्य डब्लूटीओ सदस्यों द्वारा पाटन-रोधी जाँचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातक द्वारा इस धारणा के खंडन के अधीन माना गया है। तथापि पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई भागीदारी नहीं की गई है इसलिए यह नोट किया जाता है कि एनएमई की धारणा जो पीओआई के दौरान प्रचलित थी का नियम के अधीन खंडन नहीं किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि जांच 5.10.2016 को शुरू हुई थी और वर्तमान जांच के लिए निर्धारित पीओआई अप्रैल 2015-मार्च 2016 है, इसलिए चीन एक्सेसन संधि के उपबंध जो कहते हैं कि डब्लूटीओ सदस्य चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध किसी पाटन-रोधी जांच के मामले में 11 दिसंबर, 2016 तक एनएमई पाटन-रोधी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान जांच में भी चीन जनवादी गणराज्य के संदर्भ में लागू होते हैं।

36. हानवा के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों की सत्यता और उसकी लागत की सत्यता के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हानवा के दावों और साथ ही घरेलू उद्योग के निवेदनों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की जांच की गई है। अनन्तिम जांच परिणाम में हानवा फाईन केमिकल कार्पोरेशन (एचएफसीसी) के लिए पृथक विशिष्ट मार्जिन का निर्धारण किया गया था, जैसा कि उत्तर की प्रारंभिक जांच करने से यह पता चला था कि संबंधित प्रयोज्यता एचएफसीसी था और आगे जांच होने के आधार पर प्रारंभिक मत को माना गया था। वास्तव में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करते समय प्रयोज्यता हानवा केमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) था, जो कि पहले हानवा फाईन केमिकल कार्पोरेशन (एचएफसीसी) के नाम से ज्ञात था और 29.02.2016 से प्रयोज्यता एचएफसी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। कंपनी के रिकार्ड, अंततः एचएफसीसी के एचसीसी में समामेलित हो जाने के तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच के अध्यक्षीन हैं और यह नोट किया जाता है कि कंपनी के रिकार्ड के अनुसार दावे जांच के अध्यक्षीन हैं। हानवा ने ऐसे भी निवेदन किए हैं कि जिस प्रयोज्यता ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए थे, वह वास्तव में एचसीसी है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में एचएफसीसी का नाम को केवल इसलिए प्रयुक्त किया गया था क्योंकि जांच अवधि के दौरान एचएफसीसी द्वारा निर्यात किए गए थे। सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए गए कंपनी के रिकार्ड और सत्यापन के आधार पर यह नोट किया जाता है कि हानवा केमिकल कार्पोरेशन को संबंधित पृथक विशिष्ट मार्जिन स्वीकृत करना, रिकार्डों के तथ्यों के विरुद्ध नहीं होगा और तदनुसार, हानवा केमिकल कार्पोरेशन पर विचार करते हुए इस अंतिम जांच परिणाम में पृथक विशिष्ट मार्जिन निर्धारित किया गया है।

37. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि कंपनी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के साथ पूरे व्यौरे नहीं दिए हैं और सत्यापन करने के समय और उसके बाद विभिन्न सूचनाएं प्रस्तुत की हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचसीसी से संबद्ध वस्तुओं से संबंधित उनके उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त की गई थी और उसका आवश्यक सत्यापन किया गया था। एचसीसी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए ऐसी संपूर्ण और सत्यापित सूचना पर विचार किया गया है।

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण

38. धारा 9 (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:-

(1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए निश्चित हो, अथवा

(2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

39. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उपबंध है कि:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

40. इन नियमों के अनुसार, एनएमई देशों (वर्तमान मामले में चीन) में सामान्य मूल्य को निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जा सकता है :

- (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर, या
- (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य, या
- (ग) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों की कीमत
- (घ) यदि उक्त विकल्पों से सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता हो तो, निर्दिष्ट प्राधिकारी समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करके विधिवत रूप से समायोजन द्वारा सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

I. चीन जनवादी गणराज्य

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी उत्पादक/निर्यातक जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, ने विहित ढंग और तरीके से उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, चीन जनवादी गणराज्य से वर्तमान जांच में कोई उत्पादक/निर्यातक नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-6 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की दशा में प्रचालनरत नहीं पाये गये हैं। इस परिस्थिति में, प्राधिकारी चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं और प्राधिकारी को संबंधित नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश में लागत और कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री या तीसरे देश की निर्यात बिक्री तथा तीसरे देश में ऐसे उत्पादकों की उत्पादन लागत और सहयोग संबंधी पूरे और विस्तृत आकड़े अपेक्षित होंगे। इस बाजारों में प्रचलित कीमत और लागत के संबंध में ऐसी कोई सूचना आवेदक अथवा प्रतिवादी निर्यातक ने प्रदान नहीं की है न ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना प्राप्त हुई है, न ही चीन की कंपनियों ने इस स्तर पर बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश के संबंध में कोई दावा किया है। अतः प्रारंभिक निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने की कार्यवाही की है।

43. प्राधिकारी पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का कारखाना-द्वारा सामान्य मूल्य उत्पादन की परिकलित लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत और लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

II. जापान

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और याचिकादाता के खपत के मानकों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत और लाभ को विधिवत् समायोजित किया गया है, जो कि *** अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

III. कोरिया गणराज्य

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से दो उत्पादकों अर्थात् मेसर्ज बीएसएफ कंपनी लि. और मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं।

(क) बीएसएफ कंपनी लिमिटेड

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएसएफ कंपनी लिमिटेड ("बीएसएफ") ने संबद्ध वस्तु के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि उसने भारत को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएसएफ ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्री के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

47. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण परीक्षण किया है। यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है और यदि लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद सौदों पर ही विचार किया गया है। यह भी नोट किया गया कि घाटे वाले सौदे कुल घरेलू

विक्री के 20 प्रतिशत से अधिक थे। इसलिए, प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध 1 के परंतुक के अनुसार केवल लाभप्रद विक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया की है।

48. मेसर्स बीएसएफ ने छूट, अंतरदेशीय भाड़े और पैकिंग लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने अनंतिम जांच परिणामों के लिए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार, बीएसएफ द्वारा उत्पादित पीयूसी के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर अनंतिम भारत औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(ख) हानवा कैमिकल कार्पोरेशन

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हानवा कैमिकल कार्पोरेशन ("एचसीसी") ने कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु का उत्पादक के रूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और बताया है कि उसने भारत को असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। एचसीसी ने यह भी निवेदन किया है कि कंपनी ने तीन निर्यातकों/व्यापारियों के जरिए भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और उन्होंने एचसीसी के साथ निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

50. एचसीसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर की एचसीसी के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि एचसीसी मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् टीडीए और मध्यवर्ती वस्तु के रूप में सीडीसी का उत्पादन करती है। उनके द्वारा केप्टिवली रूप से उत्पादित ऐसे मध्यवर्ती पदार्थों की लागत की विस्तार से जांच की गई है और तदनुसार एचसीसी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की उचित लागत निर्धारित की गई है और इसका उपयोग ओसीटी परीक्षणों के प्रयोजनार्थ किया गया है। यह नोट किया जाता है कि 86% विक्रियां घाटे में थीं और इसलिए लाभप्रद विक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(ग) कोरिया गणराज्य में अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक के सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(ख) निर्यात कीमत का निर्धारण

I. चीन जनवादी गणराज्य

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, याचिकादाता द्वारा किए गए दावे के अनुसार उचित समायोजन करने के साथ डीजीसीआईएंडएस के आयात के आंकड़ों के आधार पर किया है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

II. जापान

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाटन-रोधी जापान में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण, याचिकादाता द्वारा किए गए दावे के अनुसार उचित समायोजन करने के साथ डीजीसीआईएंडएस के आयात के आंकड़ों के आधार पर किया है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

III. कोरिया गणराज्य

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से दो उत्पादकों अर्थात् मेसर्स बीएसएफ कंपनी लि. और मेसर्स हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। यद्यपि बीएसएफ कंपनी लि. द्वारा यह बताया गया है कि उन्होंने भारत को सीधे पीयूसी का निर्यात किया है तथापि हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन ने यह बताया है उन्होंने संबद्ध वस्तु का निर्यात असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों अर्थात् मेसर्स पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड मेसर्स आइएमएस कार्पोरेशन और मेसर्स एवरलाइट कोरिया कं. लि. के जरिए किया है जिन्होंने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए हैं और प्राधिकारी से सहयोग कर रहे हैं।

55. मेसर्स पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड मेसर्स आइएमएस कार्पोरेशन और मेसर्स एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड नामक निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और दावा किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को मेसर्स हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

56. संयुक्त अरब अमीरात मूल की एक व्यापारिक कंपनी मेसर्ज टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर करते हुए दावा किया है कि उन्होंने मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के कोरियाई निर्यातक मेसर्ज पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है।

(क) बीएसएसएफ कंपनी लिमिटेड

57. प्राधिकारी बीएसएसएफ कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से नोट करते हैं कि बीएसएसएफ कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान सीधे भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। बीएसएसएफ ने अपने परिशिष्ट 2 में 11340 मी.टन के कुल निर्यात होना सूचित किया है और अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(ख) मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक) और मेसर्ज पी पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज पी पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके उनके मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के निर्यातक होने का दावा किया है। पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट – 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के 2200 मी.टन का निर्यात किया है। पी पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के लिए भारत औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(ग) मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक) और मेसर्ज आईएमएस कार्पोरेशन (निर्यातक)

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके उनके मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के निर्यातक होने का दावा किया है। आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट – 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के 560 मी.टन का निर्यात किया है। आईएमएस कार्पोरेशन ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, आईएमएस कार्पोरेशन के लिए अंतिम भारत औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(घ) मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक) और मेसर्ज एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके उनके मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के निर्यातक होने का दावा किया है। मेसर्ज एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट – 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के 180 मी.टन का निर्यात किया है। मेसर्ज एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, मेसर्ज एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड के लिए अंतिम भारत औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(ङ) मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक), मेसर्ज पी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) और मेसर्ज टीजे एल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूआई (व्यापारी)

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज टीजे एल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। मेसर्ज टीजे एल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने दावा किया है कि वे यूआई मूल की एक ट्रेडिंग कंपनी हैं और उन्होंने मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को जांच अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य के निर्यातक अर्थात् मेसर्ज पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट – 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान मेसर्ज हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के 1000 मी.टन का निर्यात किया है। सत्यापन के समय वे भारतीय ग्राहक को आपूर्ति की पूरी श्रृंखला के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसको ध्यान में रखते हुए मेसर्ज पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से इस व्यापारी के लिए निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(च) कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने एक सहयोगी निर्धारित की निर्यात कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है और यह ***अमरीकी डालर/किलोग्राम है।

(घ) पाटन मार्जिन का निर्धारण

63. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नानुसार है :

| क्रमांक | देश | उत्पादक | निर्यातक | सामान्य मूल्य - अम.डा./किग्रा. | निर्यात कीमत- अम.डा./किग्रा. | पाटन मार्जिन - अम.डा./किग्रा. | पाटन मार्जिन - % | पाटन मार्जिन सीमा- % |
|---------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | चीन जनवादी गणराज्य | कोई | कोई | *** | *** | *** | *** | 15-25 |
| 2 | जापान | कोई | कोई | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 3 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | मेसर्स पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 10- 20 |
| 4 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | एवरलाइट कोरिया कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 5 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | आईएमएस कार्पोरेशन | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 6 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | मेसर्स पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. और मेसर्स टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 7 | कोरिया गणराज्य | बीएसएफ कं. लि. | बीएसएफ कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 8 | कोरिया गणराज्य | उक्त क्र. सं. 3 से 7 से इतर कोई अन्य उत्पादक | उक्त क्र. सं. 3 से 7 से इतर कोई अन्य निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 30-40 |

च. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच**च.1 क्षति की जांच****निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

- (1) भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत निर्धारण जीएनएफसी, जो प्रमुख स्थानीय कंपनी है, जैसे समान उत्पाद के अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ तुलनीय है।
- (2) शुल्क लगाने से एकाधिकार हो जाएगा क्योंकि जीएनएफसी एकमात्र उत्पादक है और वह भारतीय क्रेताओं के लिए सामग्री की उपलब्धता को सीमित कर देगा।

- (3) शुल्क लगाने से भारत में मांग-पूर्ति का अंतर हो सकता है। भारतीय उद्योग 100 मांग की आपूर्ति नहीं कर सकता है। निम्नवर्ती उत्पादों के स्थानीय विनिर्माता पाटन-रोधी शुल्क लागू होने से नुकसान में रहेंगे।
- (4) इस मामले में कुछ विशिष्ट स्थितियां इस प्रकार हैं: याचिकादाता द्वारा अचानक और पर्याप्त क्षमता का विस्तार करना, याचिकादाता द्वारा वर्ष 2014 में संयंत्र को बंद कर देना और उपयुक्तता के आधार पर जांच अवधि का चयन करना। दावा की गई क्षति के परिपेक्ष्य में इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- (5) वर्ष 2013-14 में याचिकादाता की स्थापित क्षमता 14000 मी.टन थी। वर्ष 2014-15 में इस स्थापित क्षमता में 4-5 गुना वृद्धि हुई थी, जो कि 64000 मी.टन हो गई थी। लाभ-अलाभ बिन्दु प्राप्त करने और क्षमता उपयोग को सामान्य और स्थिर बनाने के लिए पर्याप्त गर्भावस्था अवधि थी। ऐसी स्थिति में याचिकादाता का वर्ष 2015-16 में क्षति होने का दावा असामयिक, अनावश्यक और पूर्णतया भ्रामक है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 (जांच अवधि) में याचिकादाता की निश्चित लागत में भी वृद्धि हुई है।
- (6) याचिकादाता ने सुगमता से इस तथ्य को दबा कर रखा है कि संयंत्र के परिसर में घातक गैस स्राव होने के कारण उनका संयंत्र वर्ष 2014 में जनवरी से लेकर नवंबर तक से बंद पड़ा हुआ था। समग्र वर्ष में इस संयंत्र के बंद होने के कारण संयंत्र को भी क्षति हुई थी। याचिकादाता भी संयंत्र को ठीक करने और अपनी क्षमता उपयोग को दुबारा प्राप्त करने में ढीला रहा है।
- (7) जांच अवधि एक अनूठी अवधि है, जिसके दौरान याचिकादाता के घाटे स्पष्ट रूप से आडम्बरपूर्ण हैं। याचिकादाता ने वर्ष 2015-16 (जांच अवधि) की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि जांच अवधि एक विशिष्ट वर्ष है, जिसमें वैश्विक क्षमताओं के बढ़ने के कारण टीडीआई की कीमतें कम हुई हैं।
- (8) यह स्पष्ट है कि जब कि समस्त क्षति अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं, वैश्विक क्षमताओं के बढ़ने के कारण जांच अवधि में उनमें मामूली गिरावट आई थी। तथापि, जांच पश्चात अवधि में कोई भी अनन्तिम शुल्क को लागू करने से पूर्व कीमत में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। प्राधिकारी को अपना प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले ऐसे विशिष्ट कारकों पर विचार करना चाहिए था।
- (9) वर्ष 2014 के दौरान जब कि याचिकादाता का संयंत्र बंद पड़ा हुआ था, संकटपूर्ण स्थिति में याचिकादाता का क्षमता उपयोग 37.09% के स्तर पर था। याचिकादाता क्षति के लिए इस कारक को जिम्मेदार नहीं मानता है, लेकिन अपने घाटों के लिए आयातों पर दोष मढ़ता है।
- (10) कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रदान नहीं की गई हैं/उन पर कतई विचार नहीं किया गया है। वस्तुतः क्षति अवधि और जांच अवधि में विश्व भर में टीडीआई की कीमतों में गिरावट आई है। उसके बाद टीडीआई की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- (11) क्षति रहित कीमत ("एनआईपी") का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और कम कीमत पर बिक्री होने और कीमत ह्रास होने के आरोप के समर्थन में कोई परिकलन नहीं किया गया है, जिसके लिए याचिकादाता द्वारा दावा किया गया है। जहां तक कि प्राधिकारी ने याचिकादाता के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली का भी उल्लेख नहीं किया है और न ही क्षति रहित कीमत की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है।
- (12) आधार वर्ष में याचिकादाता द्वारा मूल क्षमताओं का अचानक और पर्याप्त रूप से लगभग 4-5 गुना संवर्धन करने के साथ-साथ वर्ष 2014 में संयंत्र के बंद होने के फलस्वरूप उसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है। जैसा कि याचिकादाता के निजी आंकड़ों से पता चलता है, यह बड़े हुए ब्याज और लागतों में ह्रास होने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसने याचिकादाता के घाटों को बढ़ाया है।
- (13) भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है और न ही याचिकादाता ने ऐसा दावा किया है। इस प्रकार (विशेष परिस्थितियों और मांग में वृद्धि होने को ध्यान में रखते हुए) आयातों की मात्रा में न तो समग्र रूप से कोई वृद्धि हुई है और न ही आयातों की मात्रा में कोई सापेक्षिक वृद्धि हुई है।
- (14) उत्पाद की मांग ने अत्यधिक वृद्धि दर्शाई है। संबद्ध देशों से आयातों की प्रवृत्ति से गिरावट की प्रवृत्ति का स्पष्टतया पता चलता है। इस प्रकार संबद्ध देशों ने मांग में वृद्धि होने पर बाजार के अपने हिस्से को गंवा दिया है, जो कि वर्ष 2012-13 में 60.76% से घट कर जांच अवधि में 49.87 % रह गया है। सूचीबद्ध प्रवृत्ति से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की 89 सूचीबद्ध यूनिटों की वृद्धि की तुलना में उनकी वृद्धि 7 सूचीबद्ध यूनिट मात्र है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने कारगर ढंग से बाजार मांग में हुई वृद्धि को भी हथिया लिया है, जब कि उनका हिस्सा वर्ष 2012-13 में 34.32% से पर्याप्त रूप से बढ़ कर जांच अवधि में 50% हो गया है।

- (15) आधार वर्ष में संबद्ध देशों से आयातों में मात्र 6.70% की वृद्धि हुई है, जो कि मांग में समग्र वृद्धि का मात्र 31.13% है। मांग में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि की समग्र मात्रा को याचिकादाता द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है, जब कि 3% मात्रा आयातों पर छोड़ दी गई है। वर्ष 2012-13 और जांच अवधि के बीच समग्र रूप से संबद्ध देशों से आयातों में 2018 मी.टन की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में मांग में 14867 मी.टन तक की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।
- (16) समस्त क्षति अवधि में सभी संबद्ध देशों के लिए कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है। चिकादाता के दावे के विपरीत कोई कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण अथवा कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि याचिकादाता की लागत अंतरभूत कारणों से बढ़ गई है। चूंकि उत्पाद की कीमतें विश्वभर में कम हो रही हैं, आयातों की कम हुई कीमत को “अनुचित” अथवा “पाटित” नहीं कहा जा सकता है।
- (17) याचिकादाता के आर्थिक प्राचलों के आधार पर क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ कम कीमत पर बिक्री होना संबद्ध मानदंड नहीं है। निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ {विशेष सिविल आवेदन-पत्र संख्या 16426/2016 और 16427/2016} के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि कम कीमत पर बिक्री का निश्चरण तभी प्रासंगिक होगा जब अन्य आर्थिक प्राचलों के आधार पर क्षति सिद्ध हो जाए।
- (18) क्षति का निर्धारण करने के लिए एक कारक के रूप में “कम कीमत पर बिक्री” की प्राधिकारी की अवधारणा अनुचित है। प्राधिकारी किसी अंतिम जांच परिणाम को जारी करने से पहले इस त्रुटि को उचित रूप से सुधार सकते हैं।
- (19) कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी को याचिकादाता के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित करने की आवश्यकता है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण, याचिकादाता की वास्तविक स्थिति का एक कारक होना चाहिए क्योंकि क्षमता विस्तार के कारण याचिकादाता के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, एक वर्ष तक संयंत्र के बंद होने के कारण घाटे हुए हैं और वैश्विक कीमतों में गिरावट आने के फलस्वरूप क्षति रहित कीमत बड़ी है। यदि याचिकादाता की निर्यात कीमत की जांच की जाती, तो उससे भी घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत का पता चल जाता।
- (20) क्षति-रहित कीमत की संरचना, याचिकादाता द्वारा वहन की गई विशिष्ट लागतों को यदि कोई है, की उपेक्षा कर देती। क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए केवल कारगर उत्पादन की लागत पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकादाता की क्षति-रहित कीमत के लिए अचानक और पर्याप्त क्षमता विस्तार पर अत्यधिक ऊपरी खर्च, संयंत्र के बंद होने और परिणामी निष्क्रियता होने के साथ-साथ पर्याप्त क्षमता का विस्तार करने के कारण घाटे होने और साथ ही वैश्विक कीमत में गिरावट आने को गलती से कारक माना गया है।
- (21) याचिकादाता के इस दावे के विपरीत कि उसे उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के बावजूद बिक्री कीमतें कम करनी पड़ी थीं, संबद्ध अवधि में टीडीआई के उत्पादन की लागत में कमी हुई है। टीडीआई की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद याचिकादाता के उत्पादन की लागत अवास्तविक रूप से बढ़ रही हैं। वास्तव में न केवल भारतीय बाजार में बल्कि एशिया भर में टीडीआई की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने वर्ष 2015-16 (जांच अवधि) की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है कि जांच अवधि एक अनूठी अवधि है, जिसमें वैश्विक क्षमताओं के बढ़ने के कारण टीडीआई की कीमतें कम हुई हैं।
- (22) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के आंकड़े वृद्धि दर्शाते हैं। क्षमता विस्तार करने और वर्ष 2014 में संयंत्र के बंद रहने के कारण याचिकादाता की लाभप्रदता प्रभावित हुई है। याचिकादाता के वेतन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, हालांकि याचिकादाता ने इन कारकों के संबंध में कुछ क्षति दर्शाई है।
- (23) वेतन और उत्पादकता के प्राचलों द्वारा हुई क्षति के लिए संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। निवेशों पर कम प्रतिलाभ से स्पष्ट पता चलता है कि इसका कारण अधिक ब्याज और मूल्यह्रास है। वस्तुतः ये कारक क्षमता विस्तार और संयंत्र के बंद होने के लिए जिम्मेदार हैं।
- (24) याचिकादाता ने क्षति होने का दावा बड़ी हुई मालसूचियों के कारण किया है। तथापि, मालसूचियों में वृद्धि होने का सीधा संबंध, याचिकादाता की बिक्रियों की मात्रा में वृद्धि होने के साथ है। प्राधिकारी को याचिकादाता की मालसूचियों और बिक्रियों की बीच सह-संबंध पर विचार करते समय सेस्टेट द्वारा ब्रिजस्टोन टायर मेन्सुफेक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्धारित किए सिद्धांतों पर विश्वास करना चाहिए, जिसमें यह बताया गया है कि “बिक्रियों की मात्रा की तुलना में मालसूची का स्तर प्रतिशत-वार समान बना हुआ है और इसलिए इसे सीधे क्षति का एक सूचक नहीं माना जा सकता है।”

- (25) नियोजित पूंजी के संबंध में नियोजित पूंजी और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में याचिकादाता की ब्याज की कीमतों और मूल्यहास को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। यह निवेदन है कि याचिकादाता को क्षति, निरंतर ब्याज बढ़ने और मूल्यहास की लागतों के कारण हुई है, जो कि मूल क्षमता का 4-5 गुना विस्तार करने के फलस्वरूप है।
- (26) बड़े हुए घाटे और नकारात्मक नकदी प्रवाह उसी समय हुआ है जब अचानक और पर्याप्त क्षमता विस्तार करने के साथ-साथ वर्ष 2014 में संयंत्र बंद हुआ है।
- (27) अचानक और पर्याप्त क्षमता विस्तार, वर्ष 2014 में संयंत्र का बंद होना और टीडीआई की कीमतों में वैश्विक गिरावट आना ऐसे कारक हैं, जो कि घरेलू कीमतों को मुख्यतया प्रभावित कर रहे हैं।
- (28) यह अत्यधिक संदेहास्पद है कि चार वर्षों की अवधि के भीतर प्रति यूनिट वेतन लगभग दुगुना हो गया है। याचिकादाता के उत्पादन की बढ़ रही लागत का यह एक ऐसा कारक है जिसके लिए संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।
- (29) इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में 4-5 गुना वृद्धि हुई है जो कि क्षमता के विस्तार के समनुरूप है, लेकिन यह याचिकादाता के उत्पादन के आंकड़ों के समनुरूप नहीं है। उत्पादन में संतुलित वृद्धि के बिना बड़े कार्यबल की लागत, याचिकादाता को हो रही क्षति का एक कारण है।
- (30) यह नोट करना कठिन है कि जबकि क्षमता में वृद्धि होने और कार्यबल में 4-5 गुना विस्तार करने के फलस्वरूप समग्र उत्पादकता में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, प्रति कर्मचारी उत्पादकता वास्तव में आधी रह गई है। इस प्रकार उत्पादकता/उत्पादन के समनुरूप क्षमता विस्तार और परिणामी कार्यबल विस्तार का याचिकादाता के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- (31) प्राधिकारी ने अनन्तिम शुल्कों को लागू करने की आवश्यकता के बारे में ऐसी कोई “अतिरिक्त” विशिष्ट जांच नहीं की है। वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम कोई अनन्तिम शुल्क लागू करने की अनुमति नहीं देते हैं।
- (32) प्राधिकारी जांच पश्चात अवधि में बीएसएफ के रूप में शुल्क मार्जिन का परिकलन करने के लिए सामान्यकृत और सुस्थिर टीडीआई कीमतों पर विधिवत् विचार कर सकते हैं। जांच पश्चात अवधि के आंकड़े बहुत भिन्न स्थिति दर्शाते हैं, चूंकि उत्पाद की कीमत में वैश्विक वृद्धि हुई है। यह तथ्य स्वतः सिद्ध करता है कि याचिकादाता द्वारा चयनित जांच अवधि असमान्य है।
- (33) घरेलू उद्योग ने ऐसा सकारात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं किया है, जिससे यह पता कि संबद्ध देशों से आरोपित पाटित आयातों के कारण उसे वास्तविक रूप से क्षति हुई है।
- (34) समग्र रूप से अथवा उत्पादन और घरेलू खपत/मांग के संबंध में पाटित आयातों की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही अनन्तिम जांच परिणाम में इस संबंध में वास्तविक स्थिति की रिकार्डिंग सही प्रतीत नहीं होती है। यह देखा जा सकता है कि जैसा कि अनुबंध-2 के पैरा के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है, वर्तमान जांच में आयातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है और एक मात्र इस आधार पर वर्तमान जांच को कृपया समाप्त कर दिया जाए।
- (35) कीमत प्रभावों का निर्धारण करने में संबद्ध देशों से आयातों में घरेलू उद्योग के लिए विशेष कीमत प्रभाव होने के लिए व्याख्यात्मक बल की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमरीका से चाईना-ग्रेन ओरिएण्टल फ्लेट रोलड इलेक्ट्रिकल स्टील के मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपील न्यायाधिकरण ने यह पाया था कि घरेलू उद्योग को ऐसे कारण बताने की आवश्यकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने के लिए कीमत प्रवृत्तियों ने कैसे भूमिका अदा की है। प्रारंभिक जांच परिणाम के अनुसार ऐसी कोई कीमत कटौती नहीं हुई है क्योंकि आयातों के पहुंच मूल्य, संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों से अधिक हैं।
- (36) कम कीमत पर बिक्री होने के संबंध में यह निवेदन है कि यह क्षति का ऐसा कारक नहीं है, जिसकी जांच और विश्लेषण घरेलू कीमतों पर संबद्ध आयातों के कीमत प्रभाव के एक भाग के रूप में किया जाए, जैसा कि अनुबंध-3 के पैरा (2) में देखा जा सकता है।
- (37) ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है जिससे यह पता चले कि कैसे घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट, आयातों के पहुंच मूल्यों में हुई गिरावट से अधिक हुई है। साथ ही किन कारणों से घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि क्षति अवधि के दौरान टोलून और नाईट्रेट एसिड जैसे प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई है। इनकी जांच करने की भी आवश्यकता है। घरेलू कीमतों में गिरावट के बारे में स्पष्ट किया जाए और उसे कच्चे माल की कीमतों में विशेष गिरावट आने के साथ जोड़ा जाए।
- (38) घरेलू उद्योग को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि घरेलू कीमतों में गिरावट आरोप्य है और यह पाटित आयातों के प्रभाव के कारण आई है। तथापि, वर्तमान जांच में इसका पूर्णतया कोई उल्लेख नहीं है।

- (39) क्षति अवधि में मूल्यहास, ब्याज और वेतन की लागत में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है, जो कि क्रमशः 153%, 1541% और 373% है। इसलिए घरेलू उद्योग की क्षमता में 50000 मी.टन तक का विस्तार किए जाने के फलस्वरूप मूल्यहास, ब्याज, वेतन की लागत और ऊपरी व्यय में वृद्धि होने के कारण संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई है। इसलिए वर्तमान मामले में कीमत की रोकथाम करने का कोई मामला नहीं है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है।
- (40) बिक्रियों, बाजार के हिस्से, क्षमता, उत्पादन, कर्मचारियों की संख्या, वेतन, क्षमता उपयोग आदि में काफी वृद्धि हुई है, जो कि कोई क्षति नहीं दर्शाती है। इसके अतिरिक्त औसत मालसूची में भी बहुत मामूली वृद्धि हुई है। वर्तमान जांच में प्रति कर्मचारी उत्पादकता काफी कम हो गई है, जो कि क्षति जांच अवधि की तुलना में 44% से भी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लागत और क्षति में वृद्धि हुई है और न कि पाटित आयातों के कारण।
- (41) अन्य कारकों के कारण अत्यधिक लागत हो जाने के कारण लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ को नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त निवेश के लिए पूंजी जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग के आर्थिक कारकों ने सुधार दर्शाया है और जिन कारकों ने नकारात्मक प्रभाव दर्शाया है, वह संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं बल्कि अन्य कारकों के कारण प्रभावित है।
- (42) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। तथापि, यह वृद्धि उसी अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में तदनुसूची वृद्धि की तुलना में बहुत न्यूनतम है।
- (43) घरेलू उद्योग का उत्पादन आधार वर्ष में 17,845 मी.टन था, जो कि जांच अवधि में बढ़ कर 45,680 मी.टन हो गया है। यह विशाल वृद्धि लगभग 250% है। यह स्पष्ट है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में अति विशाल सुधार हुआ है। इस तथ्य को देखते हुए कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लगभग 128% की अधिक क्षमता से प्रचालन कर रहा था, उक्त वृद्धि बहुत अधिक है।
- (44) उत्पादन और बिक्रियों के रूप में संवृद्धि विशाल रही है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में बिक्रियों की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त की है। इस प्रकार आरोपित पाटित आयातों के कारण इस कारक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (45) प्रारंभिक जांच परिणाम के अनुसार घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा आधार वर्ष में 34% था, जो जांच अवधि में बढ़ कर लगभग 50% हो गया है। दूसरी ओर संबद्ध देशों के बाजार का हिस्सा आधार वर्ष में 61% था, जो जांच अवधि में घट कर 49.8% हो गया है। घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट दर्शाती है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में उसके बाजार का हिस्सा 54% है।
- (46) चूंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2014-15 में अपनी क्षमता का विशाल संवर्धन किया है, जो कि लगभग 460% है। अल्प अवधि के भीतर अत्यधिक क्षमता उपयोग की प्रत्याशा करना न केवल अवास्तविक है, बल्कि असंगत भी है। घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि घरेलू उद्योग का निम्न क्षमता उपयोग “दहेज” संयंत्र में अस्थिर प्रचालन के कारण था और न कि पाटित आयातों के कारण। इस प्रकार इन कारकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है।
- (47) मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों के कुल बाजार का हिस्सा आधार वर्ष में 61% था, जो जांच अवधि के दौरान घट कर 49.87% रह गया। देश में संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग में 30% की वृद्धि होने के बावजूद क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और बाजार के हिस्से में पर्याप्त रूप से गिरावट आई।
- (48) घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आरोपित पाटित आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 168% था, जो जांच अवधि में पर्याप्त रूप से घट कर 70% रह गया। तुलना करने की दृष्टि से यह गिरावट 98% है।
- (49) घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में भी यह मुख्यतया स्पष्ट किया गया है कि जांच का विश्लेषण करने की अवधि में उसने उपयुक्त प्रोद्योगिकी की जानकारी के बिना कार्य किया था और “अस्थिर” “दहेज” संयंत्र और निरंतर दुर्घटनाएं, विफलताओं और झटके लगने के कारण उसे अत्यधिक घाटे हुए। इसलिए प्रतिवादियों का पुनः आग्रह है कि पाटित आयातों से भिन्न कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों को आरोपित नहीं किया जा सकता है।
- (50) घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्टतया दर्शाती है कि “दहेज” संयंत्र को छोड़ कर समग्र कंपनी ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। यह पहले से ही प्रमाणित हो चुका है कि घरेलू उद्योग की अक्षमताओं और कमियों के कारण उक्त “दहेज” संयंत्र को घाटे हुए हैं, जिसको घरेलू उद्योग ने स्वतः स्वीकार किया है।

- (51) उत्पादन की लागत में वृद्धि और क्षति एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह घरेलू उद्योग की निजी अक्षमताओं द्वारा सृजित एक कृत्रिम स्थिति है, जो कि आरोपित पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है।
- (52) घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट आई है। तथापि, उसने वर्ष 2015-16 (वर्तमान जांच में जांच अवधि) की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वतः यह स्वीकार किया है कि टीडीआई कीमतों में गिरावट वैश्विक घटना थी और यह विश्वभर में क्षमता विस्तार के कारण घटित हुई थी।
- (53) घरेलू उद्योग की प्रति दिन की उत्पादकता में 156% की अत्यधिक वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में रोजगार वृद्धि से संबंधित आंकड़े 359% की विशाल वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2014-15 में वेतन में वृद्धि 108% और जांच अवधि में 85% हुई थी। जहां तक वेतन का संबंध है, यह प्राचल बहुत संतुलित कार्य-निष्पादन दर्शाते हैं। कंपनी की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट भी दर्शाती है कि वेतन और मजदूरियों में विशेष रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- (54) वेतन में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को घाटे हुए हैं, जिनका समायोजन, क्षति विश्लेषण के साथ-साथ लागत/क्षति रहित कीमत का परिकलन के लिए किया जाना चाहिए।
- (55) टोल्यून की कीमतों में गिरावट आने के कारण संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। प्रतिशत के रूप में कीमतों में ऐसी गिरावट, टोल्यून और संबद्ध वस्तुओं दोनों के लिए लगभग बराबर है। संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने का मुख्य कारण टोल्यून की कीमतों में गिरावट आना है और न कि पाटन है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है।
- (56) घरेलू उद्योग ने अपनी गैर-लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि टीडीआई और दहेज यूनिट से घाटे पर्याप्त रूप से इतने कम हो गए हैं कि वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही में समग्र रूप से उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त हो गया है।
64. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के बारे में किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :
- (1) याचिका में प्रदत्त क्षति संबंधी सूचना दर्शाती है कि यद्यपि मात्रा संबंधी मापदंड जैसे क्षमता, उत्पादन और बिक्री में सामान्य दृष्टि में सकारात्मक प्रवृत्ति रही है तथापि अनेक अन्य संकेतक जैसे क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, मालसूची का स्तर आदि क्षति की स्थिति दर्शाते हैं।
 - (2) भारतीय बाजार में घरेलू मांग में 50 प्रतिशत बाजार हिस्सा कब्जा करके पाटित आयातों में प्रभुत्व बना रखा है जो काफी अधिक है और ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की स्थिति काफी संवेदनशील हो गई है।
 - (3) घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रमुख मापदंड जैसे लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय आदि पहले की सकारात्मक स्थिति से पीओआई के दौरान काफी नकारात्मक हो गये हैं और वास्तव में नियोजित पूंजी पर आय, वृद्धि आदि जैसे कारकों में गंभीर रूप से विकट वास्तविक क्षति की स्थिति दर्शाई है।
 - (4) वास्तव में, घरेलू उद्योग को दो आधार वर्षों को छोड़कर क्षति अवधि में संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातक द्वारा आक्रामक पाटन के कारण भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है।
 - (5) घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को उसकी उत्पादन लागत से कम पर बेचना पड़ रहा है क्योंकि पाटित आयात उत्पादन लागत से कम कीमत पर उपलब्ध हैं जिससे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त करने का उसका अधिकार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
 - (6) पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और पीओआई के दौरान सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव भी स्पष्ट हैं। कीमत कटौती इस मामले में क्षति दर्शाने वाला कारक नहीं है क्योंकि कीमतें पहले से ही कम हैं और घरेलू उद्योग लागत से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। इसलिए पंधुच कीमत से तुलना का प्रश्न नहीं उठता और वह अतार्किक है।
 - (7) घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर काफी बढ़ गया है जो क्षति के स्पष्ट लक्षण दर्शाता है। उत्पादन में वृद्धि को मालसूची में वृद्धि के आलोक में देखा जाना चाहिए जो इस तथ्य को सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों द्वारा बाजार में अधिक बिक्री से रोका गया है।
 - (8) विभिन्न आर्थिक मापदंडों का एक वस्तुनिष्ठ और समग्र मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के आधार पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव काफी अधिक है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की स्थिति क्षति अवधि के आरंभिक दो वर्षों के बाद घाटा उठाने वाली कंपनी में बदल गई है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

- (9) यहां तक कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में मात्रा संबंधी मापदंड भी काफी दबाव में हैं क्योंकि क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और वह समतुल्य स्तर से कम रहा है जबकि घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है और पाटित आयातों के पास 50 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा है।
- (10) वास्तव में उत्पादन और बिक्री में मामूल वृद्धि को पाटित आयातों से कीमत संबंधी गंभीर प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग के सामने समग्र घाटे के कारण ऋणात्मक हो गई है। घरेलू उद्योग को ऐसी कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है जो लाभकारी नहीं है और वास्तव में उसकी उत्पादन लागत से कम है। घरेलू उद्योग ने इस प्रकार वास्तविक क्षति उठाई है और यह क्षति संबद्ध देशों से पाटन के कारण हुई है।
- (11) कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड ने यह बताया है कि उनकी कीमत जीएनएफसी समेत अन्य आपूर्तिकर्ताओं से तुलनीय है। इस वक्तव्य का कोई विधिकया वास्तविक आधार नहीं है और कोवेस्ट्रो ने अपने दावों को सही साबित करने के लिए कोई नियतक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- (12) कोवेस्ट्रो ने यह आरोप लगाया है कि शुल्क लगाने से एकाधिकार हो जाएगा क्योंकि जीएनएफसी एकमात्र उत्पादक है और वह भारतीय क्रेताओं के लिए सामग्री की उपलब्धता को सीमित कर देगा। इस तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है। जीएनएफसी भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है जो इस कंपनी को पाटन से बचाना आवश्यक बना देता है नहीं तो घरेलू बाजार में विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व हो जाएगा, घरेलू उद्योग के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।
- (13) कोवेस्ट्रो ने यह आरोप लगाया है कि शुल्क लगाने से भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर हो जाएगा। इस दावे का कोई आधार नहीं है। पाटन-रोधी शुल्क वस्तुतः आयातों के विरुद्ध नहीं है। इससे पाटन के क्षतिकारी प्रभाव समाप्त होते हैं। मांग-आपूर्ति का अंतर, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग को पाटन से संरक्षण की मांग करने से नहीं रोकता है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे का अनेक जांचों में समाधान किया है और यह निरंतर पाया गया है कि मांग-पूर्ति का अंतर यदि कोई हो, पाटन को अनुमति देने का कारण नहीं हो सकता है।
- (14) कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित तीन विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियां यह प्रमाणित नहीं करती हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटन के कारण हुई है। क्षमता विस्तार भारत में मांग के अनुसार किया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, वर्ष 2014 में किसी संयंत्र का बंद हो जाना, वर्ष 2015-16 में क्षति होने का कारण नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत वैश्विक अतिरिक्त क्षमता प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा कारण हो सकती है, जिससे पाटन और परिणामी क्षति हुई हो।
- (15) यह तर्क कि याचिकादाता द्वारा अचानक और पर्याप्त रूप से क्षमता का विस्तार किया जाना क्षति का कारण है, किसी योग्यता के विहीन है। देश में उत्पाद की व्यापक मांग को देखते हुए क्षमता का विस्तार किया गया था। इस प्रकार घरेलू उद्योग ने क्षमता का विस्तार करके कोई गलती नहीं की है। तथापि, घरेलू उद्योग को जिस कारण से क्षति हुई है, उसका तथ्य यह है कि निर्यातक, जीएनएफसी द्वारा क्षमता का विस्तार करने से उत्तेजित हो गए और उन्होंने जीएनएफसी को बाजार से दूर रखने के लिए पाटन करना शुरू कर दिया, जो कि जांच अवधि में बहुत आक्रामक था।
- (16) जांच अवधि में आयातों की पहुंच कीमतें अत्यधिक घट गई थीं और ऐसे आयात पाटित दरों पर थे। जीएनएफसी आधार वर्ष में और उसके बाद के वर्ष में लाभ अर्जित कर रहा था। नए संयंत्र में किसी भी प्रकार की खराबियों का पता वर्ष 2014-15 में चला था और जांच अवधि में संयंत्र सामान्य रूप से चल रहा था, जो कि जांच अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग से स्पष्ट पता चलता है। इसके अतिरिक्त निश्चित लागतों में वृद्धि को कम क्षमता उपयोग के आलोक में देखने की आवश्यकता है। तथापि, क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुबंध-3 के आधार पर किया गया है और अधिक लागत निर्धारित करने के किसी भी प्रभाव को सामान्य किए जाने की आवश्यकता है और यदि ऐसी कोई भी आरोपित अधिक लागत है, तो याचिकादाता उसका अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार स्वतः किसी क्षति के कारण नहीं हुआ है और पक्षकारों की अन्य शंकाओं अर्थात् निश्चित लागतों की कोई योग्यता नहीं है।
- (17) यह तर्क सही नहीं है कि क्षति के कारण वर्ष 2014 में नया संयंत्र बंद हो गया था। जांच अवधि में उत्पादन सामान्य था और क्षमता उपयोग लगभग 71% था। यदि पाटन नहीं हुआ होता, तो घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन कर सकता था। यह भी नोट करने की आवश्यकता है कि जीएनएफसी क्षति अवधि के प्रारंभिक दो वर्षों में लाभ कमा रहा था और उसे जांच अवधि के अत्यधिक घाटे उठाने पड़े थे और यह ऐसी अवधि थी जिसमें आयातों की पहुंच कीमत निम्नतर थी जो कि सकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ हुई थी। वस्तुतः टीडीआई की वैश्विक अतिरिक्त क्षमताओं के कारण दबाव में आए उत्पादकों/निर्यातकों ने अपनी कीमतों को और कम कर दिया था और भारतीय बाजार में आक्रामक पाटन करना शुरू कर दिया था, जब भारत में घरेलू उद्योग ने भारतीय मांग के स्तर तक क्षमता को बढ़ा दिया था और निर्यातकों का प्रयास भारत में बाजार के हिस्से को कब्जे में करने का था। ऐसे पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी।

- (18) यह तर्क दिया गया है कि जांच अवधि के चयन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए जिसकी कोई योग्यता नहीं है। विगत जांच में इस पर विचार किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान आर्थिक क्षति हुई है और इसका समर्थन तथ्यों द्वारा किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि जांच अवधि पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- (19) कुछ प्रतिवादी पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि वैश्विक अतिरेक क्षमताओं के कारण जांच अवधि में टीडीआई की कीमतों में गिरावट आई है। इससे इसकी संपुष्टि होती है कि संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक अपनी क्षमताओं का निपटान करने के दबाव में थे और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने सामग्री का पाटन करने का लक्ष्य भारतीय बाजार को बनाया क्योंकि भारत में उसकी व्यापक मांग थी। यदि जीएनएफसी ने क्षमता विस्तार नहीं किया होता, तो वे अपनी कीमतें इतने निम्न स्तर तक नहीं घटाते। जब जीएनएफसी ने भारतीय मांग के समनुरूप अपनी क्षमता का विस्तार किया था, तो संबद्ध देशों के ऐसे निर्यातकों ने जो कि अतिरेक क्षमता के दबाव में थे, आक्रामक पाटन करना शुरू कर दिया ताकि वे भारतीय बाजार में अपने बाजार के हिस्से को बनाए रख सकें और जीएनएफसी को बाजार से दूर रख सकें।
- (20) सहयोगी पक्षकारों और अन्य से पाटन का स्पष्ट पता चलता है। क्षति स्पष्ट है। कारणात्मक संबंध होने से भी यह स्पष्ट होता है कि संबद्ध देशों से टीडीआई के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने चाहिए और अंतिम जांच परिणाम के समय प्रारंभिक परिणाम की संपुष्टि की जानी चाहिए।
- (21) पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार में लाभप्रद कीमतें वसूल करने से रोका है। घरेलू उद्योग पहले लाभ अर्जित कर रहा था और जांच अवधि में निर्यातकों द्वारा पेश की गई पाटित कीमतों के कारण उसे घाटे होने शुरू हो गए। संबद्ध देशों से कीमतों में अत्यधिक कमी हुई थी, जो कि आधार वर्ष में 166 रूपए/प्रति किलोग्राम से घट कर जांच अवधि में 113 रूपए/प्रति किलोग्राम हो गई थी। ऐसी स्थिति स्वतः स्पष्ट करती है कि कैसे ऐसी कीमतों के कारण कीमतों में हास और न्यूनीकरण के प्रभाव पड़े थे और अंततः घाटे हुए थे। जांच अवधि में बाजार में पाटित सामग्री विद्यमान होने के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की लागत वसूल करने में भी सक्षम नहीं हो सका था।
- (22) जांच अवधि में अर्थात् आधार वर्ष में संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने भी विशेषकर भारत में उत्पाद की व्यापक मांग को देखते हुए वर्ष 2014-15 में किए गए क्षमता संवर्धन की सहायता से जांच अवधि में मात्रा के कुछेक प्राचलों में वृद्धि दर्शाई है, हालांकि घरेलू उद्योग मात्रा के प्राचलों में बेहतर निष्पादन कर सकता था, यदि पाटन नहीं हुआ होता। लेकिन घरेलू उद्योग को कीमत के क्षेत्र में किसी मात्रात्मक वृद्धि का लाभ प्राप्त करने से रोका गया था क्योंकि पाटित आयातों के कारण कीमत हास और न्यूनीकरण हुआ था।
- (23) पाटन होने के कारण कीमत प्राचलों में घरेलू उद्योग के लिए मात्रा के कुछेक प्राचलों में वृद्धि को समग्र सकारात्मक स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार केवल एक आधार पर मात्रा के कुछेक प्राचलों में वृद्धि को देखने से क्षति की गलत छवि प्रकट होगी। जांच अवधि के दौरान बाजार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा पाटित आयातों के कब्जे में था और ऐसे स्तर अत्यधिक हैं और ऐसे स्तर घरेलू उद्योग की कीमत की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिबिंबित होते हैं।
- (24) आधार वर्ष में जबकि घरेलू उद्योग के पास सीमित क्षमता थी, पाटित आयातों के हिस्से में गिरावट आना मात्र ऐसा कारक नहीं है, जिससे पता चलता हो कि ऐसे आयातों का कोई परिणामी प्रभाव घरेलू उद्योग पर नहीं पड़ा है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की स्थिति, ऐसी थी कि कुछ प्राचलों ने जांच अवधि में कुछ वृद्धि दर्शाई है, जबकि कीमत प्राचलों में कोई समान वृद्धि हुए बिना यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। मात्रा प्राचलों में भी निष्पादन समान से कम था क्योंकि जांच अवधि में क्षमता उपयोग केवल 71% था और उसी अवधि में माल सूचियों में वृद्धि हुई है। यदि पाटन नहीं होता, तो मात्रा प्राचलों ने काफी बेहतर स्थिति दर्शाई होती।
- (25) यह सही नहीं है कि घरेलू उद्योग की कीमत बढ़ाई गई है। प्राधिकारी ने अनुबंध-3 के सिद्धांतों के अनुसार क्षति रहित कीमत निर्धारित की है और इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि याचिकादाता ने याचिका में क्षति रहित कीमत अथवा उसकी प्रवृत्ति का प्रकटन नहीं किया है।
- (26) निम्नलिखित प्राचलों के सारांश से पाटन के हानिकारक प्रभाव का स्पष्ट रूप से पता चलता है:-
- (क) आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई थी और यह भारतीय खपत के लगभग 50% पर स्थिर थी, जो कि घरेलू उद्योग के लिए बाजार को विकृत करने के लिए पर्याप्त रूप से अधिक थी।

- (ख) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग मात्र 70% था और ऐसा समतुल्य कम क्षमता उपयोग तब था, जब कि उत्पाद की सुसंगत व्यापक मांग थी और पाटन के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रभावित हो रहा था।
- (ग) जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वृद्धि हुई थी। यदि पाटन नहीं हुआ होता, तो मालसूचियां इकट्ठी जमा नहीं होतीं और घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन करता।
- (घ) जांच अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे हुए हैं, जबकि क्षति अवधि के प्रारंभिक 2 वर्षों में घरेलू उद्योग लाभप्रद प्रचालन कर रहा था।
- (ङ) जांच अवधि में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रत्यक्षतः गंभीर प्रकृति का है।
- (च) कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त नहीं कर रहा है।
- (छ) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, सकारात्मक स्थिति से बदल कर नकारात्मक हो गया है।
- (ज) हालांकि कागजात पर कीमत कटौती नकारात्मक है, लेकिन कीमतों के प्रभावों पर विचार करने के लिए उसे प्रमुख प्राचल नहीं माना जा सकता है, जैसा कि अन्यथा ऊपर उल्लिखित किया गया है।
- (झ) विभिन्न प्राचलों में संवृद्धि नकारात्मक रही है।
- (ञ) संबद्ध देशों और साथ ही प्रतिवादी निर्यातकों से भी पाटन मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक रहा है।
- (ट) उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत में क्षति हुई है तथा यह क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन होने के कारण हुई है।
- (27) घरेलू उद्योग की मजदूरियों और रोजगार के तर्कों के संबंध में उल्लेखनीय है कि रोजगार और कर्मचारियों को अदा किए गए वेतन के स्तर में वृद्धि, क्षमता/उत्पादन में हुई वृद्धि के समनुरूप और साथ ही भूमि के श्रमिक कानून के अनुसार हुई है। कंपनी की प्रति दिन उत्पादकता ने सुधार दर्शाया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रति किलोग्राम मजदूरियां लगभग दुगुनी हो गई हैं। मजदूरियां कंपनी के लेखापरीक्षित रिकार्ड के अनुसार हैं। विधि की अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा समय-समय पर मजदूरियों को अर्थक्षम सीमा बढ़ाया जाता है। तथापि, भविष्य में रोजगार स्तर और मजदूरियों में वृद्धि को बनाए रखना, पाटन-रोधी शुल्क द्वारा बाजार में संबद्ध वस्तुओं की उचित स्थिति पर निर्भर करेगा।
- (28) यह गैर-प्रमाणित तर्क है कि रोजगार का स्तर उत्पादन के समनुरूप नहीं है और घरेलू उद्योग को अतिरिक्त मजदूरियों के कारण क्षति हुई है तथा ऐसे रोजगार स्तर ने लाभप्रदता को प्रभावित किया है। रोजगार का स्तर अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या के समनुरूप है, जिनमें उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कुशल और अकुशल कर्मचारी शामिल हैं। क्षमता में संवर्धन होने से वर्ष 2014-15 में पहली बार कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और यह जांच अवधि में तुलनीय स्तर पर थी। स्वतः रोजगार के स्तर और मजदूरियों ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, लेकिन पाटित आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित क्षमता के समनुरूप उत्पादन में पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण रूकावट आई है और कम उत्पादन के कारण किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए भी पाटन जिम्मेदार है और उसे अलग से नहीं देखा जा सकता है।
- (29) कुछ प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। सीधा पढ़ने से तो ऐसे प्रतीत हो सकता है कि आधार वर्ष में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। लेकिन यह नोट करना प्रासंगिक है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग 71% के स्तर तक कर सकता था और जांच अवधि के दौरान जो कुछ उत्पादित और बेचा गया था, उतना बेहतर नहीं था जितना कि वह कर सकता था। उत्पादन और बिक्री देश में मांग के समनुरूप नहीं थी क्योंकि पाटन ने घरेलू उद्योग का लाभप्रद दर पर अधिक बिक्री करने से रोका हुआ था। इस प्रकार संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
- (30) वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मांग और बाजार का हिस्सा वही है, जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनी पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है और कंपनी के प्राक्कलनों के अनुसार उसकी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है।
- (31) जांच अवधि में भारतीय मांग में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा बहुत अधिक था और घरेलू उद्योग ऐसे पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण कोई लाभप्रद कीमत वसूल नहीं कर सका था। इस प्रकार आधार वर्ष में पाटित आयातों के हिस्से में अकेली गिरावट यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पाटित आयातों के बाजार के हिस्से का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

पाटित आयातों के बाजार के हिस्से का वास्तविक प्रभाव, जांच अवधि में ऐसे आयातों के अत्यधिक हिस्से (लगभग 50%) से स्पष्ट पता चलता है और निर्यातकों ने ऐसा अत्यधिक हिस्सा, आक्रामक पाटन से प्राप्त किया है। ऐसे पाटन के कारण घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त हालांकि मांग के समनुरूप क्षमता में वृद्धि हुई थी, जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग मात्र 71% था, जो कि समतुल्य स्तर से कम था और ऐसा कम उपयोग, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की विशाल मात्रा के विद्यमान होने के कारण हुआ है।

- (32) जांच अवधि में नया संयंत्र पूर्णतया प्रचालन में था और घरेलू उद्योग केवल 71% क्षमता उपयोग कर सका था, जो कि भारत में पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण हुआ था। यदि पाटन नहीं हुआ होता, तो घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन और बिक्री कर सकता था। जब मांग की स्थिति अधिक उत्पादन करने के लिए अनुकूल थी, तब पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के पास मालसूचियां अत्यधिक थीं और उसका क्षमता उपयोग समतुल्य से कम था।
- (33) यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों से आयातों का घरेलू उद्योग की घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उसकी मूल्य ह्रास की लागत, ब्याज और मजदूरियों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। ऐसे दावे सही नहीं हैं। कागज पर कीमत में कटौती नकारात्मक रही है क्योंकि अंततः आयातित उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए सस्ते थे। तथापि, वर्तमान मामले में कीमत ह्रास, कीमत न्यूनीकरण और साथ ही कीमत में कटौती होने का साफ पता चलता है। साथ ही यह भी नोट करने की आवश्यकता है कि कीमत में कटौती को यहां कीमत क्षति का मुख्य प्राचल के रूप में नहीं देखा जा सकता है, चूंकि कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण बहुत स्पष्ट है तथा घरेलू उद्योग पाटित आयातों द्वारा निर्देशित अनुसार अपनी कीमतें निर्धारित करने के लिए विवश था और वह स्वतंत्र और अप्रभावित स्थिति में नहीं था। हमारा विश्वास होट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील्स तथा सोडियम क्लोरेट आदि मामलों में हाल ही में की गई अनेक जांच पर अधिक बढ़ गया है, जिनमें कीमत में कटौती नकारात्मक रही है। इन जांच में स्पष्ट रूप से ऐसा विचार किया गया है कि कीमत में कटौती को ऐसे मामलों में प्रमुख प्राचल के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिनमें कीमत में कटौती नकारात्मक रही है और कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण का साफ पता चला है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग की मूल्य ह्रास की लागत, ब्याज और मजदूरियों ने भी वही प्रवृत्ति दर्शाई है, जो कि क्षमता और उत्पादन में वृद्धि होने की रही है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच अवधि में दावा की गई क्षति केवल इन कारकों के कारण हुई है और इसके विपरीत यह देखा जा सकता है कि पाटित कीमतों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (34) माल सूची के स्तरों पर प्रतिवादी पक्षकारों के तर्क सही नहीं हैं। ऐसे पक्षकारों के निवेदन स्वतः स्पष्ट करते हैं कि आधार वर्ष में औसत स्टॉक में उत्पादन के प्रतिशत के रूप में वृद्धि हुई है। औसत स्टॉक में ऐसी वृद्धि को कम नहीं माना जा सकता है। माल सूची की ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई है, जब व्यापक मांग थी और घरेलू उद्योग केवल 71% क्षमता उपयोग कर रहा था। इस प्रकार मात्रा के प्राचलों के रूप में भी पाटन के प्रभाव का साफ पता चलता है।
- (35) यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान जांच में प्रति कर्मचारी उत्पादकता, क्षति जांच में 44% से भी अधिक गिर गई है, जो कि अत्यधिक गिरावट है, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लागत और क्षति में वृद्धि हुई है। यह प्रेक्षण सही है। प्रति दिन उत्पादकता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी रोजमर्रा के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त या बर्खास्त कर सकती है और संयंत्र की क्षमता के अनुसार रोजगार का स्तर बनाए रखा जाता है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता को जिसने प्रभावित किया है, वह पाटन द्वारा प्रवर्तित कम उत्पादन है। यदि पाटन नहीं हुआ होता, तो क्षमता उपयोग अर्थात् उत्पादन अधिक होता, जिससे प्रति कर्मचारी उत्पादकता अधिक होती। इस प्रकार प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट भी पाटन के कारण आई है और इसका कोई अन्य कारण नहीं है।
- (36) यह तर्क दिया गया है कि लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ पर प्रतिकूल प्रभाव, घरेलू उद्योग की अधिक लागत के कारण पड़ा है। यह तर्क सही नहीं है। घरेलू उद्योग पहले लाभ अर्जित कर रहा था और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आक्रामक पाटन होने के फलस्वरूप इन कारकों में गिरावट आनी शुरू हो गई और नकारात्मक हो गई, चूंकि ऐसी कीमतें विभिन्न अन्य प्रतिकूल प्रभावों के साथ गंभीर कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव डाल रही थीं।
- (37) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिवादी पक्षकारों के तर्क सही नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा विगत दो और तीन वर्षों में निवेश प्राप्त किया गया था और पाटन के कारण किए गए ऐसे निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के खतरे के विरुद्ध कोई पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं लगाया जाता है, तो कोई भी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकताओं के लिए चिंता होगी।
- (38) संवृद्धि प्राचलों पर प्रतिवादी पक्षकारों के दावों के साथ-साथ क्षति पर निर्णय भ्रामक है। अनेक प्राचलों में विशेषकर कीमत प्राचलों में संवृद्धि नकारात्मक रही है। पाटन के परिणामस्वरूप आर्थिक प्राचलों ने गिरावट दर्शाई है, जो कि क्षमता उपयोग के

तुलनीय नीचे, मालसूची में वृद्धि, वित्तीय घाटों, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ आदि से प्रतिबिंबित होती है।

- (39) कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपीय विश्लेषण पर प्रतिवादी पक्षकारों के प्रेक्षण अप्रमाणित और भ्रामक हैं। वर्तमान मामले में पाटन और क्षति विद्यमान है तथा तथ्यों ने दर्शाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण क्षति हुई है। जांच किए गए विभिन्न अन्य प्राचल भी यह दर्शाते हैं कि क्षति होने का कारण कोई अन्य कारक नहीं है। तदनुसार, निर्यातक के दावों को खारिज करने की आवश्यकता है।
- (40) प्रतिवादी पक्षकारों का यह तर्क निराधार है कि क्षमता में 37% तक की वृद्धि होने के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग को घाटे हुए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार करने पर संबद्ध देशों से निर्यातकों ने आक्रामक पाटन करना शुरू कर दिया और ऐसे आक्रामक पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यदि कोई पाटन नहीं हुआ होता, तो घरेलू उद्योग निरंतर लाभ अर्जित कर रहा होता। पहले घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

65. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

66. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) के साथ पठित पाटन-रोधी नियम 11 में निम्नानुसार प्रावधान है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

67. प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण वस्तुतः विरोधी हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के भी विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा नीचे ध्यान दिया गया है :

68. इस तर्क के संबंध में कि निर्यातक की कीमत भारतीय बाजार में जीएनएफसी समेत अन्य आपूर्तिकर्ताओं से तुलनीय है, यह नोट किया जाता है कि इस विवरण से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए पाटन और क्षति के दावों का निरनुमोदन नहीं होता है और इसे निराधार विवरण माना जाना चाहिए।

69. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है और पीयूसी पर किसी पाटन-रोधी शुल्क से एकाधिकार हो जाएगा, यह नोट किया जाता है कि यह अनुरोध कानूनी या वास्तविक रूप से बिल्कुल निराधार है। पाटन-रोधी शुल्क, यदि कोई हो, को पाटन के व्यापार विकृतकारी प्रभावों को सही करने के लिए लगाया जाता है और नियमों किसी एकमात्र उत्पादक को पाटन से संरक्षण की मांग करने से वंचित नहीं करते हैं।

70. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाने से भारत में मांग पूर्ति में अंतर हो जाएगा क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में 100 प्रतिशत मांग को पूरा करने में असमर्थ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि पाटन-रोधी शुल्क लगाये जाते हैं कि तो उनसे केवल पाटन का क्षतिकारी प्रभाव समाप्त होगा और उनमें क्षति या पाटन मार्जिन से आगे किसी संरक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है और उससे आयात प्रभावित नहीं होंगे और उपभोक्ता तब भी संबद्ध देशों से अपाटित कीमतों पर आयात कर सकते हैं।

71. प्रतिवादी पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि वर्ष 2014 में जीएनएफसी का संयंत्र बंद होने का सामना कर रहा था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा उल्लिखित ऐसी अवधि जांच अवधि से बाहर है और इसे न तो किन्हीं तथ्यों से प्रमाणित किया गया है और न ही यह पता लगाया गया है कि जांच अवधि के दौरान दावा की गई क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण नहीं हुई है और यह केवल आरोपित संयंत्र के बंद होने के कारण हुई है। विभिन्न प्रतिवादी पक्षकारों ने यह भी उल्लिखित किया है कि याचिकादाता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि कंपनी ने स्थिरीकरण के मुद्दों और साथ ही तकनीकी मुद्दों आदि का सामना

किया था और ऐसे दावों का विस्तार से जांच करने पर पता चला है कि प्रतिवादी पक्षकार यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि पाटन क्षति का कारण नहीं था और दावा की गई क्षति ऐसे अन्य कारणों से हुई है।

72. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर संबंधित नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार विचार किया है।

संचयी निर्धारण

73. पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध-II (ii) और विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 में यह प्रावधान है कि यदि कहीं एक से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटन-रोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।

74. प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि :

(क) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों में विहित निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

(ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा आयातों की कुल मात्रा से अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल सीधे उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि वे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा बेची जा रही वस्तु के समान वस्तु हैं।

75. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी आकलन करना उचित होगा।

छ. 2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग और बाजार हिस्सा

76. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच और इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। प्राधिकारी ने भारत में आयातों पर डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों के अनुसार सभी स्रोतों से भारत में पीयूसी के आयातों की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए विचार किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

(1) मांग

(2)

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| मांग | मी.टन | 49,531 | 51,168 | 57,121 | 64,398 |
| सूचीबद्ध | प्रवृत्ति | 100.00 | 103.30 | 115.32 | 130 |
| संबद्ध देशों से आयात | मी.टन | 30,097 | 32,171 | 37,232 | 32,115 |
| अन्य देशों से आयात | मी.टन | 2,438 | 1,983 | 1,319 | 122 |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | मी.टन | 16,997 | 17,014 | 18,570 | 32,161 |

मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा

77. विभिन्न स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयातों और भारतीय उत्पादक की संबद्ध वस्तु की बिक्री पर विचार करते हुए मांग निर्धारित की गई और भारत में इस मांग में संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और अन्य आयातों के बाजार हिस्से की भी जांच की गई और इस संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|------------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| घरेलू उद्योग की बिक्री | % | 34.32 | 33.25 | 32.51 | 49.94 |
| संबद्ध देशों से आयात | % | 60.76 | 62.87 | 65.18 | 49.87 |
| अन्य देशों से आयात | % | 4.92 | 3.88 | 2.31 | 0.19 |

78. उक्त तालिकाओं से यह देखा जाता है कि क्षति अवधि और समस्त जांच अवधि में देश में उत्पाद की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। इस प्रकार मांग में कोई गिरावट दृष्टिगत नहीं हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा जो कि आधार वर्ष और तात्कालिक विगत वर्ष के बीच 30 से 35% के बीच था, जांच अवधि में बढ़ कर 49.94% हो गया, जबकि संबद्ध देशों से आयात, आधार वर्ष में 60% के स्तर से घट कर जांच अवधि में 49.84% रह गए।

79. इस प्रकार क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों का बाजार का हिस्सा भी जांच अवधि के दौरान मांग में लगभग 50% बना हुआ था, हालांकि आधार वर्ष में उसमें गिरावट आई थी।

ख. आयात मात्रा और संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा

80. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण किया गया है।

81. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त कारोबार-वार आयात के आकड़ों के अनुसार संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा की जांच की है। प्राधिकारी ने अनंतिम जांच परिणामों के लिए उन पर भरोसा किया है। रिकार्ड में आयातों आकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से आयात मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक पाई गई है। संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात मात्रा निम्नानुसार दी गई है : -

| विवरण | | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|--------|----------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| मात्रा | | मी. टन | | | | |
| | चीन जन. गण. | | 5,729 | 6,738 | 8,572 | 6,724 |
| | जापान | मी. टन | 8,017 | 9,190 | 12,322 | 8,913 |
| | कोरिया गणराज्य | मी. टन | 16,351 | 16,243 | 16,339 | 16,479 |
| | संबद्ध देश कुल | मी. टन | 30,097 | 32,171 | 37,232 | 32,115 |
| | अन्य देश | मी. टन | 2,438 | 1,983 | 1,319 | 122 |
| | कुल आयात | मी. टन | 32,534 | 34,154 | 38,551 | 32,237 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| आयातों में बाजार हिस्सा | चीन जनवादी गणराज्य | % | 17.61 | 19.73 | 22.23 | 20.86 |
| | जापान | % | 24.64 | 26.91 | 31.96 | 27.65 |
| | कोरिया गणराज्य | % | 50.26 | 47.56 | 42.38 | 51.12 |
| | संबद्ध देश | % | 92.51 | 94.19 | 96.58 | 99.62 |
| | अन्य देश | % | 7.49 | 5.81 | 3.42 | 0.38 |

82. आधार वर्ष में संबद्ध देशों से आयात 30097 मी.टन थे जो कि जांच अवधि में बढ़ कर 32115 मी.टन हो गए। इस प्रकार संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है।

83. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तु के आयात प्राथमिक रूप से संबद्ध देशों से हो रहे थे। संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा, समग्र रूप से बढ़ा है और यह जांच अवधि सहित समस्त क्षति अवधि में भारत में कुल आयातों का 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। वास्तव में, संबद्ध देशों से आयात, जांच अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों का लगभग 99.62% भाग बने रहे हैं।

(ग) उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों का हिस्सा

84. उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों के हिस्से से संबंधित संबद्ध सूचना निम्नानुसार है:

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| संबद्ध देशों से आयात | मी. टन | 30,097 | 32,171 | 37,232 | 32,115 |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन | मी. टन | 17,875 | 16,317 | 23,737 | 45,680 |
| घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात | % | 168.38% | 197.17% | 156.85% | 70.31% |
| भारत में खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात | % | 60.76 | 62.87 | 65.18 | 49.87 |

85. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में उसमें गिरावट आई है।

1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

86. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है :

"नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के कारण कीमतों का अत्यधिक ह्रास हुआ है अन्यथा कीमत वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती।"

87. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद के पाटित आयातों से पर्याप्त मात्रा में कीमतों में गिरावट आई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव कीमतों में पर्याप्त मात्रा में अन्यथा गिरावट के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकते हैं, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत में गिरावट और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सीओपी) और भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना नीचे समुचित खंडों में संबद्ध देशों से आयातों की पंहुच लागत के साथ की गई है।

(क) कीमत में कटौती

88. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली के साथ आयातों की पहुँच कीमत की तुलना की है। इस संबंध में उत्पाद के पहुँच मूल्य और सभी छूटों और करों को मिलाकर व्यापार के उसी स्तर पर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थी। घरेलू कीमतों और कीमतों में कटौती का मार्जिन नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

| विवरण | यूनिट | चीन जनवादी गणराज्य | जापान | कोरिया गणराज्य | संबद्ध देश |
|----------------------|------------|--------------------|--------|----------------|------------|
| पहुँच मूल्य | रू./किग्रा | 123.92 | 111.57 | 110.05 | 113.37 |
| निबल बिक्री प्राप्ति | रू./किग्रा | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती | रू./किग्रा | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती | % | (18.35) | (9.30) | (8.05) | (10.75) |

(ख) सहयोगी निर्याताकों द्वारा कीमत में कटौती

| विवरण | यूनिट | हानवा | बीएसएफ |
|----------------------|------------|--------|--------|
| पहुँच मूल्य | रू./किग्रा | *** | *** |
| निबल बिक्री प्राप्ति | रू./किग्रा | *** | *** |
| कीमत कटौती | रू./किग्रा | *** | *** |
| कीमत कटौती | % | (6.35) | (6.97) |

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से कीमत कटौती नकारात्मक रही है।

(ग) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

90. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में गिरावट आ रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में दबाव पड़ रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोक रहा है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में होती, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान कीमत लागतों व कीमतों में बदलावों पर विचार किया है। वास्तविक स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है :

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| उत्पादन लागत | रू./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 111 | 137 | 123 |
| बिक्री कीमत | रू./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 81 | 60 |
| पहुँच मूल्य (संबद्ध देश) | रू./किग्रा. | 166.73 | 162.17 | 153.64 | 113.37 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 97 | 92 | 68 |

91. उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि उत्पादन लागत में आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से पीओआई में 123 बिंदुओं की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं की तुलना में 60 सूचीबद्ध बिंदुओं का बदलाव हुआ है। इसी अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत, मूल वर्ष में 100 बिंदुओं से घट कर जांच अवधि में 68 बिंदु हो गई है, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से समानता बनाए रखने के लिए बिक्री कीमत को कम कर दिया था। कीमत ह्रास होने का इस तथ्य से पता चलता है कि घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के समनुरूप अपनी कीमतों को बढ़ाने में समर्थ नहीं हो सका था। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत विगत अवधि की कीमतों से निम्न स्तर तक घटा दिया गया था, जिससे कीमत ह्रास का पता चलता है। इनके आधार पर यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का प्रभाव डाल रही थी।

ज. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

92. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-11 में उल्लिखित प्रावधान में क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच करना निहित है। इसके अतिरिक्त नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का तथ्य परका और निष्पक्ष जांच करना शामिल है, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनमें बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता भी शामिल है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करने से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

क. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

93. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:—

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| क्षमता मी.टन | मी.टन | 14,000 | 14,000 | 64,000 | 64,000 |
| उत्पादन | मी.टन | 17,875 | 16,317 | 23,737 | 45,680 |
| क्षमता उपयोग | % | 127.68 | 116.55 | 37.09 | 71.38 |

94. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2014-15 में प्रभावशाली ढंग से क्षमता का संवर्धन किया था और उसके बाद जांच अवधि के दौरान उसकी क्षमता स्थिर बनी रही है।

95. तथापि, घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट दृष्टिगत हुई है। घरेलू उद्योग मूल वर्ष अर्थात् 2012-13 में 127.68% तक श्रेष्ठ क्षमता उपयोग कर सका है। लेकिन जांच अवधि के दौरान उसकी क्षमता उपयोग 71.38% तक घट गया है।

96. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उत्पादन में वृद्धि को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि जांच अवधि के दौरान उसकी क्षमता उपयोग अनुकूलतम स्तर से 71.38% तक के निम्न स्तर पर बना रहा है। यदि जांच अवधि में पाटन नहीं होता तो घरेलू उद्योग समग्र भारतीय मांग को पूरा कर सकता था। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि हालांकि मूल वर्ष की तुलना में उसके क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी सहयोजित कीमत प्राचलों ने गिरावट दर्शाई है और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे हुए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार उसके ऐसे लाभ नकारात्मक हो गए हैं, जो कि उसे क्षमता और उत्पादन में हुई वृद्धि से हो सकते थे।

ख. बिक्रियों की मात्रा और बाजार का हिस्सा

97. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा और बाजार का हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| घरेलू बिक्री | मी.ट. | 16,997 | 17,014 | 18,570 | 32,161 |
| मांग | मी.ट. | 49,531 | 51,168 | 57,121 | 64,398 |
| मांग में घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा | % | 34.32 | 33.25 | 32.51 | 49.94 |

98. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। बिक्रियों की प्रवृत्ति क्षमता और उत्पादन के साथ-साथ उत्पाद की मांग में देखी गई है। हालांकि घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा आधार वर्ष में 34.32% से बढ़ कर जांच अवधि 49.94% हो गया है, जांच अवधि में मांग में संबद्ध देशों के आयातों के बाजार का हिस्सा लगभग 49.87% बना रहा है। घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों के विद्यमान होने के कारण मांग में वृद्धि के समुत्तरूप संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियां बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाया है।

99. इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमता का संवर्धन करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग घटी हुई और अलाभप्रद कीमतों पर अधिक बिक्री करने में सक्षम हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव पैदाकर जांच अवधि के दौरान उसके बाजार के हिस्से को लगभग 50% पर बनाए रखा है, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि घरेलू उद्योग उत्पादन की अपनी लागत से निम्नतर स्तर पर बिक्री करनी पड़ी थी।

ग. मालसूचियां

100. घरेलू उद्योग के पास औसत स्टॉक के रूप में मालसूचियों की स्थिति निम्नानुसार है :

| | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| औसत स्टॉक | मी.टन | 748 | 776 | 1,625 | 2,107 |

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास संचयी माल-सूचियां पड़ी हुई थीं। आधार वर्ष की तुलना में माल सूचियों के स्तर में वृद्धि हो रही है और जांच अवधि के दौरान यह उच्चतम स्तर पर बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि जबकि उसी अवधि में मांग और उत्पादन में वृद्धि हो रही है, माल सूचियों में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव का पता चलता है।

घ. लाभ/हानि

102. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|-------|------------|---------|---------|---------|-----------|
| लाभ | रु/किग्रा. | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|------|-------|
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 48 | (89) | (133) |
| लाभ | लाख रुपये | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 48 | (98) | (249) |

103. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के संबंध में वित्तीय घाटे हुए हैं। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान घरेलू उद्योग को लाभ अर्जित हो रहा था। उपरोक्त से यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमतें उसी अवधि में घरेलू कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव डाल रही थीं, जो कि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के समनुरूप अपनी बिक्री कीमतों को बढ़ाने में समर्थ नहीं था। यह देखा गया है कि पाटित आयातों के कारण जांच अवधि में उसकी लागत, 100 आधार बिन्दु से बढ़ कर 123 बिन्दु हो गई है, जबकि पाटित आयातों के कारण जांच अवधि में उसकी बिक्री कीमत, 100 आधार बिन्दु से घट कर 68 बिन्दु हो गई है। घरेलू उद्योग को हुए वित्तीय घाटों से पाटित आयातों के प्रभाव का पता चलता है।

ङ. नियोजित पूंजी पर आय

104. नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है :

| | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| नियोजित पूंजी पर आय | % | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 51 | (6) | (21) |

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि में भारी गिरावट आई है और जांच अवधि में यह नकारात्मक हो गई है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान घरेलू उद्योग अपनी नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ को सकारात्मक स्तर पर बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन पाटित आयातों से पड़े प्रतिकूल कीमत प्रभाव के कारण उसकी लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट आ गई।

च. नकदी प्रवाह

106. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति पर पाटन के प्रभाव की जांच करने के लिए नकद लाभों की प्रवृत्ति की जांच की है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ संबंधी सूचना नीचे तालिका में दी गई है :

| | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| नकद लाभ | लाख रुपये | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 59 | (53) | (149) |

107. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के नकद लाभ में क्षति अवधि में कमी आई है और पीओआई में आधार वर्ष की तुलना में वह नकारात्मक हो गया है। नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

108. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों से भिन्न अन्य कारकों आदि जो कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम रहा है, जिसके कारण भारतीय बाजार में अत्यधिक कीमत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त आधार वर्ष की तुलना में बिक्री कीमत में भी गिरावट आई है, जो कि कीमत ह्रास दर्शाता है। इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य है। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में याचिकादाता

भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र अकेला उत्पादक है, जो कि भारत के भीतर उत्पादकों के बीच पारस्परिक अनुचित प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से वर्जित करता है। जांच अवधि के दौरान लागत ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लागत में गिरावट आई है।

109. यह एक तर्क रहा है कि टीडीआई की वैश्विक कीमतें जांच अवधि के दौरान सबसे निम्नतर रही हैं। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि स्वतः वैश्विक कीमतों में गिरावट आने से पाटन के कारण घरेलू उद्योग की क्षति होती है, से मनाही नहीं की जा सकती है। ऊपर यह देखा गया है कि कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण होने से ऐसे पाटित आयातों के फलस्वरूप लाभप्रदता और नियोजित पूंजी में गिरावट आई है।

ज. उत्पादकता

110. उत्पादकता से संबंधित सूचना नीचे तालिका में दी गई है:-

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता | मी.टन/संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 87 | 29 | 56 |
| प्रतिदिन उत्पादकता | मी.टन/दिन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 133 | 256 |

111. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट दृष्टिगत हुई है, हालांकि तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष में उसमें वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि जांच अवधि में प्रति दिन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आने का कारण पाटित आयातों के कारण जांच अवधि में क्षमता का उपयोग नहीं किया जाना है। यदि कोई पाटन नहीं हुआ होता, तो उत्पादन और परिणामी उत्पादकता में वृद्धि होती।

झ. रोजगार और मजदूरी

112. रोजगार और मजदूरी से संबंधित सूचना नीचे तालिका में दी गई है:-

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|-----------|------------|---------|---------|---------|-----------|
| रोजगार | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 104 | 459 | 459 |
| मजदूरी | रु/किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 104 | 208 | 185 |

113. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और साथ ही क्षमता में संवर्धन देखा गया और जांच अवधि में ये दोनों समान बने रहे हैं। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वेतन प्रति किलोग्राम में वृद्धि हुई है और तात्कालिक विगत वर्ष में उसमें गिरावट आई है। साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी वेतन में वृद्धि हुई है लेकिन मामूली। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि पाटित आयातों के कारण क्षमता का कम उपयोग और कम अनुकूलतम उत्पादन होने के फलस्वरूप प्रति उत्पादन वेतन का उच्चतर घटक हो सकता है, लेकिन प्रति कर्मचारी वेतन में वृद्धि बहुत मामूली थी। घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि उसके पास देश में अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है अर्थात् बाजार में समानान्तर अवसर प्राप्त होने पर संबद्ध वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने की क्षमता है।

ब. संवृद्धि

114. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की संवृद्धि, विक्री कीमत, लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ आदि जैसे अनेक प्रमुख प्राचलों में नकारात्मक रही है। ऐसी नकारात्मक संवृद्धि तब देखी गई है, जब कि उत्पाद की मांग ने सुसंगत संवृद्धि दर्शाई है।

ट. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, इन निवेशों और क्षमता में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में काफी कमी आई है और यदि संबद्ध वस्तु के पाटन का समाधान नहीं किया तो आगे निवेश प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे।

ठ. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

116. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन काफी अधिक है।

ड. क्षति संबंधी निष्कर्ष

117. विभिन्न क्षति प्राचलों की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पूर्णरूपेण पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। ऐसे पाटित आयात जांच अवधि के दौरान घरेलू मांग का लगभग 50% भाग बनते हैं। इस प्रकार आयातों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है और ये जांच अवधि के दौरान भारत में खपत का पर्याप्त भाग बनते हैं।

118. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। पाटित आयातों ने कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के रूप में कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पाटित आयातों के प्रभाव से संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों में गिरावट आई है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को ऐसी बाजार कीमत पाने के लिए विवश किया है, जो कि घरेलू उद्योग की लागत भी वसूल नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे वित्तीय घाटे हुए हैं।

119. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने क्षमता उपयोग, माल सूचियों, लाभ, नकदी लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ अत्यधिक प्रभावित हुआ है। ऐसा इस तथ्य से पता चलता है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2013-14 तक अच्छा लाभ और प्रतिलाभ अर्जित कर रहा था। लेकिन जांच अवधि के दौरान उसका लाभ और प्रतिलाभ नकारात्मक रहा है। हालांकि उसकी क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि हुई है, लेकिन जांच अवधि के दौरान उसकी क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जो कि प्रत्यक्षतः घरेलू मांग में पाटित आयातों के लगभग 50% हिस्से के प्रभाव के कारण हो सकती है। यदि ऐसे पाटित आयात नहीं होते, तो घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन और बिक्री कर सकता था। इस प्रकार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ड. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

120. कारणात्मक संबंध के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/प्रयोक्ताओं/आयातकों आदि द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) याचिकादाता द्वारा अचानक और पर्याप्त रूप से क्षमता में संवर्धन करने, वर्ष 2014 में संयंत्र को बंद करने, जैसा कि याचिकादाता की वार्षिक रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है, अंतरभूत स्थापनात्मक समस्याएं होने, याचिकादाता द्वारा किए गए सस्ते निर्यात और इनके अतिरिक्त निर्यातों में अचानक लगभग 4 गुना वृद्धि करने जैसे कारणात्मक संबंध की जांच करते समय आधार वर्ष पर विचार किया जाना चाहिए। इन कारकों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और उसकी लाभ प्रदता प्रभावित हुई है।
- (2) याचिकादाता को क्षति निर्यात बाजार में हुए उसके घाटों के कारण हुई है। जबकि याचिकादाता घरेलू बाजार में कीमत ह्रास का दावा कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा निर्यात बाजार में सस्ती कीमतों/कम कीमतों पर वस्तुओं को बेचे जाने का कोई कारण नहीं है। तथापि, अंतरभूत कारणों के साथ-साथ विश्व बाजार में टीडीआई की कम बिक्री कीमत को स्वीकार करते हुए याचिकादाता के उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण याचिकादाता ने घाटे के आधार पर पर्याप्त भाग में अपनी निर्यात बिक्रियां की हैं।
- (3) संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आवेदन पत्र मात्रा में वृद्धि की सार्थकता का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा है क्योंकि संबद्ध आयातों का घरेलू कीमतों पर कोई विशेष कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है और घरेलू कीमतें मुख्यतया मुख्य कच्चे माल की कीमतों में गिरावट होने से प्रभावित हुई थीं और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और घरेलू उद्योग की स्थिति के लिए संबद्ध आयातों का कोई स्पष्टतया बल नहीं है। क्षमता में ऐसी वृद्धि होने, कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आदि का गैर-आरोपण विश्लेषण, क्षति के अन्य कारकों को पृथक् करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है, जो कि नहीं किया गया है।

- (4) मात्रा अथवा कीमत प्राचलों के रूप में आरोपित पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। कोई भी क्षति कुप्रबंधन और लागत कारक की अकुशलता के कारण हुई है।
- (5) यह प्रतीत होता है कि यदि कोई क्षति हुई है, तो उसके लिए केवल अन्य कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अन्य कारणों से हुई किसी क्षति के लिए संबद्ध देशों से आयातों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग की मात्रा अथवा कीमत के प्राचलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।
121. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (1) वर्तमान मामले में पाटन अत्यधिक है और घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है और ऐसी क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण हुई है।
- (2) यदि कोई पाटन नहीं हुआ होता, तो जांच अवधि में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होती। पाटित आयातों ने ग्राहकों को उत्पादन की लागत तक प्राप्त करने से रोका है और इसके परिणाम स्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, विभिन्न प्राचलों में संवृद्धि आदि नकारात्मक हो गई है।
- (3) मात्रा और मूल्य के प्राचलों को संयोजित करने से घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के बृहत प्रभाव पड़ने का पता चलता है।
- (4) प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि क्षमता विस्तार संबंधी व्यय के कारण क्षति हुई है। यह तर्क सही नहीं है। क्षमता का विस्तार वर्ष 2014-15 में किया गया था और घरेलू उद्योग जांच अवधि शुरू होने से पहले नए संयंत्र शुरू होने के साथ जुड़े मुद्दों से निपटने में सक्षम था। इस प्रकार जांच अवधि में हुई क्षति क्षमता विस्तार होने के कारण नहीं हुई है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसके विपरीत निर्यातकों ने अकेले भारतीय उत्पादक द्वारा क्षमता विस्तार किए जाने पर स्वतः प्रारंभिक चरण में आक्रामक पाटन करने की अपनी प्रतिक्रिया से घरेलू उद्योग को विस्थापित करने का प्रयास किया है और इस प्रकार निर्यातक आयातों के सहारे से घरेलू उद्योग को अत्यधिक हानि पहुंचा सकते हैं।
- (5) प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि क्षति का कारण वर्ष 2014 में संयंत्र का बंद हो जाना हो सकता है। संबंधित क्षति वर्ष 2015-16 (जांच अवधि) में हुई है और न कि वर्ष 2014 में। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो क्षति वर्ष 2015-16 में हुई है, वह वर्ष 2014-15 में आरोपित संयंत्र के बंद होने के कारण हुई है और न कि जांच अवधि में पाटन के कारण।
- (6) प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि क्षति का कारण स्थापना के साथ जुड़ी अंतरभूत समस्याएं हो सकती हैं, जैसा कि जीएनएफसी की वार्षिक रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है। प्रतिवादी पक्षकारों ने वार्षिक रिपोर्ट में परिचर्चाओं की कुछ "चैरी पिकिंग" की है। वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को विकृत करती हो।
- (7) प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा सस्ते निर्यात किए जाने के कारण क्षति हुई है। यह सही नहीं है। निर्यातकों की सूचना पृथक से दी गई है और दावा की गई क्षति केवल घरेलू बिक्रियों से संबंधित है। वास्तव में घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में भी संबद्ध देशों से निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। किसी भी स्थिति में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त निर्यात किए गए थे। अन्यथा उसकी क्षमता उपयोग और भी निम्नतर बना रहता जिसके फलस्वरूप उच्च निश्चित लागतें आती। यदि ऐसे कोई निर्यात नहीं किए गए होते, तो काफी अधिक क्षमता निष्क्रिय रहती जिसके फलस्वरूप उच्च लागतें आती।
122. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य कारक, जो पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध हैं, ने घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान दिया है। संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की गई है, जो इस प्रकार हैं:

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

123. संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से आयात मात्रा के संदर्भ में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति की आशंका हो। अन्य देशों से आयात कुल 0.5 प्रतिशत हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयात क्षति पहुंचा रहे हैं।

(ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा

124. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का एक बाजार है जिसमें संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों के लिए प्रयुक्त होती हैं। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से क्षति होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ग) मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की मांग में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कारण नहीं हो सकता।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

126. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी खास परिवर्तन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

127. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात के व्यौरे निम्नानुसार हैं :

| विवरण | यूनिट | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | जांच अवधि |
|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| निर्यात | मी.टन | 120 | शून्य | 2,714 | 14,947 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | - | - | 100 | 429 |

128. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभव महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण है। वास्तव में घरेलू उद्योग के निर्यातों में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। अतः निर्यात कार्य निष्पादन में संभावित गिरावट किसी क्षति का कारण नहीं है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

129. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

(छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन

130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के निष्पादन के लिए किए गए आकलन पर प्रभाव द्वारा विचार की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

झ. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

131. घरेलू उद्योग के निष्पादन का क्षति अवधि के दौरान का विश्लेषण यह दर्शाता है कि क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तव में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण गिरावट आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधार पर सिद्ध होता है:-

- (क) संबद्ध वस्तुओं के आयात में जांच की समग्र अवधि के दौरान सापेक्ष अर्थों में वृद्धि हुई है।
- (ख) भारत में पाटित आयातों के बाजार का हिस्सा जांच अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत बना रहा है, जो पर्याप्त प्रतिशत है और उसने भी घरेलू उद्योग को अधिक उत्पादन और बिक्री करने से रोका है, जो कि ऐसे पाटित आयातों की अनुपस्थिति में हो सकती थी।
- (ग) जांच अवधि के दौरान जबकि मांग बढ़ रही थी, घरेलू उद्योग के पास अत्यधिक अनप्रयुक्त क्षमता विद्यमान थी।
- (घ) घरेलू उद्योग की माल-सूचियों में वृद्धि हुई है।
- (ङ) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर अत्यधिक कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण होने का प्रभाव पड़ा है।
- (च) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2013-14 तक नियोजित पूंजी पर पर्याप्त लाभ और प्रतिलाभ प्राप्त करता रहा था। लेकिन जांच की अवधि के दौरान ये नकारात्मक रहे हैं।

132. उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण वास्तव में क्षति का सामना करना पड़ रहा है। संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक सशक्त कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ठ. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

133. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-3 के साथ पिठत पाटन-रोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण, जांच अवधि के दौरान उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना करके किया गया है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण संयंत्र-वार किया गया है और तदनुसार, भारित औसत क्षति रहित कीमत तय की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करके भारित औसत क्षति रहित पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त सामग्री के बेहतर उपयोग पर विचार किया गया है। प्रयोज्यताओं के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग पर विचार किया गया है। जांच अवधि में उत्पादन का परिकलन, बेहतर क्षमता उपयोग को ध्यान में रख कर किया गया है और प्रति यूनिट निश्चित लागत प्राप्त करने के लिए उसी उत्पादन पर विचार किया गया है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय प्रभावित नहीं किया जाए। विचाराधीन उत्पाद पर नियोजित औसत पूंजी पर उचित प्रतिलाभ (कर पूर्व 22% की दर से) (अर्थात औसत निबल निश्चित परिसम्पतियों जमा औसत भारित पूंजी), कर-पूर्व लाभ मंजूर किया गया है, ताकि क्षति रहित कीमत प्राप्त की जा सके, जैसा कि अनुबंध-3 में परिभाषित किया गया है और जिसका अनुपालन किया जा रहा है। इस प्रकार निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है, ताकि क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा सके, जो निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | देश | उत्पादक | निर्यातक | क्षति रहित कीमत - अम.डा./ किग्रा. | पहुंच कीमत - अम.डा./ किग्रा. | क्षति मार्जिन - अम.डा./ किग्रा. | क्षति मार्जिन - % | क्षति मार्जिन सीमा - % |
|---------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | चीन जनवादी गणराज्य | कोई | कोई | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 2 | जापान | कोई | कोई | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 3 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 30-40 |
| 4 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | एवरलाईट कोरिया कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 5 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | आईएमएस कार्पोरेशन | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 6 | कोरिया गणराज्य | हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन | (क) पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. (ख) एवरलाईट कोरिया कं. | *** | *** | *** | *** | 25-35 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | लि. (ग) आईएमएस कार्पोरेशन (घ) टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी | | | | | |
| 7 | कोरिया गणराज्य | बीएसएफ कं. लि. | बीएसएफ कं. लि. | *** | *** | *** | *** | 25-35 |
| 8 | कोरिया गणराज्य | उक्त क्र. से. 3 से 7 के उत्पादकों से इतर कोई अन्य उत्पादक | उक्त क्रमांक 3 से 7 के निर्यातकों से इतर कोई अन्य निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 30-40 |

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

134. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियों का सार संक्षेप में नीचे दिया गया है:

क. घरेलू उद्योग के दृष्टिकोण

- मैसर्स हेनकेल एधेसिव्स टेक्नोलॉजीस इंडिया प्रा. लि. द्वारा कुछ उत्पादों को बाहर निकालने की मांग बिना किसी आधार के है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हेनकेल ने प्रारंभ में "खाद्य सुरक्षित एधेसिव्स के विनिर्माण के लिए आयात किए जाने वाले 80:20 के अनुपात में आइसोमर की मात्रा वाले खाद्य सुरक्षित टीडीआई" को बाहर किए जाने का अनुरोध किया है और बाद में "खाद्यान्न संपर्क उपयोग के उद्देश्य से एधेसिव्स में उपयोग किए जाने के लिए यूरोपीय संघ विनियमन 10/2011 के अनुरूप और खाद्य की 0.01 मिलीग्राम/किलोग्राम विशिष्ट प्रवजन मात्रा वाले टीडीआई" को बाहर किए जाने के अनुरोध में बदलाव किया है। हेनकेल ने संबद्ध देशों से अपने आयातों के व्यौरे के बारे में नहीं बताया है और केवल उस उत्पाद को बाहर किए जाने के अनुरोध का सहारा लिया जिनका दावा उनके द्वारा आयात किए गए के रूप में किया गया है। प्राधिकारी प्रकटन विवरण में लिए गए दृष्टिकोण अर्थात् अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद से कुछ उत्पादों को बाहर किए जाने की पुष्टि कर सकते हैं।
- इसे दोहराया जाता है कि हेनकेल द्वारा समग्र तर्क को देखते हुए जो महत्वपूर्ण है वह यह तथ्य है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीडीआई और संबद्ध देशों से भारत में आयात किए गए टीडीआई में कोई अंतर नहीं है। घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए टीडीआई संबद्ध देशों से पाटित किए गए टीडीआई का रासायनिक लक्षणों, प्रयोगों, प्रौद्योगिकी आदि के मामले में समान वस्तु है। इस कारण से विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में, जो पहले दी गई है, उसको छोड़कर कोई अतिरिक्त उत्पाद को बाहर किए जाने की अनुमति इस प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में भी नहीं दी जानी चाहिए।
- घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है और इन तथ्यों के आधार पर पाटनरोधी नियमावली में की गई परिकल्पना के अनुसार इन दोनों के बीच एक कारणात्मक संबंध है।
- हनवा केमिकल कारपोरेशन के लिए कोई अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण उस प्रतिष्ठान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जिसने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में किया है और जिसने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है, वह हनवा फाइन केमिकल कारपोरेशन है और न कि हनवा केमिकल कारपोरेशन। निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में सम्पूर्ण प्रश्नों का उत्तर एचएफसीसी को निर्यातक/उत्पादक के रूप में रखकर किया गया है और ऐसी परिस्थिति में प्राधिकारी के पास एचसीसी को अलग-अलग मार्जिन प्रदान किए जाने के लिए इसके समक्ष कोई सूचना नहीं है।

- v. पाटनरोधी शुल्क अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से भी अमेरिकी डॉलर में निर्धारित की गई तयशुदा मात्रा के संबंध में लगाया जाना चाहिए। यह अनुरोध है कि शुल्क की निर्धारित मात्रा को इस प्राधिकारी द्वारा अधिकांश जांचों में अपनाया गया है और वही रूप सबसे अधिक प्रभावी पाया गया है। टीडीआई जैसे किसी उत्पाद, जिसमें आयात की अधिकांश मात्रा होती है, में शुल्क के किसी अन्य प्रकार को संदर्भ कीमत अथवा उस प्रकार के रूप में लगाया जाता है, पाटनरोधी शुल्क के रूप में किसी उद्देश्यपूर्ण संरक्षण के अनुमानित निवारण संबंधी प्रभावों का गलत अर्थ निकलेगा और सम्पूर्ण प्रयास निष्फल हो सकता है। शुल्क की निर्धारित मात्रा एक न्यूनतम संरक्षण के रूप में कार्य करेगा और एक संदर्भ कीमत रूप से आयातक और निर्यातक किसी शुल्क की कमियों को दूर करने के लिए उन प्रथाओं को अपनाने में भी आसानी से सक्षम होंगे। घरेलू उद्योग को पाटन के कारण पहले ही गंभीर वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है और अमेरिकी डॉलर में निर्धारित मात्रा को छोड़कर किसी अन्य रूप में शुल्क से क्षतिकर पाटन से इसकी वसूली नहीं हो पाई।
- vi. जांच की अवधि के पश्चात के कार्य निष्पादन का एक नई जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों की जांच करना विशेष रूप से संदर्भ कीमतों की वकालत करने का अनुरोध एक नई जांच की आवश्यकताओं के संदर्भ में उचित नहीं है। प्राधिकारी की यह एक सतत प्रथा रही है कि एक नई जांच में जांच की अवधि के पश्चात के कार्य निष्पादन की जांच नहीं की जाए। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में हुए घटनाक्रमों की जांच का प्रावधान करार में है और किसी बिल्कुल नई जांच में जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों पर विचार करने से अपरिपक्व और गलत निष्कर्ष निकल सकता है। पाटनरोधी करार में इस स्थिति की पहचान और इसका समर्थन विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय द्वारा किया गया है और हम उसी पर अपना भरोसा करते हैं। संबंधित एबी रिपोर्ट के उद्धरण नीचे संलग्न किए गए हैं:

"81. हमारे दृष्टिकोण से, पाटनरोधी करार में जांच करने वाले प्राधिकारियों को उनके व्यक्तिपरक विचारों के अनुसार जांच की अवधि की उप अवधियों अथवा आंकड़ों के उप समुच्चय को अपने विवेक से चुनने की अनुमति न देकर बल्कि समीक्षा तंत्र के माध्यम से ऐसे प्रमुख परिवर्तनों की संभावना पर विचार किया जाता है, जो जांच की अवधि के बाद के चरण में अथवा जांच की अवधि के बाद भी होता है। पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.1 इस मामले में स्पष्ट है कि "(क) पाटनरोधी शुल्क तभी तक लागू रहेगा और उसी सीमा तक लागू रहेगा, जो पाटन को दूर करने के आवश्यक होगा जिससे क्षति हो रही हो।" इस सामान्य नियम को आगे बढ़ाते हुए, अनुच्छेद 11.2 में कुछ परिस्थितियों में, जिसमें "शुल्क के सतत आरोपण के लिए आवश्यकता की समीक्षा" करने के लिए एक उचित समय अवधि के बाद किसी हितबद्ध पक्षकार का अनुरोध शामिल है" जांच करने वाले प्राधिकारियों की अपेक्षा है। अनुच्छेद 9.3 के उप पैराग्राफ 1 में पाटनरोधी करार में इस बात का भी निर्धारण किया गया है कि वसूला गया पाटनरोधी शुल्क किसी भी समय पाटन मार्जिन से अधिक नहीं होगा और यह कि वसूली गई ऐसी कोई भी अधिक राशि को वापस किया जाएगा। इस कारण से, यदि जांच की अवधि तथा उसके बाद कोई प्रमुख परिवर्तन होता हो, जिससे पाटन के मार्जिन में कटौती हुई हो अथवा पाटन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया हो, तब पाटनरोधी करार के ये प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्यातक के कानूनी हितों की रक्षा की जा सके।" (यूरोपियन समुदाय – ब्राजील से मेलेयेबल कास्ट आयरन क्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स पर पाटनरोधी शुल्क – डब्ल्यूटी/डीएल219/एबी/आर दिनांक 22 जुलाई, 2003)

- vii. प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध है। यह भारत में संबद्ध वस्तुओं के इस प्रकार के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना अनिवार्य कर देता है। इसके अलावा, हम प्राधिकारी से लगाए गए अंतिम शुल्कों की पुष्टि तथा अमेरिकी डॉलर में तय की गई मात्रा के मामले में अंतिम शुल्क की सिफारिश करने का भी अनुरोध करते हैं।

ख) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण

- i. पाटनरोधी महानिदेशक ने हनवा फाइन केमिकल की एसजीएंडए तथा वित्तीय लागत को छोड़कर 11 महीने के लिए उत्पादन की लागत पर विचार किया है और जांच की अवधि के एक माह के लिए हनवा केमिकल कारपोरेशन की उत्पादन की लागत पर ध्यान नहीं दिया है। पाटनरोधी महानिदेशक ने सीओपी के निर्माण के लिए एक महीने के लिए हनवा केमिकल कारपोरेशन की एसजीएंडए तथा वित्तीय लागत पर विचार किया है।

- ii. कैलेंडर वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता के उत्पादन की सुविधा को एक साल तक बंद होने के तथ्यों, जिसके कारण भारतीय मांग और भारतीय आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने के लिए आयात अपेक्षित था, पर विचार नहीं किया गया है।
- iii. प्राधिकारी को क्षति के विश्लेषण के लिए केवल पुराने संयंत्र पर विचार करना चाहिए क्योंकि नए संयंत्र के कारण स्पष्ट रूप से कार्यक्षमताओं में कमी आई है।
- iv. कीमत ह्रास/कीमत पर दबाव के संदर्भ में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित था कि वे इस तथ्य का आंकलन करें कि क्या प्राधिकारी द्वारा देखी गई याचिकाकर्ता की कीमतों में गिरावट का कारण संबद्ध वस्तुओं का आयात ही था। याचिकाकर्ताओं की क्षमताओं का आवश्यकता से कम उपयोग का कारण इसकी कार्यक्षमता में अंतर्निहित कमियां हैं और यह किसी भी रूप में संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हो सकता है।
- v. कुछ बिन्दुओं पर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दावे को इसके अपने आंकलन पर विचार किए बिना बार-बार दोहराया है। प्राधिकारी इन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं।
- vi. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई कथित क्षति और संबद्ध देशों से कथित रूप से पाटित आयातों के बीच एक स्पष्ट और सांकेतिक कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया है। 2014 में अचानक और पर्याप्त मात्रा में क्षमता का विस्तार, याचिकाकर्ता के संयंत्र का बंद होना, स्थापना की अंतर्निहित समस्याएं आदि क्षति का कारण हैं और कारणात्मक संबंध के संदर्भ में इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- vii. प्राधिकारी अवश्य नोट करें कि वर्तमान जांच की अनोख तथ्यात्मक स्थितियों को देखते हुए शुल्क का केवल उपयुक्त रूप ही शुल्क का निर्धारित रूप है।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता, जिसमें डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात संबंधी आंकड़े शामिल हैं, के संबंध में विभिन्न अनुरोधों का समाधान अंतिम जांच परिणाम में किया जा सकता है।
- ix. प्राधिकारी चीन के निर्यातकों के लिए उनके रिकार्डों के आधार पर और न कि संरचित सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।
- x. यह पुनः दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और वर्तमान जांच में कारणात्मक संबंध का अभाव है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (ii) के प्रावधानों को देखते हुए, घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वह सर्वप्रथम यह सिद्ध करे कि जांच की अवधि में पर्याप्त मात्रा में आयातों में वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया जाता है कि सीमाओं में कीमत में कटौती को वर्तमान जांच में गोपनीय रखा गया है जबकि अन्य सभी जांचों में सीमाओं में उसका खुलासा किया गया है। हम अंतिम जांच परिणामों में उनके प्रकटन का अनुरोध करते हैं।
- xi. घरेलू कीमतें संबद्ध आयातों की कीमतों की तुलना में स्वयं अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं और आयात की कीमतों का घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान जांच को कृपया इस आधार पर भी समाप्त किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन – ग्रेन उन्मुख फ्लैट रोलड इलैक्ट्रिकल स्टील में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग के लिए यह अपेक्षित है कि वह इस संबंध में कारण बताए कि किस प्रकार से कीमत की प्रवृत्ति की भूमिका घरेलू कीमतों को प्रभावित करने में रही है।
- xii. घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि कार्यक्षमता में इसकी कमी और इसके अस्थायित्व के कारण जांच की अवधि के अधिकांश भाग के दौरान इसके संयंत्र का बंद होना है। घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वह यह दर्शाए कि घरेलू कीमतों में कटौती पाटित आयातों के प्रभाव के कारण हुई है।
- xiii. ह्रास, ब्याज और मजदूरी की लागत में क्षति की जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस कारण से संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि के कारण 50,000 मीट्रिक टन तक घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप ह्रास, ब्याज, मजदूरी और अतिरिक्त खर्च की लागत में वृद्धि है।
- xiv. यह अनुरोध किया जाता है कि अन्य कारकों, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, का वर्तमान जांच में विश्लेषण नहीं किया गया है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति जैसे कारक क्षमता में वृद्धि, इसके संयंत्रों में से एक संयंत्र

की अस्थिरता के कारण लागत में वृद्धि के कारण हुई है, और प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में गिरावट पर इसके लिए विचार किए जाने की आवश्यकता है।

- xv. इस याचिका के अपर्याप्त अगोपनीय पाठ ने समचित खंडन दायर करने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता करने के हमारे अधिकार को बाधित किया है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से वह उद्देश्य और प्रयोजन बाधित हो जाता है जिसके लिए इन हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किए गए थे। इसके फलस्वरूप, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है।
- xvi. अनंतिम शुल्क की सिफारिश द्वारा 9ख की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार नहीं की गई है। तदनुसार, इन सिफारिशों को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया था। प्रकटन विवरण इस संबंध में मौन है कि किस प्रकार से धारा 9ख की पूर्व शर्तों को पूरा किया गया था। उसको देखते हुए यह निवेदन है कि अंतिम जांच परिणाम नियम 20 की आवश्यकताओं के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि नहीं कर सकता है।
- xvii. याचिकाकर्ता यह दर्शाने में सक्षम नहीं हो पाया है कि कोई पाटन हुआ है और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। अनुबंध-II (ii) और (iv) इस प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य कर देता है कि वह निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देश की परिधि में घरेलू उद्योग के संबंध में कथित रूप से पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करें। विस्तृत अनुरोध, जो इन मानदंडों में सुधार को दर्शाते हैं, की पुष्टि किए जाने को दोहराया जाता है।
- xviii. अत्यधिक और अनुमति न दिए जाने योग्य गोपनीयता का दावा किया गया है और इसकी अनुमति निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विशिष्ट न्याय पद्धति के विपरीत दी गई है। इसके अलावा, सहयोग न करने वाले निर्यातकों के संबंध में निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए अपनाई गई पद्धति इस तथ्य के बावजूद गोपनीय रखी गई है कि यह एक स्थापित कानून है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास गोपनीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनुरोधों में से किसी अनुरोध पर कानून की आवश्यकता के मामले में नहीं विचार किया गया है।
- xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सॉफ्ट प्रति में डीजीसीआईएंडएस के अलग-अलग आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं। इस मामले का तर्क रिकार्ड में यह दर्ज नहीं करता है कि इन आंकड़ों की इस प्रकार की सॉफ्ट प्रति के संबंध में किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी पक्षकार ने गोपनीयता का दावा किया था। उसकी आपूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है।
- xx. डीएस 397 यूरोपीय समुदाय – चीन से कुछ लौह अथवा इस्पात फास्टर पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया था जिसने एक प्राधिकारी को "सही कारण का आंकलन करने का दायित्व सौंपा था और यह कि इस अनुरोध की पुष्टि पूर्ण रूप से कर दी गई थी।" उसको उद्धृत करने के सिवाय, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि "संदर्भ कीमत" आधार शुल्क उस स्थिति में सबसे अधिक उपयुक्त शुल्क है जब वर्तमान कार्यवाही को समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया जाता है। शुल्क के रूप में एक तरफा निर्धारण से नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन होगा। शुल्क का बैचमार्क रूप ही वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में शुल्क का उपयुक्त रूप है।
- xxi. हेनकेल ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के विनियमनों को प्रस्तुत किया है जो यह दर्शाता है कि खाद्य संपर्क उपयोगों में इसका प्रयोग किए जाने पर टीडीआई सहित कुछ उत्पादों द्वारा प्रस्तुत खतरे की पहचान करने के लिए एक विशिष्ट विनियमन और मानक सही कारणों से अन्य न्याय क्षेत्र में लागू होते हैं। इन उत्पाद में कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक पदार्थ तथा नैनो अणु हो सकते हैं और इस खतरे को अवश्य ही कम किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, एक वैश्विक और स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में, हेनकेल से यह अपेक्षित है कि वह इन मानदंडों का पालन करे।
- xxii. जीएनएफसी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां यह संगत प्रमाणनों को उपलब्ध कराने तथा अपेक्षित जांच का पालन करने में अपनी असमर्थता के कारण हेनकेल को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति न कर सकता है/नहीं कर पाएगा और अब यह प्रतिवादी पर एक अनुचित बोझ डालना चाहता है जिसमें उन्हें पाटनरोधी शुल्कों का भुगतान करना पड़ सकता है और उसका आयात करना पड़ सकता है। जब जीएनएफसी ने उचित प्रक्रिया के बाद इसे पूरा नहीं किया है, और जहां यह हेनकेल द्वारा अपेक्षित उत्पाद की आपूर्ति करने में स्पष्ट रूप से सक्षम नहीं है/इच्छुक नहीं है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने इस प्रकार के सीमित उत्पाद को बाहर न किए जाने की अनुमति न देकर अत्यधिक भेदभाव किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

135. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्राथमिक रूप में प्रकटन विवरण के संदर्भ में उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति और पुनर्स्थापन हैं। सभी संबंधित प्रतिवादी दृष्टिकोण एवं अनुरोध को अन्य बातों के साथ-साथ इन अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त खंडों में समाधान किया गया है जो संबंधित तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए संबंधित नियमों और न्याय पद्धतियों को देखते हुए भी स्वतः स्पष्ट है। उसके बावजूद, इन पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रकटन विवरण के संबंध में कुछ विशिष्ट टिप्पणियों का समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

- i. एचएफसीसी और एचसीसी के उत्पादन की औसत लागत के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि पीओआई के दौरान, एचसीसी ने किसी विषय वस्तु का निर्यात नहीं किया है, इसलिए उत्पादन की लागत एचएफसीसी के 11 महीने के आंकड़ों के आधार पर गणना की गई है। चूंकि, एचएफसीसी को एचसीसी के साथ विलय कर दिया गया था, इसलिए एसजी और ए खर्चों को विलय की गई कंपनी अर्थात् एचसीसी के लिए माना जाता था ताकि कंपनी की बिक्री की लागत आ सके।
- ii. एचसीसी के इस तर्क के संबंध में कि पाटन/क्षति मार्जिन को औसत आधार पर तय करना उचित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादक/निर्यातक, जिसकी अलग-अलग मार्जिन के प्रयोजन से जांच की गई है, के अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण किया गया है। हालांकि, निर्यातक आधारित शुल्क एचसीसी को बहु मार्जिन दिए जाने के समतुल्य होगा, जो इन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। तदनुसार, भारत औसत पाटन और क्षति का आंकलन किया गया है जो एचसीसी के लिए शुल्क के निर्माण में परिणति पर होगा।
- iii. बीएसएफ के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित वास्तविक स्थितियों और इस प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण की उपेक्षा की है, यह नोट किया जाता है कि इस अंतिम जांच परिणाम में दिए गए अनुसार इस मामले के लिए संबंधित तथ्यों की विभिन्न जांच यह दर्शाती है कि बीएसएफ की टिप्पणी का कोई आधार नहीं है। इस मामले के तथ्यों और सत्यापित सूचना पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की गई है और दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- iv. बीएसएफ के इस तर्क के संबंध में कि कैलेंडर वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता की उत्पादन क्षमता का एक वर्ष तक बंद होना जिसके कारण भारतीय मांग और भारतीय आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए आयात किया जाना अपेक्षित था, पर विचार नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि उल्लिखित अवधि जांच की अवधि से पहले की है। किसी भी मामले में, मांग एवं आपूर्ति का अंतर पाटन के लिए औचित्यपूर्ण कोई कारण नहीं है और यह शुल्क स्वतः आयात के विरुद्ध नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पाटन के केवल क्षतिकारक तत्वों को दूर करने के लिए लगाया गया है।
- v. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को क्षति के विश्लेषण के लिए केवल पुराने संयंत्रों पर विचार करना चाहिए क्योंकि नए संयंत्र के फलस्वरूप स्पष्ट रूप से कार्यक्षमता में कमी हुई है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा, एनआईपी का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान सर्वोत्तम उपयोग पर विचार इस जांच परिणाम में संबंधित खंड के अंतर्गत विस्तार में दिए गए अनुसार कच्चे माल, उपयोगिताओं आदि के बारे में विचार किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण एवं गैर आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़े गए थे।
- vi. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी चीन के निर्यातकों के लिए उनके रिकार्डों के आधार पर और न कि संरचित सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करें, यह नोट किया जाता है कि चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली में दिए गए अनुसार किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन गण के किसी निर्यातक, जिसने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया।
- vii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि इसकी अस्थिरता के कारण जांच की अवधि के अधिकांश भाग में इसके संयंत्र के बंद होने तथा इसकी कार्यक्षमता में कमी के कारण हुई है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई असाधारण एवं गैर आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़े गए थे।
- viii. इस तर्क के संबंध में कि इस याचिका के अपर्याप्त अगोपनीय पाठ ने समुचित खंडन दायर करने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता करने के हमारे अधिकार को बाधित किया है। यह नोट किया जाता है कि गोपनीयता संबंधी दावों की अनुमति नियम 7 के प्रावधानों के अधीन जहां भी लागू हो, दी जाती है।
- ix. इस तर्क के संबंध में कि अंतिम शुल्क की सिफारिश धारा 9ख की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार नहीं की गई है। यह नोट किया जाता है कि अंतिम शुल्कों की सिफारिश सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, जिन्हें नियम 13 के अंतर्गत बाद में लगाया गया था, पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 के अनुसार की गई थी।

- x. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता यह दर्शाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं कि कोई पाटन हुआ है और घरेलू उद्योग को इसके परिणामस्वरूप क्षति हुई है। यह नोट किया जाता है कि इस अंतिम जांच परिणाम में विभिन्न प्रकार की चर्चा विशिष्ट रूप से पाटन के सभी पहलुओं और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के सभी पहलुओं का समाधान करते हैं।
- xi. इन दावों के संबंध में कि "संदर्भ कीमत" आधार शुल्क वर्तमान मामले में सबसे उपयुक्त शुल्क है, यह नोट किया जाता है कि केवल इस मामले के तथ्यों के आधार पर शुल्क के उपयुक्त रूप की सिफारिश की जाएगी, यदि इस प्रकार के किसी शुल्कों को लगाया जाना अपेक्षित हो।
- xii. हेनकेल के दावे के संबंध में कि प्राधिकारी का खाद्य सुरक्षित टीडीआई को बाहर किए जाने के इसके दावे के संबंध में विश्लेषण सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है और यह किए गए अनुरोधों पर विचार करने में असफल है, तब प्राधिकारी नोट करते हैं कि हेनकेल ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियों में इस बात का उल्लेख किया है कि खाद्य सुरक्षित टीडीआई श्रेणी का वर्तमान में उनके द्वारा अन्य देशों से आयात किया जाता है। वर्तमान जांच का इस प्रकार के किसी अन्य देशों से टीडीआई के आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, हेनकेल यह नहीं दर्शा सके कि क्या जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से खाद्य सुरक्षित टीडीआई का कोई आयात हुआ था और किस प्रकार से आयात किए गए इस प्रकार के उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीडीआई से अलग थे। प्राधिकारी द्वारा इन उत्पादों पर बाहर किए जाने पर तब विचार किया जाता है जब तथ्य यह दर्शाते हों कि आयात की गई सामग्री घरेलू स्तर से उत्पादित वस्तुओं की समान वस्तु नहीं है। जहां तक आयात की गई टीडीआई और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तु इस नियमावली में दिए गए प्रावधान के अनुसार समान वस्तु हैं, इस उत्पाद को बाहर किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और तदनुसार, हेनकेल के दावे पर विचार नहीं किया गया है।
- xiii. आवेदक के इस तर्क के संबंध में कि हनवा केमिकल कारपोरेशन के लिए किसी अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि एचएफसीसी/एचसीसी द्वारा निर्यात के तथ्यों को उचित रूप में सत्यापित किया गया था और एचसीसी के लिए इसका निर्धारण करना उपयुक्त पाया गया था।
- xiv. इस तर्क के संबंध में कि मैसर्स ताज अल मुलुक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण हनवा केमिकल कारपोरेशन को कोई अलग-अलग मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि ताज अल मुलुक से आयात पर अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया था, हालांकि इस समूह के शेष निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया था।

ढ. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

136. उठाये गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों जैसे इस प्रारंभिक जांच परिणाम में दर्ज हैं कि जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- (1) विचाराधीन उत्पाद का भारत को संबद्ध देशों से निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
- (2) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- (3) वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ण. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

137. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ कम होगा, घरेलू उद्योग का ह्रास होने से रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। सामान्यतः पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इसलिए, पाटन-रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने से ईरान से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा और उपभोक्ताओं इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अभी भी इस उत्पाद की आपूर्ति के अनेक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

प. सिफारिश

138. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और अनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- (क) विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से भारत को सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है।

(ख) घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

(ग) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दों पर सार्थक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू की गई थी और उसका संचालन किया गया था तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित करने के साथ-साथ पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित पाटन और क्षति को दूर करने के लिए निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लागू करना आवश्यक है। इसलिए प्राधिकारी नीचे निर्धारित किए गए रूप में और तरीके से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं।

139. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में बराबर समान अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार राशि के अनुसार अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है, जिसका विवरण नीचे तालिका के कालम (3) में विनिश्चित किया गया है, उसके मूल देश की प्रविष्टि कालम (4) में विनिश्चित की गई है, निर्यातक देश की प्रविष्टि कालम (5) में की गई है, उत्पाद के उत्पादक की प्रविष्टि कालम (6) में विनिश्चित की गई है, निर्यातों के निर्यात की प्रविष्टि कालम (7) में विनिश्चित की गई है और भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की विनिश्चित राशि की प्रविष्टि कालम (8) में की गई है, प्रति यूनिट का मापन कालम (9) में किया गया है और उसकी मुद्रा कालम (10) में विनिश्चित की गई है। यह पाटन-रोधी शुल्क इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

शुल्क तालिका

| क्रमांक | उप-शीर्ष | वस्तुओं का विवरण | मूल देश | निर्यातक देश | उत्पादक | निर्यातक | राशि | यूनिट | मुद्रा |
|---------|----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|------|----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | 29291020 | टोलीन डि-आइसोसायनेट | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | कोई भी | कोई भी | 0.26 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 2 | 29291020 | टोलीन डि-आइसोसायनेट | चीन जनवादी गणराज्य | पाटन-रोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश | कोई भी | कोई भी | 0.26 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 3 | 29291020 | टोलीन डि-आइसोसायनेट | पाटन-रोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश | चीन जनवादी गणराज्य | कोई भी | कोई भी | 0.26 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 4 | 29291020 | टोलीन डि-आइसोसायनेट | जापान | जापान | कोई भी | कोई भी | 0.15 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 5 | 29291020 | टोलीन डि-आइसोसायनेट | जापान | पाटन-रोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश | कोई भी | कोई भी | 0.15 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|
| 6 | 29291020 | टोलीन डि- आइसोसायनेट | पाटन-रोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश | जापान | कोई भी | कोई भी | 0.15 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 7 | 29291020 | टोलीन डि- आइसोसायनेट | कोरिया गणराज्य | कोरिया गणराज्य | हानवा केमिकल कापेरिशन | (क) पीपीएंडवी इंटरनेशनल कंपनी लि. (ख) एवरलाईट कं. लि. (ग) आईएमएस कापेरिशन | 0.22 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 8 | 29291020 | टोलीन डि- आइसोसायनेट | कोरिया गणराज्य | कोरिया गणराज्य | बीएस एफ कं.लि. | बीएस एफ कं.लि. | 0.31 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 9 | 29291020 | टोलीन डि- आइसोसायनेट | कोरिया गणराज्य | कोरिया गणराज्य | उपरोक्त क्रमांक 7 और 8 में उल्लिखित से इतर कोई अन्य संयोजन | | 0.44 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 10 | 29291020 | टोलीन डि- आइसोसायनेट | पाटन-रोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश | कोरिया गणराज्य | कोई भी | कोई भी | 0.44 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |
| 11 | 29291020 | टोलीन डि- आइसोसायनेट | कोरिया गणराज्य | पाटन-रोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश | कोई भी | कोई भी | 0.44 | कि.ग्राम | अमरीकी डालर |

140. उपरोक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी दिनांक 28 मार्च, 2017 के प्रारंभिक जांच परिणाम की संपुष्टि करते हैं। तथापि, उपरोक्त संस्तुत शुल्क सीमा-शुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (2) के अनुसार अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क को लागू किए जाने की तारीख को लागू होगा।

141. इन अंतिम जांच परिणामों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के बाद उनके आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, 1995 में यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 के अनुसार सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2017

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Toluene Di- Isocyanate (TDI)’ originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.

No.14/36/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time [hereinafter also referred to as the Act] and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, [hereinafter also referred to as the Rules], as amended from time to time, thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. Whereas M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as “the petitioner” or “the applicant”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and Rule *supra* for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of “Toluene Di- Isocyanate” (TDI in short) (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration), originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP (hereinafter also referred to as the subject countries) alleging dumping of subject goods from subject countries and consequent injury to the domestic industry.
3. And whereas the Authority on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No.14/36/2016-DGAD dated 05.10.2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation in accordance with the sub Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
4. The Authority issued Preliminary Findings vide Notification No.14/36/2016- DGAD dated 28.03.2017, read with corrigendum dated 10.4.2017, recommending provisional anti-dumping duty in the present investigation on imports of subject goods from subject countries. Based on such recommendation, Ministry of Finance issued a customs notification imposing provisional anti-dumping duty vide Customs Notification No. 25/2017-Customs (ADD) dated 05.06.2017 accepting the recommendations of the Authority. Provisional duties were imposed for six months from the date of customs notification *supra*.

B. PROCEDURE

5. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation;
 - i. Preliminary scrutiny of the application showed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
 - ii. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of rule 5 *supra*.
 - iii. In addition to the provisions of sub-rule (5) of Rule 5 *supra*, the Government of Korea RP was informed through its Embassy in India about the receipt of the subject application as per provisions of Article 2.14 of Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Korea RP
 - iv. Post initiation, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the AD Rules. Necessary extensions to file such submissions wherever warranted have also been permitted by the Authority.
 - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules *supra*. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

- vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;
- Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd, China PR.
 - Changzhou Dahua Group Co., Ltd, China PR.
 - Shanghai BASF Polyurethane Co., Ltd, China PR.
 - Bayer Material Science (China) Co., Ltd, China PR.
 - Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes, Japan.
 - Nippon Polyurethane Industry Co., Ltd, Japan.
 - Hanwha Fine Chemical Co., Ltd, Korea RP
 - OCI Corporation/OCI Company Ltd, Korea RP
 - BASF Company Ltd, Korea RP
- vii. In response to the initiation notification and intimation, the following exporters / producers from subject countries have responded to the Authority by filing Exporter Questionnaire Response;
- Hanwha Chemical Corporation, Korea RP
 - TAJ AL Mulook General Trading LLC, UAE
 - PP and Y International Co. Ltd, Korea RP
 - IMS Corporation, Korea RP
 - Everlite Korea Co., Ltd, Korea RP
 - BASF Company Ltd, Korea RP
- viii. Apart from the above companies, following companies from China PR also shown their interest to participate in the investigation though they claimed not to have exported the subject goods to India during the POI;
- Wanhua Chemical Group Co., Ltd
 - Cangzhou Dahua Holding Co., Ltd
- ix. Following exporters also filed certain submissions following the initiation;
- Covestro (Hong Kong) Limited
 - Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes INC
- x. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information;
- Sheela Group Co.,
 - Tirupati Foam
 - Kurlon Ltd.
 - Springwell Mattresses
 - Sunrise Foam Product Pvt Ltd.
 - M H Polymers
 - Pyarelal Foam (South)
 - Jindal Foam
 - Allied Foam
 - Dura Puff
 - Fancy Foam
 - Hindustan Polyfoam
 - Shree Malani Foams
 - Prime Comforts
 - Springfeel Polyurethanes
 - Aadi Polymers

xi. In response, following importers/users have responded by filing Importer Questionnaire responses;

a) Sheela Foam Ltd.,

- xii. Apart from the above parties, M/s. Indian Polyurethane Association, claimed to be an association of users of the subject goods in India and M/s. Henkel Adhesives Technologies India Pvt Ltd, claimed to be an importer cum user of the subject goods in India sought to participate in the present investigation but after almost six months from the date of initiation. Both the parties filed their submissions. However, M/s. Henkel Adhesives Technologies India Pvt Ltd did not file the importer questionnaire response as prescribed. The said parties also *inter alia* submitted that there is no legal bar on their participation in the present investigation after lapse of significant time from the date of initiation. It has been contended by the domestic industry that participation and submissions at such a very belated stage should be out rightly rejected and such parties should be declared as non-cooperative. However, without getting into the merit of tenability of the request for participation and the objections raised, the Authority has considered the submissions made by such parties to the extent they are relevant for the purpose of the present investigation and are addressed at appropriate places in this final finding.
- xiii. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xiv. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry or not. Principles of Annexure III to the Anti-Dumping Rules have been followed to determine the Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP').
- xv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. On site verification of the information provided by the domestic industry and also the exporters were conducted to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, is relied upon for the purpose of this final finding.
- xvii. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
- xviii. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- xix. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in hearings held on 11.8.2017 and 17.10.2017. All the parties attending the oral hearing were requested to file their written submissions and also rejoinders and such submissions are also considered for the purpose of this final finding.
- xx. The Authority has considered 1st April, 2015 to March 31st 2016 (12 months) as the POI so as to undertake analysis on the most recent data. Thus, investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 31st March 2016(POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, however, covered the periods Apr' 12-Mar' 13, Apr' 13-Mar' 14, Apr' 14-Mar' 15 and the period of investigation.
- xxi. Import information as per secondary sources (IBIS) has been provided in the application by the applicant and the same has been relied upon at the initiation stage. However, the Authority has relied upon the transaction wise import data as collected from DGCI&S for the purpose of volume and value of subject goods into the country for the previous years and POI for the purpose of provisional finding and the same is relied upon in this final finding also.
- xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present provisional finding on the basis of the facts available.
- xxiii. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 27th November 2017 to the concerned interested parties. Comments were requested by 6th December 2017 Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority are considered in this final finding.
- xxiv. ***In this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

- xxv. Exchange rate for conversion of US\$ to Rupees considered for the POI is Rs. 65.91 per 1 US\$ as per customs data.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

6. The product under consideration (PUC) in the present investigation is "Toluene Di- Isocyanate" (TDI) originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.
7. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound with the formula $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration.
8. TDI is a clear liquid and is used for production of Flexible Polyurethane Foam, Furniture cushion, Industrial Gaskets, Protective pads for Sports & Medical use, Automobiles: Seats, Furniture, Lining, Sun visors etc., packing: Electronic items, Frozen Foods, Medicines, Audio-video Computer CD's etc.
9. TDI being an organic chemical is categorised under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under subheading 29291020 which pertains to Toluene di-isocyanate. However, as submitted by the applicant, this heading includes certain grades other than isomers (80:20) hence the classification is indicative only. It has also been claimed by the applicant that the imports of the subject goods have been reported under some other subheadings also such as 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 and 39095000. An examination of the import data as per DGCI&S shows that imports during POI were under subheading number 29291020 and there were substantial imports under subheading 29291010 and 29291090 also. Hence, the Customs classification is treated as indicative only and in no way binding on the scope of the PUC in the investigation and any measures to be recommended to be imposed, if any.
10. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:
"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation".
11. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules.

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

- a) In this investigation product under consideration is TDI having isomer content in 80:20 ratio, and any other grades of TDI have been excluded from the scope of PUC. Thus, TDI used in adhesives, which are subsequently used in Adhesives for food packaging, appears as included within the PUC. Food-safe TDI having isomer content in 80:20 imported for manufacture of food-safe adhesives should specifically be excluded from the scope of the current investigation. Henkel has submitted that they have imported the same for its use in Food based industry. Most of the participants are foam manufacturers and their end-use is clearly distinct from Henkel's end-use of the imported goods.
- b) Henkel in its initial submissions has requested for exclusion of "food-safe TDI having isomer content in 80:20 imported for manufacture of food safe adhesives" from the scope of PUC. However, the company has changed the request of exclusion to "TDI having specific migration limit of 0.01 mg/kg of food and adherent to the EU Regulation 10/2011 for use in adhesives intended for food contact application.
- c) Henkel has been in negotiations with the Petitioner for two years to procure food-safe TDI which can be used in the manufacture of food-safe adhesives. However, GNFC has been unable to meet regulatory requirements with respect to food safety and required TDI specifications. It is clear that the product imported by Henkel is not manufactured by GNFC.
- d) The TDI produced by GNFC is not suitable for food-safe adhesives. Due to this, Henkel had to import such food-safe TDI. Henkel also cited certain past decisions while seeking exclusion of food safe TDI as claimed.
- e) Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc (MCNS) sought clarifications from the Authority whether two products namely "TM" and "MT" are included/excluded in the scope of PUC or not. It has been submitted by MCNS that TM is a mixture of 50% or more of TDI and polymeric MDI (Polymethylenepolyphenyl/ polyisocyanate or PMDI). Further, MT is a mixture of less than 50% of TDI and modified monomeric MDI,

4,4'- (Diphenyl methaneisocyanate). It has also been submitted by MCNS that there exists a vast difference in the chemical composition of TDI and TM/ MT and in fact TDI is used in the production/manufacturing process of TM and MT.

Views of the Domestic Industry

- a) The PUC is clearly defined in the initiation notification and also in the provisional finding and the same may be adopted for the purpose of final finding as well.
- b) Henkel has requested for exclusion of Food Safe TDI which is claimed to be imported by them from the scope of PUC. However, the company could not substantiate the need for exclusion Food Safe TDI. As such, the request for exclusion of food safe TDI is totally unsubstantiated and are highly vague. Also, the imports do not show any data concerning food grade TDI. Exclusion as asked is not tenable on this basis alone.
- c) Henkel also did not file the details of their imports including invoices so that the facts of imports of food safe TDI can be verified by the Authority. Henkel did not file any IQ Response so that the difference of TDI imported by them and what is defined as PUC in the present investigation can be examined by the Authority.
- d) A mere claim that the DI is not producing the same is not a valid claim as GNFC understands the TDI produced by it meets all the chemical and technical properties of food grade TDI. Henkel has never shown interest in purchasing TDI from GNFC. Permitting such exclusion shall lead to misuse of such exclusions and duties may be circumvented under the garb of excluded item.
- e) Also, Henkel has not given any technical, chemical and commercial details of the food safe TDI for which they have sought exclusion. It is also not established by Henkel how food safe TDI would be identified at the customs frontiers and what was the name for this type used at the time of import. The import data do not show any description as to food grade TDI.
- f) There are not sufficient technical reasons provided by Henkel while seeking exclusion of so called Food Grade TDI from the scope of PUC. It appears that the focus of Henkel is to get the material at dumped prices and for that a plea of grade issue is brought in. Henkel could not come up with any cogent reason based on facts as to how the food safe TDI is different from the TDI produced by the DI.
- g) Below are the observations of the DI about technical comparison of GNFC's product viz. TDI understood to be desired by Henkel;
 - i. TDI Purity: 99.9% (This is more than Lower Side Limit of 99.5% asked by Henkel)
 - ii. GNFC's TDI has % of isomer as: 80 +/-1: 20 +/- 1.
 - iii. Hydrolizable Chloride is less than 80 PPM, which is matching with requirement of M/s. Henkel.
 - iv. Acidity of HCl remains less than 40PPM, which is matching with requirement of M/s. Henkel.
 - v. Colour: Generally remains 15 APHA +5.
 - vi. NCO remains minimum at 48.13 (% w/w), which is higher than Lower limit of M/s Henkel.
 - vii. Heavy Metals: After a meeting with M/s Henkel in March-2016, GNFC has tried to analyse heavy metals in its laboratory. GNFC could not find any traces of heavy metals in analysis. Also, in this regards, it was decided that M/s. Henkel will ask for TDI sample for analysis at their end but they have never asked for the same.
- h) With regard to the aspect of heavy metals, GNFC is ready to give TDI sample to M/s. Henkel and Henkel can prove their claims accordingly. M/s. Henkel has never shown interest in purchasing TDI from GNFC in the past. In any case, there is nothing called food grade TDI and TDI produced and sold normally is highly toxic in nature.
- i) The above analysis clearly shows that there are no technical reasons for Henkel to seek exclusion of so called Food Grade TDI from the scope of PUC. It appears that the focus of Henkel is to get the material at dumped prices and for that a plea of grade issue is brought in. GNFC can give its TDI for any sample testing by Henkel and Henkel should come up with the a cogent reasoning based on a technical report that how are they justified in seeking exclusion of TDI type mentioned by them and no exclusion should be permitted merely on such ground.
- j) GNFC is a TDI producer. TDI purchased either domestically or imported by Henkel will have to undergo further processing at the end of Henkel to suit the requirements of products produced by them. M/s. Henkel is converting TDI to adhesive which is used in plastic packaging.
- k) Henkel has requested for exclusion of Food Safe TDI from the scope of PUC. However, while seeking an exclusion of an imported product, Henkel has not submitted the details of the product that they have imported before the Authority. No IQR has been submitted. No details as to volume, price, other details etc. of that import

are submitted and a mere request for exclusion is made. In fact Henkel in the past has requested for exclusion of “food-safe TDI having isomer content in 80:20 imported for manufacture of food safe adhesives” and have subsequently changed the request for exclusion to “TDI having specific migration limit of 0.01 mg/kg of food and adherent to the EU Regulation 10/2011 for use in adhesives intended for food contact application”. The Authority may take note of such inconsistencies in the claims of the importer.

- l) Also, the submissions by Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes INC are also not of any merit and the issue raised itself are of no basis. TDI alone is included in the scope of PUC and the same is properly defined in the initiation and also in the provisional finding.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

12. The product under consideration (PUC) in the present investigation is “Toluene Di- Isocyanate” (TDI) originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.
13. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound with the formula $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration.
14. TDI being an organic chemical is categorised under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under subheading 29291020 which pertains to Toluene di-isocyanate. However, as submitted by the applicant, this heading includes certain grades other than isomers (80:20). Hence, the classification is indicative only.
15. The Authority has examined the claims and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the above, the Authority holds that the products manufactured by the Applicant constitute like article to the subject goods imported into India from the subject countries within the meaning of Rule 2 (d) of the AD Rules.
16. With regard to the request of M/s Henkel Adhesives Technologies India Private Ltd. to exclude Food Safe TDI from the scope of PUC, the issue has been examined after considering the submissions of Henkel and the domestic industry. While the crux of the argument of Henkel is that GNFC is not producing and supplying the food safe TDI which is primarily used by Henkel hence the inclusion of same in the scope of PUC is not justified. GNFC submitted that the TDI produced and supplied by them have all the essential properties of food safe TDI as required by Henkel though Henkel has not placed any order for the same in the recent past. As per GNFC, TDI is by nature toxic and when it is put through further chemical reactions by the users including adhesives intended for food contact application, the toxic elements get neutralised and TDI as such cannot be produced and sold without such toxic property which is in the basic nature of the product. GNFC also submitted inter alia that exclusion of such a type would lead to wide misuse rendering any duties imposed as not effective. It is also noted that Henkel has initially requested for exclusion of Food Safe TDI from the scope of PUC. However, subsequently changed the request for exclusion to “TDI having specific migration limit of 0.01 mg/kg. of food and adherent to the EU Regulation 10/2011 for use in adhesives intended for food contact application”. It is noted that there is no facts on record in this regard submitted by Henkel to substantiate the claims and enable the Authority to consider their request. After considering the submissions, the Authority notes that the facts as available on record do not show that the food safe TDI as claimed by Henkel is a different product from the TDI as defined in this investigation produced and sold by the domestic industry in terms of technical and commercial parameters. Accordingly, the request made by M/s. Henkel Adhesives Technologies India Private Ltd to exclude the food safe TDI is not accepted.
17. With regard to the clarification sought by Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes INC, it is noted that this matter has been dealt in the provisional finding itself to which the said exporter did not provide any comments. The view taken in the provisional finding stands relevant for the purpose of this final finding also since, post oral hearing, they did not offer any comments in this regard and has been reiterated as below:

“ There have not been any submissions made by any of the responding interested parties vis-à-vis the definition and scope of the PUC, except one exporter, namely Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc (MCNS). MCNS sought clarifications from the Authority whether two products namely "TM" and "MT" are included/excluded in the scope of PUC or not. It has been submitted by MCNS that TM is a mixture of 50% or more of TDI and polymeric MDI (Polymethylenepolyphenyl/polyisocyanate or PMDI). Further, MT is a mixture of less than 50% of TDI and modified monomeric MDI, 4,4'- (Diphenylmethane diisocyanate). It has also been submitted by MCNS that there exists a vast difference in the chemical composition of TDI/PUC and TM and MT and in fact TDI is used in the

production/manufacturing process of TM and MT. After carefully examining the submissions of MCNS, the Authority notes that the definition and scope of PUC is clearly provided in the initiation notification and also in this provisional finding which should help MCNS to gauge whether their product falls under the PUC category or not. With the given facts, it does not appear to be essential and practical on the part of the Authority to provide a specific opinion on the inclusion or exclusion of two different products that are claimed to be exported by MCNS into India. PUC fulfilling the definition herein above alone shall come under the ambit and scope of present investigation and not any other products.”

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

18. The Application has been filed by M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited as the domestic industry.
19. The applicant company has claimed that they are the sole producer of subject good in India. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes “a major proportion” of the domestic production; in fact 100% share of total domestic production.
20. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under;
“(2) (b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”
21. It is noted that the application based on which the present anti-dumping investigation is initiated has been filed by M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited as the “domestic industry” concerning the subject goods in India. As per the claims of the applicant, M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited is the sole producer of the subject goods in India. It is also noted that there are not any rival submissions on the aspect of domestic industry and standing filed by any of the opposing interested parties.
22. None of the interested parties have made any submission with regard to the scope and standing of the domestic industry. The applicant, however, submitted that they are the sole producer of the subject goods in India and qualifies to be treated as the “domestic industry” within the meaning of Rule 2 (b) for the purpose of present investigation.
23. Since the production of the applicant accounts for “a major proportion” in the total production of the subject goods in India [in fact 100%], the Authority holds that the applicant satisfies the standing criteria under Rule 5(3) and constitutes domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

- i. The Petitioner has claimed excessive confidentiality pertaining to various details in the Proforma IV A and indexed trend is also not provided for certain parameters and the same are unduly condoned which is prejudicial to the Respondent’s interests. The Authority may seek the withheld information from the Petitioner, or in the alternate, a suitable non-confidential summary thereof be provided.
- ii. Part VI (Costing Information) has been claimed as confidential. Parameters prescribed in Formats B, CI and CII, D and E have been entirely claimed as confidential. Such claims are in violation of the decision of the Hon’ble Supreme Court of India in *Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority 2003 (158) E.L.T. 673 (S.C.)* and also in the case of *RIL Vs. Designated Authority [2006 (202) ELT 23 (SC)]*.
- iii. It is necessary for the applicant industry to disclose all the necessary information or its non-confidential version in accordance with the provisions of law so that other interested parties are in a position to defend their interests which is not done in the present case.
- iv. Designated Authority has not provided the segregated DGCI&S data in soft copy. The preliminary findings also do not record that any party had claimed confidentiality under any other law on such data.

Views of the Domestic Industry

- i. Excessive Confidentiality in submissions is adopted by responding producers/exporters and importers. The NCV version of the EQ Responses and IQ Responses do not permit any reasonable understanding of the claims of such parties vis-à-vis dumping and the detail of import that have been made in the country by such responding parties.
- ii. NCV versions of the documents are provided in a manner restraining the domestic industry from making any evaluation of the same.

- iii. The following basic information provided by the producer/exports/importers respectively cannot be claimed as confidential;
 - a. Information on total volume of exports/imports from subject countries,
 - b. Average price of imports from subject countries,
 - c. Holding Company details and also the name of the concerned producers where exporters/traders have filed the response. In fact, none of the exporters/traders participating have disclosed the names of the respective producers name whose materials have been exported by such parties.
- iv. While the rules requires the parties providing information on a confidential basis to furnish non-confidential summary thereof, the responding parties have resorted to a methodology convenient to them and literally restricted the petitioner from gauging the factual position with regard to dumped imports made by them. Excessive confidentiality adopted by the responding parties also contravenes the findings of the Appellate Body in European Communities-Anti-Dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China (WT/DS 397/AB/R dated 15th July, 2011) wherein the Appellate Body has interpreted Articles 6.5 and 6.5.1 of the Anti-dumping Agreement concerning confidentiality.
- v. The petitioner has claimed certain business sensitive information as confidential by providing adequate reasoning. Information claimed as confidential has been followed by an indexed summary wherever possible. In fact, it is the opposing parties which have resorted to excessive confidentiality and the DI is not provided with any meaningful summary of their data. For example, when GNFC disclosed all information with regard to volume parameters, exporters and importers did not disclose any volume information in its NCV response and not even any summary/range of the same. Also, it should be noted that the DGCI&S summary data relied upon is available in the public file which is self- explanatory on which all transactions are considered as that of PUC and others etc. It is not obligatory to provide the same in excel format. There isn't any violation of the jurisprudence set in Sterilite case by the DI.
- vi. The contentions of deficiencies in the petition are all baseless and have no legal or factual basis and all the contentions are denied as bereft of any merit. There isn't anything in the rule which says contents of proforma IVA should be disclosed to all interested parties as it is. It also needs to be noted that financial statements and balance sheets of the company is provided and no such statements product wise as demanded by certain parties is nether maintained nor statutorily required and the claim is not of any merit.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

24. Various submissions made by the opposing interested parties and also domestic industry with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed herein below.
25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

 - (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
 - (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*
26. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.
27. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. Various discussions in this final finding are self-explanatory on the other contentions of the parties on confidentiality aspect.

28. With regard to the submission of confidentiality qua the DGCI&S transaction wise import data, it is noted that the import information as per DGCI&S which has been relied upon, the details of which is made available both in the provisional finding and also the final findings

E. MISCELLANEOUS ISSUES

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

- i. The initiation of the present investigation is bad in law and therefore must be terminated immediately. Further, even if the initiation is deemed to be valid, the requirements of dumping, injury to the domestic industry and causal link are not fulfilled.
- ii. There are serious deficiencies in the Petition which are sufficient for terminating the investigation.
- iii. Post-POI data must be considered before imposition of Final Duty and Duty, if any, must be on Reference Price Basis.
- iv. Unique factual situation of the Petitioner and the selected POI mandates consideration while examining dumping and injury in the present case. The POI, i.e., FY 2015-16 follows an exceptional and anomalous period for the Petitioner. Due to the market upheaval and changes in 2014, the economic parameters of the Petitioner have been adversely affected. Even the calculation of Petitioner's normal cost of production and non-injurious price need to include these considerations.
- v. The Balance sheet and financial statements for the subject year for the company and the specific product in question have not been provided.
- vi. The segregation of DGCI&S data for the PUC and others and how the raw import data has been sorted by the Authority is not clear. The Authority should provide the complete transaction-wise raw import data as well as sorted import data in MS-Excel format.
- vii. Recommendation of provisional duty not in accordance with the specific requirement of Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the "Act") and Rule 12 of the AD Rules. Thus, the preliminary findings are without jurisdiction, illegal, arbitrary, unreasoned and in clear disregard of the principles of natural justice.
- viii. The first condition for imposing preliminary findings is with regard to dumping, injury (material injury) and causal link during the period of investigation while the second precondition is in relation to the injury during the course of investigations which, by definition, is subsequent to the period of investigation (POI). In the instant case the Authority while recommending its preliminary findings failed to appreciate such requirements. The Designated Authority also failed to record any factor which can be construed as a "further" determination "during the course of the investigation" as it being a mandatory requirement.
- ix. Domestic Industry has not been able to prove their case of injury on any of the parameters provided in the law and therefore has miserably failed to establish their case in terms of the requirement of the law.
- x. The Domestic Industry is not suffering any injury and the imposition of duty would create an imbalance in trade rather than counter-balance the negative effects of alleged dumping.
- xi. The DI is catering to substantial Indian demand (without any duty imposition) and the prices of TDI have globally increased in the period post-POI.
- xii. The DI's production facilities are unreliable and prone to constant shut-down.
- xiii. In light of the Petitioner's new capacities of about 50,000MT which it has admittedly had operational difficulties with, the Authority must consider that the duty may be imposed for a shorter, limited duration allowing the Petitioner's capacities enough time to stabilize. Any duty beyond a reasonable extent must be discouraged.
- xiv. Higher anti-dumping duty should be imposed for Japan on account of non-cooperation by Japanese producer/exporters.
- xv. ADD is an attempt to establish monopoly

Views of the Domestic Industry

- i. Importers/users namely M/s Indian Polyurethane Association (IPA in short) and M/s Henkel Adhesives Technologies India Private Ltd have sought to participate in the present investigation at a very belated stage. The public file shows that IPA has first time responded on 4th April, 2017 by way of filing comments on the PF and Henkel responded on 2nd May, 2017 which is almost 6 months after the date of initiation i.e 5.10.2016. Such delay is when the initiation has clearly set the time limits to file any responses including questionnaire responses.

- ii. The deadlines set to reply were as per Rule 6 (4) of the AD Rules and the said rule is applicable for all the 'interested parties' in an investigation and the interested parties are defined in the AD Rule at Rule 2 (c). The parties who do not fall in the category of 'interested parties' have no role in a specific AD investigation.
- iii. IPA has submitted that there is no bar on an interested party like IPA to join an investigation at the time of their choosing. The claim is not correct and the provisions of Rule 6(4) are applicable on all 'interested parties' to an investigation and any party who do not adhere to the provision of Rule 6(4) of the AD Rules with regard to time limits to respond to the initiation cannot be treated as an interested party under any circumstances and their submissions whatsoever also cannot be taken on record.
- iv. The submission made by IPA dated 4th April, 2017 has nothing to prove their credentials as the association of users of the subject goods as provided in the Rule. IPA failed to provide any registration certificate, MoA or AoA, list of their members, IQ Responses by the members etc that the credentials of the Association are also in question apart from the delay in responding to the Authority. Based on this alone, IPA cannot be treated as an interested party under the Rules for the purpose of present investigation. They should be declared as non-cooperative party.
- v. Henkel has also not filed any importer questionnaire response. In the absence of importer questionnaire response, the credential of Henkel and also the details of their import of subject goods can be examined and on this ground alone Henkel should not be treated as a cooperative importer or interested party for the purpose of present investigation.
- vi. The submissions of exporters on public interest in India cannot be taken on face value. The Authority has found significant dumping margin and injury margin in case of exports made by such exporters also. Such parties are trying to put forth all arguments to avoid any anti-dumping duties on it which it is otherwise liable now. Catering to about 50% of the Indian demand did not help the DI to achieve profits as the prices were suppressed and depressed by dumped imports and the price underselling has also been very significant.
- vii. Any claimed increases in global prices post POI and also domestic situation post POI are irrelevant and such changes would at the best be the subject matter of a review. It is also a baseless argument in the context of public interest that the DI's plant is prone to shut down and is unreliable. GNFC has decades of experience in producing TDI and its new plant is also operating with all the stability that the Indian users can rely on GNFC for TDI.
- viii. Certain parties have requested to consider post POI data before publishing the final finding. It is submitted that post POI data has no relevance in the context of a fresh investigation and the claim has no legal sanctity. Any changes post POI can at the best be a subject matter of an MTR under Rule 23 and cannot be considered for the purpose of Rule 17 and 18. This is a settled issue before the Authority and similar view on this issue has been taken by the Authority in plethora of investigations in the past.
- ix. The contentions of opposing parties against provisional duties are not correct. Provisional duties were found essential and have been recommended by the Authority and the Central Government has imposed the same. The provisional finding elaborated on the facts of the present case and why was it essential to impose provisional duties pending further investigation. The PF clearly contains the 'further' determination at appropriate places and PF needs to be confirmed at the time of final finding.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

29. Various interested parties have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination and injury claims of the domestic industry. While the issues regarding the dumping and injury determination is addressed in the appropriate places in this finding, the general issues raised by the parties to the investigation are examined and addressed as provided hereunder;
 - i. With regard to the contention that the initiation of the present investigation is bad in law and therefore must be terminated immediately and the requirements of dumping, injury to the domestic industry and causal link are not fulfilled, the Authority notes that the case was initiated based on application filed by the domestic industry prima facie establishing dumping of subject goods from subject countries and consequential injury to the domestic industry as provided in the Rule. Detailed findings as to the dumping, injury and a causal relationship are provided in this finding which is self-explanatory. Thus, the claims are unsubstantiated and void of merits.
 - ii. With regard to the contention that there are serious deficiencies in the Petition which are sufficient for terminating the investigation, it is noted that the petition based on which the present investigation was initiated contained all the relevant details to substantiate the claims and wherever required further details were sought from the petitioner. Thus, the claims are unsubstantiated and void of merits.
 - iii. With regard to the submission that Post-POI data must be considered before imposition of Final Duty and Duty, if any, must be on Reference Price Basis. It is noted that the authority is required to examine and consider only the POI and previous three years data as undertaken at the time of initiation under the AD Rules for the

- determination of dumping and injury. With regard to the request for reference price duty, it is noted that the form of duty which is found appropriate to achieve the envisaged purpose of duty is adopted.
- iv. With regard to the claims of unique factual situation of the Petitioner that the selected POI mandates consideration and even the calculation of Petitioner's normal cost of production and non-injurious price, it is noted that POI selected has been the most recent and appropriate period to examine the various parameters as envisaged in AD Rules and the NIP is also determined as per the principles in Annexure III to the Rules.
 - v. With regard to the contention that the Balance sheet and financial statements for the subject year for the company and the specific product in question have not been provided, it is noted that the relevant information in this respect as prepared by the petitioner has been provided and are also available in the public domain.
 - vi. With regard to the claim that the segregation of DGCI&S data for the PUC and others, the authority notes that raw data has been segregated and based on the data for the PUC has been considered for analysis which formed the basis for the final findings.
 - vii. With regard to the contention that recommendation of provisional duty is not in accordance with the specific requirement of Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the "Act") and Rule 12 of the AD Rules, thus, the preliminary findings are without jurisdiction, illegal, arbitrary, unreasoned and in clear disregard of the principles of natural justice, it is noted that the provisional finding explains the legal and factual back ground which has led to the recommendation for provisional duties pending further investigation.
 - viii. With regard to the contention that the Authority failed to appreciate the requirements of provisional finding while notifying the same along with a "further" determination, it is noted that the provisional finding was recommended in consonance with the legal requirements and it was found appropriate to recommend interim measures after provisionally examining the facts concerning dumping, injury and their causal relation. The provisional finding showed existence of ingredients essential for recommendation of provisional measures.
 - ix. With regard to the claim that the Domestic Industry has not been able to prove their case of injury on any of the parameters provided in the law and therefore has miserably failed to establish their case in terms of the requirement of the law, it is noted that present finding is self-explanatory since it has dealt all relevant injury parameters.
 - x. With regard to the contention that the Domestic Industry is not suffering any injury and the imposition of duty would create an imbalance in trade rather than counter-balance the negative effects of alleged dumping, it is noted that while the present finding ipso-facto addresses the issue of injury, the purpose of imposition of anti-dumping duties is to remove the injurious effects of dumping and imposition per se would not lead to any trade imbalance as claimed.
 - xi. With regard to the claim that the DI is catering to substantial Indian demand (without any duty imposition) and the prices of TDI have globally increased in the period post-POI, it is noted that the dumping and consequent injury during the POI determined is the subject matter of the present investigation.
 - xii. With regard to the claim that the DI's production facilities are unreliable and prone to constant shut-down, it is noted that petitioner is in production of TDI for several years and have expanded the capacity a few years back and are supplying the subject goods from its facilities as a regular producer.
 - xiii. With regard to the submission that duty may be imposed for a shorter, limited duration considering the situation therein, the view of the Authority on the quantum of duty required and its duration is provided in the concluding part of this finding after considering all relevant facts of this investigation and what is provided in the rule which is self-explanatory..
 - xiv. The Authority has also considered the contentions of the domestic industry vis-à-vis the interest shown by M/s Indian Polyurethane Association (IPA in short) and M/s Henkel Adhesives Technologies India Private Ltd to participate in the present investigation but after lapse of significant time from the date of initiation. It is noted in this respect that consideration of the issues raised by the said parties at this juncture may not impede the current investigation in any manner and on that ground the issues raised by the said parties are addressed in this finding.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

30. The present investigation has been initiated on 5.10.2016 and it was open for the producers/exporters from China PR in the present investigation to rebut the NME presumption for the purpose of normal value determination. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR (in the present case) provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:

- a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
31. It is noted that none of the producers/exporters from China PR who have exported the subject goods to India during the POI have responded to the Authority in the present investigation by filing the required EQ Response and MET Response. Thus, the presumption of NME vis-à-vis China PR stands un-rebutted in the present investigation by the Chinese producer/exporters.

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

- i. Individual margin should be granted in the name Hanwha Chemical Corporation and not in the name of Hanwha Fine Chemical Corporation which has ceased to exist as a legal entity.
- ii. Preliminary duties were notified considering Hanwha Fine Chemical Corporation as the exporter, who was not the legal entity anymore, instead of Hanwha Chemical Corporation, despite the fact that the proper disclosure was made at the appropriate time with the supporting documents regarding Merger of Hanwha Fine Chemical Corporation in Hanwha Chemical Corporation within the tenure of Period of Investigation itself.
- iii. Evidences such as contract of Company Merger in Korean as well as translated copy in English, Relevant Extract of Commercial Act of Korea under which the merger of HFCC with HCC penetrated, Audited Annual Financial Statement of Hanwha Chemical Corporation (HCC) for 2016, Shareholder's list as on 31.12.2015 of HFCC, Post POI Export to India were submitted.
- iv. Hanwha does not procure any inputs from the related party. Hanwha only procures steam from the related party which accounts for not more 0.01% of the total cost of production of subject goods.
- v. At the time of preliminary findings, Hanwha's cost of production was not considered for computation of normal value because of the reason that the cost of manufacturing intermediaries such as TDA and CDC were not provided in the response. In the present scenario, Hanwha has provided the cost of goods of TDA and CDC during the production of subject goods at the time of verification including the cost of basic raw material. Subsequently, additional documents were also provided on the specific queries of the Authority. Thereafter, stage wise cost sheet of subject goods were also demanded, which was also provided along with justification. In view of the same, it is requested that the normal value should be determined on the basis of the verified information provided by Hanwha and not on the basis of the best estimates as done at the time of preliminary finding.
- vi. Hanwha has made exports through four different trading channels which were verified by the Authority during the onsite verification. Among these, there were four transactions of exports made through TAJ AL MULLOOK of Dubai to Indian Customer. The Indian Customer thereafter transhipped all such goods to other countries without entrance of subject goods into Indian Customs. Since, these goods were not consumed in India, Hanwha requests for exclusion of such goods for the purpose of Anti-dumping duty computation.
- vii. Government of Korea submitted that the name HCC instead of HFCC should be used in all relevant notifications. Korean Government also submitted that the information submitted by HCC should be used for all calculation purposes in view of Para 3 of Annexure II to the WTO AD Agreement. It has been submitted by the Korean Government that any duty on TDI will affect the TDI users in India and requested not to impose any anti-dumping duty.
- viii. The normal value for China in the current investigation may be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods in view of the fact that the period of 15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11th December 2016 in terms of para 15(d) and have currently become non-operational. Any other methodology used for the determination of normal value for Chinese exporters would be in violation of the obligations of India under the WTO.

Views of the Domestic Industry

- a. China PR should be treated as Non Market Economy country for the purpose of present investigation and Normal Value in case of Chinese producers should be determined as per the provisions of Annexure I Para 7.
- b. Chinese producers have been denied MET status in several investigations including recently concluded investigations by both Indian Authority and other countries like EU, USA, Australia etc as a part of various anti-dumping investigations by treating China PR an NME country.
- c. MET status can be given only in the event of fulfilment of all the MET conditions by the responding producers/exporters and not otherwise. Thus, requirements of para 8 (3) of Annexure I of AD rules has to be fulfilled holistically to obtain MET status.
- d. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
- e. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values. The expression “substantially reflect market values” has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The fact that such prices are comparable to the price prevailing in China is grossly insufficient.
- f. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establishes that their books are audited in line with international accounting standards. Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS).
- g. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules.
- h. The onus is on the responding Chinese producer/exporters to establish that they are operating under market economy conditions after satisfying all the conditions mentioned in AD Rules.
- i. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected, irrespective of the fact that the other companies of the group involved in production or sale of the product under consideration have filed the response.
- j. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been fully transparent and completely established through documentary evidence.
- k. There are not any cooperating producers/exporters in the present investigation who have rebutted the presumption of NME status by filing all relevant information as per MET Questionnaire. China PR should be treated as Non Market Economy country based on this fact alone.
- l. The applicant has submitted normal value and dumping margin as per the available information and methods permissible specified in the AD Rule and relevant annexure to the rule. Details of such calculations are provided in the NCV application which is elaborate and contains all essential specifics. The Authority may rely on such information all practical purposes in this investigation in case the concerned producer/exporters fail to meaningfully cooperate.
- m. The provisions of China Accession Treaty have no implications on the present case since the present case is initiated on 5.10.2016 and the POI selected is April 2015- March 2016.
- n. It is evident from the EQ Response filed by HFCC that the entity namely Hanwha Fine Chemical Corporation (HFCC) merged into a business division of Hanwha Chemical Corporation (HCC) on 29th February, 2016. However, the EQ Response is filed by providing details of HFCC as the entity which has no legal or factual justification.
- o. The questions in the entire EQ Response should have been answered by treating HCC as the entity with the given facts and not HFCC which ceased to exist on 29th February, 2016. In this scenario, the Authority should treat the entire response as incorrect and incomplete and is not of any pursuable legal tenability.
- p. All the questions are answered in the concerned Response by treating HFCC as the relevant entity. For example list of shareholders, details of factories involved etc of HFCC is provided whereas what is relevant as can be seen from the facts disclosed is replies to these questions by HCC as the entity and not HFCC which ceased to exist on 29.2.2016 well within the POI. The incorrect and inappropriate answers provided cannot be rectified at this juncture and the Response as such should be rejected.
- q. It can be noted that any response by HCC would have to be significantly different from that of HFCC and the examination of EQ Response filed by HFCC instead of HCC would not help the Authority to conduct any

- examination of dumping. HFCC ceased to exist on 29.2.2016 and the entity relevant to have filed EQ Response in the given scenario is HCC and HCC did not file any EQ Response in effect.
- r. Entire questions in the EQ Response should have been answered by HCC and HCC alone could have sought individual margin and not HFCC. In any case, even if an individual margin is given to HFCC, it is of no use as HFCC is not in existence.
 - s. It is submitted by HCC in the NCV repose that there is one channel involved in the export of PUC into India, however, the name of such exporter is not provided. It needs to be seen whether such exporter involved have filed exporter response.
 - t. HCC has resorted to excessive confidentiality and did not disclose the name of exporter in the channel. How can a name of the exporter be treated as confidential? Can the Authority treat name of an exporter as confidential in the duty table if at all an individual margin is provided? Thus, basic information is kept as confidential in absolute disrespect to the confidentiality provisions and such claim of confidentiality is absolutely bogus which should be rejected by the Authority.
 - u. It is evident from the EQ Response filed TAJ AL Mulook that TAJ AL Mulook is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by TAJ AL Mulook?
 - v. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by TAJ AL Mulook cannot be considered for individual margin determinations.
 - w. It is evident from the EQ Response filed PP and Y International Co. Ltd that PP and Y International Co. Ltd is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by PP and Y International Co. Ltd?
 - x. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by PP and Y International Co. Ltd cannot be considered for individual margin determinations.
 - y. It is evident from the EQ Response filed IMS Corporation that IMS Corporation is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by IMS Corporation?
 - z. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by IMS Corporation cannot be considered for individual margin determinations.
 - aa. It is evident from the EQ Response filed Everlite Korea Co., Ltd that Everlite Korea Co., Ltd is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by Everlite Korea Co., Ltd?
 - bb. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by Everlite Korea Co., Ltd cannot be considered for individual margin determinations.
 - cc. EQ Response filed by the exporter is binding in nature while determining individual margin. EQ Response has been filed by Hanwha Fine Chemical Corporation (HFCC) and not by Hanwha Chemical Corporation (HCC). Thus, granting Individual Margin to HCC does not arise at all. Rule 17 (3) says that “the designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:” and the known exporter or producer concerned in the EQ Response filed is HFCC and not HCC.
 - dd. The issue is not only the correctness of merger of HFCC and HCC as it stands today. Had the EQ Response been filed by HCC, then it was incumbent upon the Authority to examine the correctness of merger. However, since the EQ Response was filed by HFCC which is an entity ceased to exist on 29th February, 2016 and not by HCC, the EQ Response itself is infructuous and no examination can be done on merit.
 - ee. Admittedly, Hanwha has provided the cost of captively produced inputs at the time of verification only including the cost of basic raw material, which were consumed for manufacturing TDA and CDC such as DNT, H2, Chlorine etc. Thus, the Response was incomplete at the time of filing and response needs to be rejected on this ground alone.
 - ff. It is claimed by Hanwha that the Indian Customer transhipped all such goods from TAJ to other countries without entrance of subject goods into Indian Customs and such goods were not consumed in India. The entire claim by Hanwha is unsubstantiated and we request the Authority not to accede to the request of Hanwha on face value to exclude such exports. Interestingly, Hanwha who is the producer from Korea is claiming that material exported through TAJ was transhipped by Indian customer but neither TAJ nor the concerned Indian customer have submitted any documentary evidences to substantiate the claim. In fact, TAJ filed the EQ Response as an exporter of the goods to India and it was nowhere mentioned that the material

- was not destined for Indian consumption. Goods exported by TAJ were at dumped levels and have caused injury to the domestic industry among other producer/exporters and such exports cannot be excluded for the purposes of margin calculations as prayed by Hanwha.
- gg. The response filed by Hanwha may be rejected and no individual margin for Hanwha should be determined based on its response which is grossly incomplete and incorrect.
 - hh. There is no basis to say that normal value for China PR should be based on price in China PR. There aren't any responses from producer/exporter who have exported the PUC during the POI from China PR in the present case. Hence, Normal Value (NV) has to be based on best available information and also by applying the principles of non-market economy.
 - ii. The contentions that reduction in price of TDI are on account of reduction in international price of raw materials has no basis. Decline in the price of raw materials over the years has no meaning since the dumping margin found is positive. The exporters have been selling at a higher price in its domestic market even after such reduction in major raw material prices and resorted to exports at lower prices to India viz. it domestic prices resulting in dumping.
 - jj. The reduction in Toluene price does not negate the admitted dumping margin in case of cooperative exporters and also country wide margins. Raw Material (RM) prices have shown declines but what matters is the difference in prices domestically offered by the exporters and at what price they have exported to India. As long as the margin of dumping is positive, reduction in RM prices have no meaning and the DI is clearly fighting against the practice of dumping adopted by the producers/exporters of subject goods from subject countries and not any mere reduction in price of the TDI on account of any decline in RM prices.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

32. The Authority notes that the relevant provisions laid down under Annexure I to the Antidumping Rules with regard to "Market Economy Treatment" are as follows;

[8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country.

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate:

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph]."

[(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a member of the World Trade Organization]."

33. The Authority also notes that Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

34. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraphs shall expire in 15 years from the date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th December, 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2015 to March, 2016. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevailed in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
35. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules. However, there are not any participation by producers/exporters from China PR who have exported the subject goods to India during the POI, therefore, it is noted that the presumption of NME which was prevalent during the POI is not rebutted as provided in the Rule. It is also noted that since investigation has been initiated on 5.10.2016 and the POI determined for the present investigation is April 2015-March 2016, the provisions of China Accession Treaty which says that WTO Members could use an NME antidumping methodology till December 11, 2016 in case of an antidumping investigation against Chinese producer/exporters is well applicable in the present investigation vis-à-vis China PR.
36. With regard to the contentions raised by the domestic industry regarding the correctness of EQ Responses by Hanwha and the correctness of its cost, the Authority notes that the issue is examined in detail by taking into account the claims of Hanwha and also the submissions of the domestic industry. Individual margin for Hanwha Fine Chemical Corporation (HFCC) was determined in the provisional finding as the preliminary examination of the response showed that the entity in question was HFCC and the preliminary view was taken on such basis pending further investigations. The entity which was in effect at the time of filing the EQ Response was Hanwha

Chemical Corporation (HCC) which was formerly known as Hanwha Fine Chemical Corporation (HFCC) and the entity HFCC ceased to exist as on 29.2.2016. The records of the company were subjected to examination to ascertain the facts of merger of HFCC in HCC eventually and it is noted that the claims are as per records of the company which has been subjected to verification. Submissions were also made by Hanwha that the entity which has filed the response effectively is HCC and the name of HFCC was used in the EQ Response only because the exports during the POI were made by HFCC. Considering the records of the company that has been submitted for verification and based on the verification, it is noted that granting individual margin concerning Hanwha Chemical Corporation shall not be against the facts as per records and accordingly the individual margins are determined in this final finding considering Hanwha Chemical Corporation.

37. With regard to the contentions of the domestic industry that the company did not file complete details along with the EQ Response and various information has been submitted at the time of verification and thereafter, the Authority notes that information required from HCC for the determination of their cost of production concerning the subject goods have been availed by the exporter and the same was subjected to necessary verification. Only such complete and verified information is considered for determination of cost of production of the subject goods produced by HCC.

a. Determination of Normal Value

38. Under Section 9A (1)(c), “normal value” in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

39. Paragraph-7 of the Annexure-1 to the Anti-dumping Rules provides as follows:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”

40. According to these Rules, the normal value in NME countries (China in the present case) can be determined on any of the following basis:

- a) On the basis of the price in a market economy third country, or
- b) The constructed value in a market economy third country, or
- c) The price from such a third country to other countries, including India.
- d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

i. China PR

41. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR, who have exported the subject goods to India during the POI, have responded in the form and manner prescribed. Thus, none of the producer/exports in the present investigation from China PR could be found to be operating under market economy condition for determination of normal value in terms of Para-6 of Annexure-1 to the Rules. Under this circumstance, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the Chinese producers/exporters and the Authority has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure - I to the Rules supra.
42. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. No such information with regard to prices and costs prevalent in these markets have been provided either by the applicant or by the responding exporters, nor any publicly available information could be accessed, nor the responding Chinese companies have made any claim with regard to an appropriate market economy third country. Therefore, the Authority proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis.
43. The Authority determines the Normal Value for China PR on best available facts basis in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the Normal Value of the product under consideration has been determined based on the international price of the major raw material, consumption norms of the petitioner, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so determined is *** US\$/KG

ii. Japan

44. The Authority notes that none of the producers/exporters from Japan has responded to the Authority in the present investigation. In view of the same, the Authority has determined the Normal Value based on the international price of the major raw material, consumption norms of the petitioner, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. which is *** US\$/KG

iii. Korea RP

45. The Authority notes that EQ Responses has been filed by two producers from Korea RP namely M/s BASF Company Ltd and M/s Hanwha Chemical Corporation.

a) BASF Company Ltd

46. The authority notes that BASF Company Ltd ("BASF") has submitted the exporters' Questionnaire response claiming to be a producer cum exporter of subject goods and informed that it has exported the subject goods directly to India. The authority notes that BASF has submitted details about domestic sales in Appendix-1.
47. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80%, then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. It was also noted that the loss making transactions were more than 20% of the total domestic sales. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based only on the profitable sales in terms of the provisions of Annexure I of the AD Rules.
48. M/s. BASF has claimed adjustment on account of rebate, inland freight and packing cost. The authority has accepted all the adjustments with due verification for the purpose this final finding. Accordingly, normal value is determined is *** US\$/KG

b) Hanwha Chemical Corporation (HCC)

49. The Authority notes that Hanwha Chemical Corporation ("HCC") has submitted the Exporters' Questionnaire response claiming to be a producer of the subject goods in Korea RP and informed that it has exported the subject goods to India indirectly through unrelated exporters/traders. It has also been submitted by HCC that the company has exported the PUC to India through three exporters/traders and they have filed EQ Responses along with HCC.
50. The response filed by HCC has been examined for the purpose of determination of normal value concerning HCC. It is noted that HCC produces main raw materials namely TDA and also CDC as intermediates. The cost of such intermediates captively produced by them has been examined in detail and fair cost of the subject goods produced by HCC has been determined accordingly and the same is used for the purpose of OCT tests. It is noted that 86% of the sales was loss making and hence the normal value is determined based on the profitable sales. Accordingly, the Authority has determined the normal value is *** US\$/KG.

c) Normal Value for other producers and exporters in Korea RP

51. The Authority notes that no other producers/exporters from Korea RP have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Korea RP, the Authority has considered the normal value of the cooperative exporter and the same is *** US\$/KG.

b. Determination of Export Price**i. China PR**

52. The Authority notes that none of the producer/exporter from China PR, have responded to the Authority in the present investigation. In view of the non-cooperation, the Authority has determined net export price for all producers/exporters on the basis of DGCI&S import data with due adjustments as claimed by the petitioner and the same is *** US\$/KG.

ii. Japan

53. The Authority notes that none of the producer/exporter from Japan, have responded to the Authority in the present investigation. In view of the non-cooperation, the Authority has determined net export price for all producers/exporters on the basis of DGCI&S import data with due adjustments as claimed by the petitioner and the same is *** US\$/KG.

iii. Korea RP

54. The Authority notes that EQ Responses has been filed by two producers from Korea RP namely M/s. BASF Company Ltd. and M/s. Hanwha Chemical Corporation. While it has been submitted by BASF Company Ltd that they have exported the PUC directly to India, however, it has been submitted by Hanwha Chemical Corporation that they have exported the subject goods through unrelated exports/traders M/s PP and Y International Co. Ltd., M/s. IMS Corporation, M/s. TAJ AL Mulook General Trading LLC and M/s. Everlite Korea Co., Ltd has filed their EQ Responses and are cooperating with the Authority.
55. Exporters namely M/s. PP and Y International Co. Ltd, M/s. IMS Corporation and M/s. Everlite Korea Co., Ltd has filed their EQ Response and claimed that they have exported the subject goods produced by M/s Hanwha Chemical Corporation to India during the POI.
56. EQ Response have also been filed by M/s. TAJ AL Mulook General Trading LLC, a UAE based Trading Company, claiming that they have exported the subject goods produced by M/s Hanwha Fine Chemical Corporation through Korean exporter namely M/s. PP and Y International Co. Ltd.

a) BASF Company Ltd

57. The Authority notes from the EQ Response filed by BASF Company Ltd that BASF Company Ltd has exported the subject goods to India during the POI directly. BASF have reported a total export of 11340 MT in their Appendix-2 and claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed. Accordingly, the net export price determined as *** US\$/KG

b) M/s. Hanwha Chemical Corporation (Producer) and M/s. PP and Y International Co. Ltd. (Exporter)

58. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s PP and Y International Co. Ltd claiming themselves as an Exporter of subject goods from Korea RP of the subject goods produced by M/s Hanwha Chemical Corporation. Appendix-2 filed by M/s PP and Y International Co. Ltd shows that they have exported 2200 MT of subject goods produced by Hanwha Chemical Corporation to India during the POI. PP and Y International Co. Ltd. has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed. Accordingly, the weighted average net export price has been determined as *** US\$/KG.

c) M/s. Hanwha Chemical Corporation (Producer) and M/s. IMS Corporation (Exporter)

59. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s. IMS Corporation claiming themselves as an Exporter of subject goods from Korea RP of the subject goods produced by M/s. Hanwha Chemical Corporation. Appendix-2 filed by IMS Corporation shows that they have exported 560 MT of subject goods produced by Hanwha Chemical Corporation to India during the POI. IMS Corporation has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed. Accordingly, the net export price has been determined as *** US\$/KG.

d) M/s Hanwha Chemical Corporation (Producer) and M/s. Everlite Korea Co., Ltd. (Exporter)

60. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s. Everlite Korea Co., Ltd claiming themselves as an Exporter of subject goods from Korea RP of the subject goods produced by M/s Hanwha Chemical Corporation. Appendix-2 filed by M/s. Everlite Korea Co., Ltd shows that they have exported 180 MT of subject goods produced by Hanwha Chemical Corporation to India during the POI. M/s. Everlite Korea Co., Ltd has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed. Accordingly, the net export price has been determined as *** US\$/KG

e) **M/s. Hanwha Chemical Corporation (Producer), M/s. PP and Y International Co. Ltd. (Exporter) and M/s. TAJ AL Mulook General Trading LLC, UAE (Trader).**

61. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s. TAJ AL Mulook General Trading LLC. M/s. TAJ AL Mulook General Trading LLC have claimed that they are a trading company based in UAE and have Exported the subject goods produced by M/s. Hanwha Chemical Corporation to India during the POI through the exporter from Korea RP namely PP and Y International Co. Ltd. Appendix-2 filed by M/s. TAJ AL Mulook General Trading LLC shows that they have exported 1000 MT of subject goods produced by Hanwha Fine Chemical Corporation to India during the POI. During the course of verification, they could not provide the complete chain of supply up to the Indian customer. In view of this export price of the trader through M/s. PP and Y International could not be determined.

f) **Export Price for non-cooperating producers and exporters from Korea RP**

62. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Korea RP, the Authority has determined the net export price on the basis of export price of a cooperative exporter and the same is *** US\$/KG.

c. **Determination of Dumping Margin**

63. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from subject countries has been determined by the Authority and the same is as follows;

| S. No. | Country | Producer | Exporter | Normal Value - US\$/Kg | Export price - US\$/Kg | Dumping Margin - US\$/Kg | Dumping Margin - % | Dumping Margin Range- % |
|--------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | China PR | Any | Any | *** | *** | *** | *** | 15-25 |
| 2 | Japan | Any | Any | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 3 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | PP and Y International Co. Ltd | *** | *** | *** | *** | 10- 20 |
| 4 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | Everlite Korea Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 5 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | IMS Corporation | *** | *** | *** | *** | 5-15 |
| 6 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | PP and Y International Co. Ltd, Everlite Korea Co., Ltd IMS Corporation | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 7 | Korea RP | BASF Company Ltd | BASF Company Ltd | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 8 | Korea RP | Any other than the producers at S.No 3 to 7 above. | Any other than the exporters at S.No 3 to 7 above. | *** | *** | *** | *** | 30-40 |

G. Injury Determination**G.1 Injury Examination****Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

- i. The pricing of the subject goods in Indian market is comparable with other suppliers of the same product such as GNFC, which is the major local player.
- ii. Imposition of duty may lead to monopoly as GNFC is the sole producer and it will restrict the availability of the material to Indian buyers.
- iii. Imposition of duties may lead to demand supply gap India. Indian industry cannot supply to the 100% demand. Local manufacturers of downstream products will suffer if anti-dumping duties are imposed.
- iv. Certain unique situation in this case are sudden and substantial capacity expansion by the Petitioner, plant shut-down of the petitioner in 2014 and selection of POI merits reconsideration. These factors should be considered in the context of injury claimed.
- v. In the year 2013-14, the installed capacity of the Petitioner was 14000 MT. In the year 2014-15, this installed capacity was increased 4-5 times, to 64000 MT. There is a substantial gestation period for achieving break-even profits and even for achieving normalcy and stabilizing capacity utilization. In such a case, the Petitioner's claim of injury for the following year, i.e., 2015-16, is premature, unwarranted and completely misleading. The Petitioner's fixed costs also increased in the year 2014-15 and 2015-16 (POI) period.
- vi. The Petitioner has conveniently withheld the fact that their plant remained shut down in 2014, from January when there was a fatal gas leak on the plant premises up to November. Injury was also suffered by the plant owing to this shut-down for an entire year. The Petitioner has been slow to recover from the same and to regain its capacity utilization.
- vii. The POI is an odd-period, during which the losses of the Petitioner are clearly inflated. The Petitioner in its Annual Report for 2015-16 (POI) admits that the POI was a unique year, which experienced low TDI prices due to increased global capacities.
- viii. It is clear that while prices of subject goods from subject countries remained steady throughout the period of injury, they declined only in the POI, admittedly due to the global overcapacity. However, the price in the period post-POI has increased substantially, before the imposition of any provisional duties. The Authority should have considered such unique factors prior to issue of its Preliminary Findings and a more recent period of investigation should have been selected.
- ix. During 2014 wherein there was plant shut down, the Petitioner's capacity utilization has been critically low at 37.09%. The Petitioner does not attribute its injury to this factor, but simply blames imports for its losses.
- x. International prices of raw material have not been provided / considered at all. In fact, over the period of Injury and up to the POI, the prices of TDI have fallen consistently, globally. Thereafter, the prices of TDI have increased.
- xi. There is no mention of a non-injurious price ("NIP") and no calculation thereof to support the allegation of price underselling and suppression which has been claimed. Even the Authority has not shared the methodology for determination of NIP nor the trend of NIP for the Petitioner.
- xii. The sudden and substantial capacity expansion of the Petitioner of about 4-5 times original capacity in the base year, coupled with a complete years' shutdown in 2014 has led to decreased profitability. The same is also responsible for increased interest and depreciation costs, evidenced in the Petitioner's own data, which has increased the petitioner's losses.
- xiii. There is no increase in volume of dumped imports in relation to production or consumption in India and neither has the Petitioner made such a claim. Thus, there is neither absolute growth (considering special circumstances and growth in demand) nor any relative increase in import volumes.
- xiv. The demand for the product has shown significant growth. The trend of imports from the subject countries clearly shows a declining trend. Thus, the subject countries have lost market share, in the face of growing demand, from almost 60.76% in 2012-13 to 49.87% in the POI. The indexed trend shows absolute growth of a mere 7 indexed units compared to the DI growth of 89 indexed units. Moreover, the growth in market demand has been effectively captured by the Petitioner, whose share has increased from a meagre 34.32% in 2012-13 to a substantial 50% in the POI.
- xv. The increase in the imports from the subject countries is merely 6.70% over the base year, which amount to only 3.13% of the overall increase in demand. Demand increased by about 30%. This entire quantum of increase in demand has been taken over by the Petitioner, except for 3% attributable to the imports. In

- absolute terms, imports from subject countries have increased by 2018 MT between 2012-13 and POI, whereas the Demand has increased by 14867 MT in the same time period. It is evident that Imports have decreased in relation to production of the domestic industry.
- xvi. There is no price undercutting throughout the period of injury for all the subject countries. Contrary to the claims of the petitioner, there is no price suppression/ depression or price underselling. This is because the Petitioner's costs are inflated due to inherent reasons. In any case, where prices of a product are falling globally, the decreased price of imports cannot be said to be "unfair" or "dumped".
 - xvii. For the purposes of analysing injury based on economic parameters of the Petitioner, price underselling is not a relevant criterion. In the case of *Nirma Ltd. v. Union of India* [Special Civil Applications No.16426/2016 & 16427/2016], the Gujarat High Court clarified that the determination of underselling would only be relevant once injury had been established, based on other economic parameters.
 - xviii. The Authority's consideration of "price underselling" as a factor in determination of injury is unjustified. The Authority may duly rectify this error prior to issue of any Final Findings.
 - xix. For analysing price suppression / depression, the Authority is required to determine a Non Injurious Price (NIP) for the Petitioner. Determination of the NIP, should factor in factual situation of the Petitioner such as increased cost of production of the Petitioner due to capacity expansion, losses due to plant shutdown for a year and decreased global prices has led to an inflated NIP. Even an examination of the Petitioner's export prices would have been reflective of the reasonable non-injurious price for the DI.
 - xx. The construction of the NIP must disregard the exceptional costs, if any, incurred by the Petitioner. Only the cost of efficient production must be considered in the NIP. In the present case, the excessive overheads incurred towards sudden and substantial capacity expansion, the losses because plant shutdown and resultant inactivity as well as the losses because of global price decline have been erroneously factored into the Petitioner's NIP.
 - xxi. Contrary to the Petitioner's claims that selling prices had to be lowered despite increasing cost of production, the cost of production of TDI decreased in the subject period. It is the costs of production of the Petitioner which are unnaturally increasing, despite falling TDI prices. In fact, the global prices of TDI fell, not just in the Indian market but across Asia. In addition to this, the Petitioner itself has admitted, in its Annual Report for 2015-16 (POI) that the POI was a unique year, which experienced low TDI prices due to increased global capacities.
 - xxii. The Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales figures show growth. The profitability of the Petitioner is affected by the capacity expansion and plant shut down in 2014. The wages and productivity of the Petitioner has increased-even though some injury is exhibited, by the Petitioner, pertaining to these factors.
 - xxiii. The injury by the parameters of wages and productivity is not attributable to the imports from the subject countries. The low return on investments is clearly attributable to the high interest and depreciation. These factors are, in turn, attributable to the capacity expansion and plant shut down.
 - xxiv. The Petitioner claims injury by virtue of increased inventories. However, the increase in inventories is directly correlated to the increase in sales volume of the Petitioner. The Authority must rely on the principles laid down by the CESTAT in *Bridgestone Tyre Manf. v. Designated Authority*, while considering the correlation between inventories and sales of the Petitioner in which it was stated that "Compared to increase in sales volume, the level of inventory has almost remained the same percentage-wise and this cannot therefore be straightaway considered to be an injury indicator."
 - xxv. With respect to the Capital Employed, an analysis of the Capital Employed and Return on Capital Employed must necessarily consider the costs of interest and depreciation of the Petitioner. It is submitted that the injury to the Petitioner is caused by the continuously increasing interest and depreciation costs, which are a result of the capacity expansion of 4-5 times the original capacity.
 - xxvi. The increased losses and negative cash flow squarely coincide with relevant facts of capacity expansion in a sudden and substantial manner coupled with the plant shutdown in 2014.
 - xxvii. The sudden and substantial capacity expansion, the plant shutdown for 2014 and the global decline in prices of TDI are factors that are clearly affecting the Domestic prices.
 - xxviii. It is highly suspect that wages per unit have almost doubled over the period of four years. This is a factor in the increasing cost of production of the Petitioner, a factor that is in no way attributable to imports from the subject countries.

- xxix. Further, the number of employees has grown 4.5 times, which is commensurate to capacity expansion, but not commensurate to the actual production figures of the Petitioner. The cost of a larger workforce, without balanced increase in production, is the reason for the injury being suffered by the Petitioner.
- xxx. It is crucial to note that while the overall productivity increased 2.5 times, in response to capacity increase and workforce expansion of 4.5 times, the per employee productivity actually halved. Thus, the capacity expansion and the resultant workforce expansion without commensurate growth in production / productivity have taken a toll on the profits of the petitioner.
- xxxi. The Authority has made no such “further” specific findings regarding the necessity of application of provisional duties. The present Preliminary Findings do not allow for imposition of any provisional duties.
- xxxii. The Authority may duly consider the normalized and stabilized TDI prices in the post-POI period for calculation of duty margins qua BASF. The post-POI data shows a very different situation since the price of the product has increased globally. This fact itself establishes that the POI as selected by the Petitioner is anomalous.
- xxxiii. The domestic industry has not provided positive evidence that it has been materially injured due to alleged dumped imports from the subject countries.
- xxxiv. There was no significant increase in volume of dumped imports either in absolute terms or relative to production and domestic consumption/demand. Also, recording of the factual position in this respect in the provisional finding does not appear correct. It can be seen that there is no significant increase in imports in the current investigation as required under the provisions of para (ii) of Annexure II and the current investigation may please be terminated on this ground alone.
- xxxv. In determining price effects, the imports from subject countries ought to have explanatory force for the occurrence of the significant price effect for the domestic industry. The WTO Appellate Body in China-Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from US has found that the domestic industry is required to provide reasons as to how the pricing trends played a role in affecting the domestic prices. There is no price undercutting as per the PF that the landed values of the imports are higher than the domestic prices of the subject goods.
- xxxvi. With regard to price underselling, it is submitted that it is not a factor of injury to be examined and analysed as part of the price effect of subject imports on the domestic prices as may be seen from Para (ii) of Annexure II.
- xxxvii. There is no analysis as to how the prices of the domestic industry declined more than the decline in the landed values of the imports. Also what are the reasons for increase in the cost for the domestic industry when the prices of major raw materials, such as Toluene and Nitric Acid, declined over the injury investigation period is also need to be examined. The decline in domestic prices could well be explained and linked to the significant decline in raw material prices.
- xxxviii. The domestic industry is required to demonstrate that the reduction in the domestic prices is attributable and due to the effect of dumped imports. However, this is totally absent in the current investigation.
- xxxix. The cost of depreciation, interest and wages has substantially increased by 153%, 1541% and 373% respectively over Injury Investigation Period. Therefore, the reasons for the increase in the cost of the domestic industry for the subject goods are the increase in the cost of depreciation, interest, wages and overheads as a result of increase in the capacity of the domestic industry by 50000 MT. Therefore, there is no such case of price prevention in the current case as well, as alleged by the domestic industry
- xl. There has been significant increase in sales, market share, capacity, production, no. of employees, wages, capacity utilization etc. which shows no injury. Also, there is only very minimal increase in average inventory. The productivity per employee in the current investigation has significantly come down by more than 44% over the injury investigation resulting into increase in cost and injury to the domestic industry but not the dumped imports.
- xli. Profitability, cash flow and return on investment suffered because of higher cost due to other factors. Also, the ability of the domestic industry to raise capital for investment is not affected. Thus, the economic factors of the domestic industry have shown improvement and for the factors that have shown to be negatively impacted are not due to the imports from the subject countries but are affected due to other factors.
- xl.ii. Demand of the subject goods has witnessed around 30% increase in the period of investigation when compared to the base year. However, said increase is very minimal when compared to the corresponding increase in the production and sales of the domestic industry during the same period.
- xl.iii. The production of the domestic industry has increased from 17,845 MT in the base year to 45,680 MT in the POI, a huge increase of around 250%. It is evident that the production of the domestic industry has improved

gigantically from base year to the POI. The said increase is even more significant in view of the fact that in the base year the domestic industry was operating at above par capacity of around 128%.

- xliv. The growth in terms of production and sales has been tremendous. The domestic industry has achieved highest sales volume in domestic market during the POI. Thus, there is no adverse impact on this factor because of the alleged dumped imports.
 - xliv. As per the preliminary findings, the market share of the Domestic industry has increased from 34% in the base year to around 50% during the POI. On the other hand, the market share from subject countries has reduced from 61% in the base year to 49.87% during the period of investigation. The annual report of the domestic industry clearly shows that they held 54% market share during the FY 2015-16.
 - xlvi. Since the domestic industry has increased its capacity massively by around 460% in 2014-2015, any expectation of higher capacity utilization within a short period of one year would be not only unrealistic but absurd as well. The annual report of the domestic industry also makes it clear that the lower capacity utilization of the domestic industry was on account of the unstabilized operations in 'Dahej' plant and not on account of allegedly dumped imports thus there were no adverse effects on these factors as claimed by the domestic industry.
 - xlvi. Total market share of Imports from subject countries with respect to demand decreased from 61% during the base year to 49.87% during the period of investigation. Despite of 30% increase in the total demand of the subject good in the country, the volume and market share of the imports from the subject countries has fallen substantially during the injury period.
 - xlvi. The share of the allegedly dumped imports in relation to production of the domestic industry decreased substantially from 168% during the base year to 70% during the period of investigation. There is a fall of 98% in comparable terms.
 - xlvi. The Annual Report of the domestic industry also makes it abundantly clear that during the injury analysis period they have worked without proper technological know how's which have caused them huge losses courtesy to "destabilized" 'Dahej' plant and repeated accidents, failures and seizures. Therefore the respondents reiterate that the losses caused to the domestic industry on account of factors other than 'dumped imports' cannot be attributed to the imports of the subject goods.
 - l. The annual report of the domestic industry clearly shows that the company as a whole, but for the 'Dahej' plant has earned huge profits. It has already been established that said 'Dahej' plant incurred losses on account of the admitted inefficiencies and incapability of the domestic industry itself.
 - li. The increase in cost of production and injury was not a natural phenomenon but an artificial situation created by domestic industry's own inefficiency and not on account of the allegedly dumped imports.
 - lii. It has been submitted by the domestic industry that the drop in prices of the product under consideration has been on account of dumped imports from the subject countries. However, they themselves have admitted in their annual report of 2015-16 (POI in the present investigations) that the fall in TDI prices was a global phenomenon and happened due to capacity expansions worldwide.
 - liii. There has been significant increase of 156% in the productivity per day of the domestic industry. The figures relating to employment increase by a whopping 359% in the period of investigation as compared to the base year. Wages increased by 108 % in 2014-15 and 85% during the period of investigation. These parameters show very robust performance as far as wages are concerned. The annual report of 2014-15 of the company also shows that there has been an exceptionally high increase in the salaries and wages.
 - liv. The domestic industry's losses are on account of unprecedented increase in wages which ought to be adjusted appropriately in injury analysis as well as for the calculation of cost/NIP.
 - lv. The fall in the prices of the subject goods is on account of the fall in Toluene prices. The fall in prices in percentage term is almost equal for both toluene as well as the subject goods. The primary reason for the fall in the prices of the subject goods was fall in the toluene prices and not dumping as alleged by the domestic industry.
 - lvi. The DI, in its unaudited Financial Reports has reported that losses from TDI, Dahej unit have reduced so substantially that, overall, substantial profit has been achieved in Q1 of FY2016-17 as opposed to losses in Q1 2015-16.
64. Following are the injury related submissions made by the domestic industry in brief;
- i. The injury information provided in the petition shows that although volume parameters such as capacity, production and sales showed a positive trend in a plain reading, a number of other indicators such as capacity utilization, market share, inventory levels etc. showed a situation of injury.

- ii. The Indian market was dominated by dumped imports by holding more than 50% market share in the domestic demand which is very significant and a level enough to render the position of domestic industry seriously vulnerable to such dumped imports.
- iii. Key parameters relating to the financial situation of the domestic industry, namely profitability, cash profit, ROCE etc turned out to be significantly negative during the POI from a positive situation earlier and, in fact, factors such as return on capital employed, growth etc showed a seriously grave material injury situation.
- iv. In fact the domestic industry has faced huge financial losses on account of aggressive dumping adopted by producers/exporter from subject countries in the injury period except two base years.
- v. The domestic industry has been selling the subject goods below its cost of production since the dumped imports were present at a price less than its cost of production seriously injuring the rights of the domestic industry to realize a remunerative price for the subject goods produced by it.
- vi. The dumped imports were suppressing the domestic prices and serious positive price underselling effects were also evident during the POI. Price undercutting may not be a factor showing injury in this case since the prices are already suppressed and the domestic industry has been selling at a price below its cost. Hence, the question of matching the landed by does not arise and are illogical.
- vii. The inventory levels of the domestic industry substantially increased which shows clear signs of injury. The increase in production needs to be seen in light of the increase in inventory which signifies the fact that the domestic industry has been prevented from selling more in the market by the dumped imports.
- viii. An objective and holistic evaluation of various economic parameters clearly demonstrates that dumped imports from subject countries have caused material injury to the domestic industry. The price effect of the dumped imports has been significant on the basis of price suppression and price underselling and as a result of which profitability of the domestic industry has deteriorated and situation of the domestic turned out to be loss making after two initial years in the injury period, thus, the domestic industry has suffered material injury.
- ix. Even the performance of the domestic industry in terms of volume parameters are also under serious pressure since the capacity utilization have declined and also remained at below par levels while inventory level of the domestic industry have increased and more than 50% of the market share has been held by dumped imports.
- x. In fact, the marginal growth in production and sale has been negated by the overall losses faced by the domestic industry on account of serious price competition from dumped imports. Domestic industry was forced to sell at a price which has not been remunerative and, in fact, below its cost of production. The domestic industry has, thus, suffered material injury and the injury has been caused on account of dumping from subject countries.
- xi. It has been submitted by Covestro (Hong Kong) Limited that their pricing is comparable to that of other suppliers including GNFC. The statement has no legal or factual basis and there is no EQ Response filed by Covestro to substantiate their claims.
- xii. It has been alleged by Covestro that imposition of duty may lead to monopoly as GNFC is the sole producer and it will restrict the availability of the material to Indian buyers. The argument has no legal basis. GNFC is the sole producer of subject goods in India which makes it necessary to protect this company from dumping, else the domestic market will be dominated by foreign players leaving no room for the domestic industry. Also, legally, there is no bar on sole producer to seek protection from dumping. Duties do not ban imports. Imports can be still made but at non dumped prices.
- xiii. It has been alleged by Covestro that imposition of duties may lead to demand supply gap India. The claim has no basis. AD duties are not against imports per se. It would help to remove the injurious effect of dumping. Demand supply gap, if any, does not disqualify a domestic industry from seeking protection against dumping. This Authority has subjected this issue to examination in plethora of investigations and it was consistently found that demand supply gap, if any, is not a reason to permit dumping.
- xiv. The three unique factual situation pointed out by certain opposing parties do not establish that the injury caused to the domestic industry are not because of dumping from subject countries. Capacity expansion was as per the demand in India. Any alleged plant shut downs in 2014 cannot be the cause of injury in 2015-16. Also, the admitted global excess capacity was apparently one of the parameters which triggered dumping and consequent injury.
- xv. The contention that sudden and substantial capacity expansion by the petitioner is the cause of injury is devoid of any merit. The capacity expansions were carried out looking at the robust demand for the product in the country, thus, the DI did not err in carrying out any capacity expansions. However, what has caused injury to the domestic industry is the fact that the exporters got rattled with the capacity additions carried out by GNFC and to keep GNFC away from the market, the exporters resorted to dumping which was very aggressive in the POI.

- xvi. The landed prices of imports were significantly reduced by the POI and such imports were at dumped rates. GNFC was in profit during the base year and the year after that. Any initial glitches of a new plant were at the best noticed at times in 2014-15 and the plant was in normal operation during the POI which is evident in the production and capacity utilisation during the POI. Also, the increase in fixed costs needs to be seen in light of the low capacity utilisation. In any case, NIP is determined based on Annexure III and any alleged effect of higher fixed costs is liable to be not mated and the petitioner will not get any undue advantage of any such alleged higher costs, if any. Thus, capacity expansion per se was not the cause of any injury and other apprehensions of parties viz. fixed costs are also not of any merit.
- xvii. The contention that shutdowns in the new plant during 2014 are the cause of injury is not correct. The operation was normal during the POI and the utilisation was about 71% in POI. DI could have produced much more had there been no dumping. It is also needs to be noted that GNFC was making profits in the initial two years of injury period and faced highest losses during the POI and this was the period wherein the landed price of imports were the lowest coincided with positive dumping margin. In fact, the producer/exporters who were under pressure due to global excess capacities of TDI reduced their prices further and resorted to aggressive dumping in Indian market when the DI in India increased its capacity to the level of Indian demand and the attempt of the exporters were to hold on to the market share in India. As a result of such dumping, the domestic industry suffered injury.
- xviii. It has been contended that selection of POI merits reconsideration which is not of any merit. The DI suffered material injury during the POI considered in the present investigation on account of dumping of subject goods from subject countries and the same is supported by facts which means there are no basis to the argument that the POI merits reconsideration.
- xix. Certain opposing parties have admitted that the prices of TDI declined in the POI due to global over capacities. This establishes that the producers/exporters from subject countries also were under pressure to dispose of its capacities and resultantly they chose Indian market as the target to dump the material as the demand in India have been robust. Had there been no capacity expansion undertaken by GNFC, they would not have reduced the prices to such low levels. When GNFC increased its capacity in line with Indian demand, the exporters from subject countries who were under pressure of excess capacity resorted to aggressive dumping so that they could maintain their market share in the Indian market and keep GNFC away from the market.
- xx. Dumping is evident from cooperating parties and others. Injury is evident. A causal link is also very evident that AD duties must be imposed on imports of TDI from subject countries and PF should be confirmed at the time of final findings.
- xxi. The dumped prices of imports prevented the DI from realising profitable prices in the market. DI was in profit earlier and what triggered the losses during the POI have been the dumped prices offered by the exporters. Significant reduction in prices from subject countries from a level of Rs166/ Per KG in the base year to Rs 113/Per KG in the POI is very evident of the situation that how such prices caused price suppression and depression effects and also losses eventually. The DI was not even able to recover its costs of production in view of the presence of dumped material in the market during the POI.
- xxii. The imports from subject countries have increased in absolute terms by the POI viz. the base year. The DI has also shown increases in some of the volume parameters by the POI especially with the help of capacity additions executed in the year 2014-15 looking at the robust demand for the product in India though the DI could have done better in terms of volume parameters also had there been no dumping. But the DI was restrained from gaining the benefit of any volume increases on price front also as the prices were suppressed and depressed by dumped imports.
- xxiii. The increases in certain volume parameters could not be converted into overall positive situation for the DI in terms of price parameters as well because of dumping. Thus, looking at volume increase on a standalone basis would only give an incorrect picture of injury. During the POI, about 50% of the market share was still held by dumped imports and such levels are significant and the effect of such level is reflected in the pricing adversities of the DI.
- xxiv. Mere reduction in share of dumped imports over the base year wherein the DI had only limited capacity is not a factor which suggests such imports have no consequences on the DI. Thus, the situation of the DI was that certain volume parameters have shown some increases by the POI without any corresponding increase on price parameters that it cannot be said that the DI did not suffer any injury. Even the performance of the volume parameters was below par as the capacity utilisation was only 71% in the POI and there were increases in the inventory during the same period. Had there been no dumping, volume parameters also would have shown much better position.

- xxv. It is not true that the DI's cost is inflated. The NIP is determined as per the principles of Annexure III by the Authority and there is no basis in the argument that the petitioner did not disclose NIP or its trend in the petition.
- xxvi. The injurious effect of dumping is clearly evident in the following parameters in brief;
- a) Imports increased in absolute terms and stood at about 50% of the Indian consumption which was significant enough to distort the market for DI;
 - b) The DI's capacity utilisation was only 71% during the POI and such below par capacity utilisation was when the product marked a robust growth in demand consistently that the production and capacity utilisation of the DI was impacted because of dumping;
 - c) The inventories with the DI increased in the POI. Had there been no dumping, inventories would not have piled up and the DI would have produced more;
 - d) DI suffered financial losses in the POI whereas the DI was operating in profits in the initial 2 years of the injury period;
 - e) Price depression and suppression of a serious nature is evident in the POI;
 - f) Price underselling is positive showing that the DI was not achieving fair price for its product;
 - g) ROI has turned into negative from a positive situation;
 - h) Price undercutting though negative on paper cannot be seen as the core parameter considering the prices effects otherwise as above;
 - i) Growth have been negative on various parameters;
 - j) Dumping margin have been significantly positive from subject countries and also from responding exporters;
 - k) The above points clearly show that the DI suffered volume and price injury and the injury was caused by dumping of subject goods from subject countries.
- xxvii. With regard to the contentions on wages and employment situation of the DI, the level of employment and wages paid to the employees has increased in line with increase in capacity/production and also as per the labour law of the land. The productivity of the company per day has shown improvements. It has been contended that the wages per kg have almost doubled. The wages are as per the audited records of the company. Wage increases as required under the law from time to time have been carried out by the company to the extent feasible. However, maintaining the employment level and wage increases in the future shall depend upon the fair situation of subject goods in the market by way of ADD.
- xxviii. It is an unsubstantiated contention that the level of employment has not been commensurate to the production and the DI suffered because of excess wages and such employment level has impacted the profitability. The level of employment was commensurate with the number of employees required including skilled and unskilled employees to execute the production of the product. The number of employees increased significantly for the first time in 2014-15 with the capacity addition and the same was at comparable levels in the POI. The level of employment or wages per se did not cause any losses but it is the unfair competition from dumped imports which have caused losses to the DI. What has restrained production commensurate to capacity set up by the DI is the presence of dumped imports and any adverse situation on account of low production is also attributable to dumping and cannot be seen separately.
- xxix. It has been contended by certain opposing parties that there have not been any adverse impacts on production and sale of the DI. In a plain reading, it may appear that the production and sale have increased over the base year. But it is relevant to note that the DI could utilise its capacity to the level of 71% only during the POI and what has been produced and sold by the DI in the POI was not the best it could do. The production and sale was not line with the demand in the country as dumping prevented it from selling more at a profitable rate. Thus, production and sale of DI was adversely impacted because of dumping from subject countries.
- xxx. The demand and market share relevant for the present investigation is what determined by the Authority as per its practice and what is reported in the annual report is as per the estimates of the company.
- xxxi. The share of imports from subject countries in Indian demand was very significant in the POI and the DI could not have realised any profitable price in the presence of such dumped imports. Thus, a decline in share of dumped imports over the base year alone is not sufficient to say market share of dumped imports were not of any adverse effects. The actual impact of the market share of dumped imports is apparent in the significant share of such imports during the POI (about 50%) and such significant share was achieved by the exporters by resorting to aggressive dumping. The market share of the DI was adversely affected because of dumping.

Also, though the capacity increased in line with the demand, the Capacity Utilisation during the POI was only 71% which is a below par level and what has caused such low utilisation has been the presence of huge volume of dumped imports from subject countries.

- xxxii. The new plant was fully operational in the POI and the DI could achieve only 71% of capacity utilisation which was due to presence of dumped material in India. Had there been no dumping, the DI would have produced more and sold more. When the demand situation was conducive for more production, the DI ended up in significant level of inventories and below par Capacity Utilisation (CU) as a result of dumping.
- xxxiii. It has been contended that there hasn't been any impact of imports from subject countries on the domestic prices and the cost of depreciation, interest and wages of the DI has substantially increased. The claims are not true. Price undercutting has been negative on paper as ultimately the imported products were cheaper to the consumers. However, price suppression, depression and also price underselling is very evident in the present case. It is also needs to be noted here that price undercutting cannot be seen as the core parameter of price injury here since the effects of price suppression and depression are very evident and the DI is forced to determine its prices as dictated by dumped imports and not in a free and uninfluenced manner. We place our reliance further on various recent investigations wherein the price undercutting has been negative such as Hot Rolled and Cold Rolled steels, Sodium Chlorate etc wherein a clear view has been taken that PU cannot be seen as the key parameter in cases where PU is negative and price suppression and depression have been evident. Also cost of depreciation, interest and wages of the DI has shown similar trend as that of increase in capacity and production. It cannot be said that the injury claimed in the POI are only on account of these factors and on the contrary it can be seen that the dumped prices have caused injury to the DI.
- xxxiv. The contentions of the opposing parties on inventory levels are not true. The submission of such parties itself shows that average stock as percentage of production increased over the base year. Such increase in average stock cannot be termed as minor. And such a situation of inventory was created when the demand was robust and the DI was operating only at 71% capacity utilisation. Thus, the effects of dumping are evident on volume parameters as well.
- xxxv. It has been contended that the productivity per employee in the current investigation has significantly come down by more than 44% over the injury investigation resulting into increase in cost and injury to the domestic industry. The observation is not true. Productivity per day is also important as the company cannot hire and fire its employees on a daily basis and the employment level as per the plant capacity is maintained. What has impacted the productivity per employee is the lower production triggered by dumping. Had there been no dumping, capacity utilisation and meaning there by production would have been higher which would have resulted in better productivity per employee as well. Thus, the deterioration in productivity per employee is also on account of dumping and not for any other reason.
- xxxvi. It has been contended that adverse effects on profitability, cash flow and return on investment are on account of higher cost of the DI. The contention is not true. The DI was earlier making profits and these factors started to deteriorate and turned negative as a result of aggressive dumping of subject goods from subject countries since such prices were creating serious price suppression and depression effects among various other adverse effects.
- xxxvii. The observations of the opposing parties on ability to raise capital investments are not correct. The investments were carried out by the DI two or three years back and such investments made are adversely impacted because of dumping. Thus, any additional capital requirements will have a concern should there be no AD duties against the menace of dumped imports of subject goods from subject countries.
- xxxviii. The claims of opposing parties on the growth parameters as well as conclusions on injury are misleading. The growth have been negative on many parameters especially price parameters. The economic parameters have shown deterioration as a result of dumping which is reflected in below par capacity utilisation, increase in inventory, financial losses, price suppression and depression, negative ROCE etc.
- xxxix. The observations of opposing parties on causal link and non-attribution analysis are unsubstantiated and misleading. There is dumping and injury in the present case and the facts have shown that the cause of injury is dumping of subject goods from subject countries. The various other parameters examined clearly shows that the cause of injury is not any such other factors. The claims of the exporter need to be dismissed accordingly.
- xl. The argument of the opposing parties that the losses to the domestic industry in POI are due to increase in capacity by 357% is baseless. The exporters from subject countries resorted to aggressive dumping upon capacity expansion by DI and such aggressive dumping has caused injury to the DI. Had there been no dumping, DI would have just continued to operate in profit. The DI was in profits earlier.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

65. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
66. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Rule 11 of AD Rules read with para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.
- “The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*
67. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the opposing interested parties and also domestic industry. However, certain specific submissions made by the interested parties addressed by the Authority are as below;
68. With regard to the contention that the exporters’ price is comparable to that of other suppliers including GNFC in the Indian market, it is noted that the statement do not disprove the claims of dumping and injury raised by the domestic industry and is seen as an unsubstantiated statement.
69. With regard to the contention that the applicant is the sole producer in India and any anti-dumping duties on PUC shall lead to monopoly, it is noted that the submission devoid of any merit legally and factually. Anti-dumping duties, if any, are imposed to correct the trade distorting effects of dumping and the Rules do not preclude a sole producer from seeking protection from dumping as per AD Rules,
70. With regard to the contention that the imposition of duties may lead to demand supply gap in India since the domestic industry may not be able to cater to 100% demand in India, the Authority notes that the AD duties if imposed are only to remove the injurious effect of dumping and do not envisage any protection beyond the lower of injury or dumping margin and it will not prevent imports per se and the consumers can still import but at an undumped price from subject countries.
71. With regard to the submissions of the opposing parties that the plant of GNFC have been facing shut down in 2014 and also in February, 2017, the Authority notes that such periods pointed out by the opposing parties are beyond the POI and it was neither substantiated with facts nor ascertained that the injury claimed during the POI are not on account of dumping of subject goods from subject countries and solely on account of any such alleged shutdowns. It has also been brought up by various opposing parties that the petitioner in its annual reports have admitted that the company faced stabilisation issues and also technical issues etc. and a detailed examination of such claims shows that the opposing parties could not establish that dumping was not the cause of injury and the injury claimed were on account of such other reasons.
72. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra.

Cumulative Assessment

73. Article 3.3 of WTO agreement and Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. *The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and*
 - b. *Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.*

74. The Authority notes in this respect that:

- The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
- The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

75. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

G.ii. VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

a. Demand and market share

76. Authority has defined, for the purpose of the present investigation and this final finding, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of like article by the Indian Producer and imports from all sources. The Authority has considered imports into India as per DGCI&S on transaction wise import data to determine the volume and value of imports of PUC into India from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

i) Demand

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| Demand | MT | 49,531 | 51,168 | 57,121 | 64,398 |
| Indexed | Trend | 100 | 103 | 115 | 130 |
| Imports from Subject Countries | MT | 30,097 | 32,171 | 37,232 | 32,115 |
| Imports from Other Countries | MT | 2,438 | 1,983 | 1,319 | 122 |
| Sales of Domestic Industry | MT | 16,997 | 17,014 | 18,570 | 32,161 |

ii) Market Share of domestic industry and imports in Demand

77. Considering imports of subject goods from various sources and sales of subject goods of the Indian Producer, demand was determined and further market share of subject imports, domestic industry and other imports in such demand in India was also examined and the factual position in this respect is as follows;

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|--------------------------------|------|---------|---------|---------|-------|
| Sales of Domestic Industry | % | 34.32 | 33.25 | 32.51 | 49.94 |
| Imports from Subject Countries | % | 60.76 | 62.87 | 65.18 | 49.87 |
| Imports from Other Country | % | 4.92 | 3.88 | 2.31 | 0.19 |

78. It is seen from the above tables that demand for the product in the country has shown positive growth over the injury period and throughout the POI. Any distortions in demand was, thus, not evident. The market share of the domestic industry which was in the range of 30 to 35% between base year and immediate previous year increased to 49.94% in the POI whereas that of imports from subject countries declined to 49.84% in the POI from a 60% level in the base year.

79. Thus, market share of domestic industry has increased over the injury period. Also, market share that of the subject countries stood at about 50% in the demand during the POI though declined over the base year.

b. Import volume and market share of subject countries

80. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analysed as under in this respect.

81. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as per the transaction wise import data provided by DGCI&S. On the basis of this import data on record, the import volume from each subject countries is found to be above the de-minimis levels. Imports volume from subject countries and other countries has been as under: -

| Particulars | | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|-------------------------|-------------------------|------|---------|---------|---------|--------|
| Volume | China PR | MT | 5,729 | 6,738 | 8,572 | 6,724 |
| | Japan | MT | 8,017 | 9,190 | 12,322 | 8,913 |
| | Korea RP | MT | 16,351 | 16,243 | 16,339 | 16,479 |
| | Subject Countries Total | MT | 30,097 | 32,171 | 37,232 | 32,115 |
| | Other countries | MT | 2,438 | 1,983 | 1,319 | 122 |
| | Total imports | MT | 32,534 | 34,154 | 38,551 | 32,237 |
| Market Share in Imports | China PR | % | 17.61 | 19.73 | 22.23 | 20.86 |
| | Japan | % | 24.64 | 26.91 | 31.96 | 27.65 |
| | Korea RP | % | 50.26 | 47.56 | 42.38 | 51.12 |
| | Subject Countries | % | 92.51 | 94.19 | 96.58 | 99.62 |
| | Other countries | % | 7.49 | 5.81 | 3.42 | 0.38 |

82. The imports from subject countries which were 30097 MT in the base year increased to 32115 MT during the POI. Thus, the volume of imports from the subject countries increased in absolute terms.

83. It is noted that the imports of the subject goods into India were primarily taking place from subject countries. The share of imports from subject countries increased in absolute terms and it was more than 90% of the total imports into India throughout the injury period including the POI. In fact, imports from subject countries constituted about 99.62% of the total imports into India during the POI.

c. Share of dumped imports in relation to production and consumption

84. The relevant information concerning share of dumped imports in relation to production and consumption is seen as follows;

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|
| Imports from Subject Countries | MT | 30,097 | 32,171 | 37,232 | 32,115 |
| Production of domestic industry | MT | 17,875 | 16,317 | 23,737 | 45,680 |
| Imports from subject countries in relation to production of domestic industry. | % | 168.38 | 197.17 | 156.85 | 70.31 |
| Imports from subject countries in relation to consumption in India | % | 60.76 | 62.87 | 65.18 | 49.87 |

85. It is noted that though the imports from subject countries increased in absolute terms, the same declined in relation to production and consumption in India.

i. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

86. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

87. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries at the appropriate sections below.

a) Price Undercutting

88. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

| Particulars | Unit | China PR | Japan | Korea RP | Subject Countries |
|-----------------------|--------|----------|--------|----------|-------------------|
| Landed Value | Rs./KG | 123.92 | 111.57 | 110.05 | 113.37 |
| Net Sales realization | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Price Undercutting | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Price Undercutting | % | (18.35) | (9.30) | (8.05) | (10.75) |

b) Price undercutting by cooperative Exporters

| Particulars | Unit | Hanwa | BASF |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Landed Value | Rs./KG | *** | *** |
| Net Sales realization | Rs./KG | *** | *** |
| Price Undercutting | Rs./KG | *** | *** |
| Price Undercutting | % | (6.35) | (6.97) |

89. The authority notes that the price undercutting has been negative from subject countries.

c) Price suppression/depression

90. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The factual position is shown in the table below:

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Cost of production | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 111 | 137 | 123 |
| Selling Price | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 81 | 60 |
| Landed Value (Subject Countries) | Rs./KG | 166.73 | 162.17 | 153.64 | 113.37 |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 92 | 68 |

91. It can be seen from the above table that the cost of production increased from 100 indexed points in the base year to 123 points in the POI, whereas the selling price moved from 100 indexed points in the base year to 60 indexed points in the POI. In the same period landed price of imports from subject countries declined from a 100 indexed points in the base year to 68 points in the POI which shows the domestic industry had reduced the selling price to match the landed value of imports from subject countries. Price suppression is evident in the fact that the domestic industry could not increase its prices in proportion to increase in costs. The selling price of the domestic industry was reduced to a level lower than the prices in the previous period that price depression is also evident. Based on these, it is noted that the landed price of imports was causing price depression/suppression effects on the domestic industry.

H. Economic parameters of the domestic industry

92. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below

a. Capacity, Production & Capacity Utilization

93. Capacity, production and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|----------------------|------|---------|---------|---------|--------|
| Capacity MT | MT | 14,000 | 14,000 | 64,000 | 64,000 |
| Production | MT | 17,875 | 16,317 | 23,737 | 45,680 |
| Capacity utilization | % | 127.68 | 116.55 | 37.09 | 71.38 |

94. It is observed that capacity and production of the domestic industry increased during the POI. The domestic industry undertook capacity additions effectively 2014-15 and the capacity thereafter remained the same during the POI.
95. Capacity utilization of the domestic industry has, however, shown a decline. The domestic industry has been able to achieve a best capacity utilization of 127.68% during the base year i.e 2012-13. However, the same has declined to 71.38% during the POI.
96. It has been claimed by the domestic industry that increase in production should not be seen in isolation since the capacity utilisation remained much lower than optimal levels at 71.38% during the POI. The domestic industry could have catered to the entire Indian demand during the POI had there been no dumping. It has also been submitted by the domestic industry that though the capacity and production increased over the base year, the associated price parameters showed declines and financial losses have been suffered by the domestic industry. This has effectively negated the benefits which ought to have been achieved by the domestic industry by virtue of increase in capacity and production as per the claimant domestic industry.

b. Sales volume and market share

97. Sales volume and market share of the domestic industry is given in the following table:

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|---------------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|
| Domestic sales | MT | 16,997 | 17,014 | 18,570 | 32,161 |
| Demand | MT | 49,531 | 51,168 | 57,121 | 64,398 |
| Market Share of domestic industry in Demand | % | 34.32 | 33.25 | 32.51 | 49.94 |

98. It is noted that sales of the domestic industry showed increases during the POI. The trend of sales is seen in the light of additions in capacity and production and also demand for the product. Though the market share of the domestic industry increased to 49.94% during the POI from a 34.32% level in the base year, the market share of imports from subject countries in the demand remained at about 49.87% in the POI. The domestic industry has not been able to

increase the sales of the subject goods commensurate with the increase in demand because of the presence of dumped imports from the subject countries.

99. It is noted in this respect that the increase in market share of the domestic industry is the result of capacity additions by the domestic industry and domestic industry was able to sell more but at a reduced and at non- remunerative price. It appears that the dumped imports maintained a market share of almost 50% during the POI by creating price depression and suppression effect on the prices of domestic industry as evident from the fact that the domestic industry had to sell at level lower than its cost of production.

c. Inventories

100. The position of inventories noted as average stock with the domestic industry moved as follows;

| | Units | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|---------------|-------|---------|---------|---------|-------|
| Average Stock | MT | 748 | 776 | 1,625 | 2,107 |

101. The Authority notes that the Domestic Industry was left with accumulated inventories during the POI. The levels of inventories have been increasing as compared to the base year and have been at the highest level during the POI. It is further noted that the increase in inventories when the demand and production has been showing increases in the similar period depicts adverse volume effects on the domestic industry.

d. Profit/Loss

102. The profitability of the domestic industry is given in the following table;

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Profits | Rs./Kg | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 48 | (89) | (133) |
| Profits | Rs Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 48 | (98) | (249) |

103. It is noted that the domestic industry has suffered financial losses concerning the subject goods during the POI. The domestic industry was earning profits during 2012-13 and 2013-14. It is noted herein from above that the landed price of imports were creating price depression and suppression effects on the domestic prices in the same period that the domestic industry was not able to increase its selling price commensurate with the increase in cost. It is seen the cost has increased from 100 base points to 123 in the POI, whereas selling price has moved from 100 base points to 60 during the POI due to dumped imports which has dipped from 100 base points to 68 during the POI. The impact of dumped imports is evident on financial losses of the domestic industry.

e. Return on capital employed

104. Information regarding return on capital employed is given in the table below;

| | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| Return on Capital Employed | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 51 | (6) | (21) |

105. The Authority notes that return on capital employed of the domestic industry has deteriorated over the injury period and have been negative during the POI. The domestic industry was able to maintain its ROCE at positive levels during 2012-13 and 2013-14, however, due to the adverse prices effects created by the dumped imports, the profitability and also ROCE has deteriorated.

f. Cash Flow

106. Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table;

| | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|--------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| Cash Profits | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 59 | (53) | (149) |

107. It is seen that the cash profits of the domestic industry declined over the injury period and has been negative in the POI in comparison to the base year. Adverse effects on cash flow are apparent.

g. Factors affecting domestic prices

108. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of the imported material from the subject countries has been below the cost of production of the domestic industry causing significant price suppression in the Indian market. Also, the selling prices have declined viz. the base year also showing price depression. Thus, the factor affecting the domestic prices is the landed value of the subject goods from the subject countries. It is also noted that the petitioner in the present investigation is the sole producer of the subject goods in India which rules out adverse effects of any unhealthy inter se competition among the producers within India. There has not been any significant change in the cost structure during the POI and the costs have declined during the POI over the previous year.
109. It has been an argument that the global prices of TDI have been the lowest during the POI. It is noted in this respect that decline in global prices per se do not rule out dumping causing injury to the domestic industry. It is seen above that due to the suppression and depression in prices, such dumped imports has led to deterioration in profitability and capital employed.

h. Productivity

110. Information regarding productivity is given in the table below;

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Productivity per employee | MT/Nos | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 87 | 29 | 56 |
| Productivity per day | MT/day | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 133 | 256 |

111. It is noted that productivity of the domestic industry per employee shows declines over the base year though the same has increased over the immediate previous year. It is also noted that the productivity per day has increased during the POI. It has been submitted by the domestic industry that the cause of decline in productivity per employee is the result of underutilisation of capacity in the POI owing to dumped imports. Had there been no dumping, the production and resultant productivity would have been higher.

i. Employment and Wages

112. Information regarding employment and wages is given in the table below;

| Particulars | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Employment | Nos. | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 104 | 459 | 459 |
| Wages | Rs/Kg | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 104 | 208 | 185 |

113. It is noted that the employment level of the domestic industry has increased over the injury period and during the POI. Increase in number of employees and also additions in capacity is seen during 2014-15 and both remained the same during the POI. Wages per kg has shown increases during the POI over the base year and declines over the immediate previous year. It is also noted that wages per employee increased but only marginally. It has been submitted by the domestic industry that underutilisation of capacity and below optimal production owing to dumped imports may have resulted in higher element of wages per production, however, the wage increases per employee were very marginal and it has also been submitted by the domestic industry that they have the potential to create more employment in the country viz. the subject goods in the event of level playing situation in the market.

j. Growth

114. It is noted that growth of the domestic industry has been negative in a number of core parameters such as selling price, profits, ROCE etc. Such negative growth is visible when the demand for the product has showed consistent growth.

k. Ability to raise capital investment

115. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made additions in capacity. However, despite these investments and additions in capacity, the performance of the domestic industry has deteriorated and any further investments may also get adversely affected.

l. Level of dumping & dumping margin

116. It is noted that the imports from the subject countries are entering the Indian market at dumped prices and the margins of dumping are significant.

I. CONCLUSIONS ON INJURY

117. On an examination of various injury parameters, it is noted that there has been an increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms. Such dumped import constituted almost 50% of the domestic demand during the POI. Imports have, thus, increased in absolute terms and constituted a considerable portion of the consumption in India during the POI.
118. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression and depression. Effect of dumped imports has been to reduce the domestic prices of the subject goods. Dumped imports have forced the domestic industry to fetch a market price which could not even cover its cost that the domestic industry suffered financial losses.
119. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from the subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of capacity utilisation, inventories, profits, cash profits, return on investment etc. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been significantly affected. This is evident from the fact that the domestic industry was earning decent profits and return on capital employed till 2013-14. However, during the POI, the profits and returns have been negative. Though the capacity, production and sales increased, capacity utilisation declined during the POI apparently as an effect of about 50% share of dumped imports in the domestic demand. The domestic industry would have produced and sold more had there been no such dumped imports. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

J. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

120. Following are the causal link related submissions made by the producers/exporters/ users/ importers etc.;
- i. While conducting the causal link examination factors such as sudden and substantial capacity expansion by the petitioner, plant shut-down of the petitioner in 2014, inherent problems of establishment as listed in the petitioner's Annual Report, cheap exports made by the petitioner and, additionally, the sudden enhancement of exports of about 4 times viz. the base year should be taken into consideration. These factors have led to injury in the domestic market and affected the profitability of the DI.
 - ii. The Petitioner has suffered injury owing to its losses in the export market. While the Petitioner may claim price suppression in the domestic market, there is no reason for it to sell goods in export market at cheaper prices / lower prices. However, due to the increasing cost of production of the Petitioner due to inherent reasons combined with an admittedly low selling price of TDI in the global market, the petitioner has made a substantial part of its export sales on a loss basis.

- iii. There is no causal link between subject imports and the alleged injury to the domestic industry. The application failed to reasonably assess the significance of the increase in volumes, there was no evidence for the significant price effect by the subject imports on domestic prices and the domestic prices were affected mainly due to the drop in the main raw materials prices, and there was no evidence that the domestic industry is experiencing injury and the subject imports have no explanatory force for the status of the domestic industry. Non attribution analysis of such as increase in capacity, decline in raw material prices etc needs to be done to segregate other factors of injury which is not done.
 - iv. There has not been any injury on account of allegedly dumped imports in terms of volume or price parameters. Any injury is on account of mismanagement and inefficiency on the cost factor.
 - v. It is apparent that injury, if any, has been caused solely on account of other reasons. Any injury on account of other reasons should not be permitted to be attributed to imports from the subject countries. Imports from subject countries did not create any adverse effect on volume or price parameters of the DI.
121. Following are the causal link related submissions made by the domestic industry;
- i. Dumping is significant in the present case, domestic industry has suffered material injury and such injury is caused because of the dumping of subject goods from subject countries.
 - ii. Had there been no dumping, the domestic industry would not have suffered any injury in the POI. The dumped imports prevented passing on even cost of production to the customers and as a result profits, ROI, growth on various parameters etc turned negative.
 - iii. Both volume and value parameters put together shows the enormous effect of dumping of subject goods from subject countries on the domestic industry.
 - iv. It has been contended by opposing parties that capacity expansion related expenses are the cause of injury. This contention has no truth. Capacity was expanded effective 2014-15 and the DI was able to recover from any start up issues associated with the new plant before the start of the POI. Thus, the injury that occurred in the POI is not due to expansion of capacity as alleged. On the contrary, the exporters reacted to the capacity expansions by sole Indian producer by resorting to aggressive dumping to destabilise the DI at the initial stage itself and the exporters could do significant harm to the DI with the dumping that they have resorted to.
 - v. It has been contended by opposing parties that the cause of injury could be plant shut downs in 2014 which has no basis. The injury in question concerns 2015-16 (POI) and not 2014. It cannot be said that the injury that have taken place during the 2015-16 period are due to any alleged plant shutdown in 2014-15 and not due to dumping in the POI.
 - vi. It has been contended by the opposing parties that the cause of injury could be the inherent problems associated with establishment as listed in the annual report of GNFC. The opposing parties have done some cherry picking of the discussions in the annual report. Annual report does not have anything in it which vitiates the injury suffered by the DI on account of dumping.
 - vii. It has been contended also that the injury are on account of the cheap exports made by the DI. This is not true. Information of exports is separately provided and the injury claimed is concerning domestic sales only. In fact the DI is competing with the exporters from subject countries in the export market also. In any case, substantial exports were made by the DI during the POI. Else the capacity utilisation would have remained even lower resulting in higher fixed costs. Had there been no exports, much more capacity would have been remained idle leading to higher cost
122. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping from subject countries and material injury to the domestic industry has been done as follows:
- (a) **Volume and prices of imports from third countries**
123. The imports from the countries other than the subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Imports from other countries accounted for less than 0.5% in total. Thus, it cannot be said that imports from other countries have been causing injury.
- (b) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**
124. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject countries compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like article and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

125. The Authority notes that demand for the product showed increase during the injury period and also during the POI. Thus, it can be concluded that the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

(d) Development in Technology

126. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(e) Export performance of Domestic Industry:

127. The details of exports by the domestic industry is as follows;

| Period | Unit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | POI |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Exports | MT | 120 | Nil | 2,714 | 14,947 |
| Trend | Indexed | - | - | 100 | 429 |

128. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In fact, the exports by the domestic industry have increased during the POI. Therefore, any possible decline in export performance is not a cause of any injury.

(f) Productivity of the Domestic Industry

129. The Authority notes that the deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

(g) Performance of the domestic industry with respect to other products

130. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the domestic industry's performance, since being the sole producer. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

131. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially injured over the injury period and during the POI. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- Imports of the subject goods have increased in absolute terms;
- Market share of dumped imports in demand has been about 50% during the POI which is a significant percentage and the same has prevented the domestic industry from producing and selling more which it could have done in the absence of such dumped imports;
- The domestic industry had significant unutilised capacity in the POI even though the demand had increased.
- Inventories of the domestic industry have been on the rise;
- There have been significant suppressive and depressive effects on the domestic prices caused by the dumped imports from subject countries;
- The domestic industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. This is evident from the fact that the domestic industry was earning decent profits and return on capital employed till 2013-14. However, the same been negative during the POI

132. The above analysis shows that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports of PUC into India from subject countries. There exists a causal relation between the dumped imports of the subject goods originating in or exported from subject countries and the injury suffered by the domestic industry.

L. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

133. The Authority has determined Non Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been determined plant wise and accordingly weighted average NIP has been worked out. The weighted average NIP has been considered for comparing the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw

materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows;

| S.No | Country | Producer | Exporter | Non Injurious Price – US\$/Kg | Landed price - US\$/Kg | Injury Margin - US\$/Kg | Injury Margin - % | Injury Margin Range - % |
|------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | China PR | Any | Any | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 2 | Japan | Any | Any | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 3 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | PP and Y International Co. Ltd | *** | *** | *** | *** | 30-40 |
| 4 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | Everlite Korea Co., Ltd | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 5 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | IMS Corporation | *** | *** | *** | *** | 20-30 |
| 6 | Korea RP | Hanwha Chemical Corporation | a)PP and Y International Co. Ltd b)Everlite Korea Co., Ltd c)IMS Corporation | *** | *** | *** | *** | 25-35 |
| 7 | Korea RP | BASF Company Ltd | BASF Company Ltd | *** | *** | *** | *** | 25-35 |
| 8 | Korea RP | Any other than the producers at S.No 3 to 7 above. | Any other than the exporters at S.No 3 to 7 above. | *** | *** | *** | *** | 30-40 |

M. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

134.The comments on Disclosure statement received from various interested parties are summarised I brief as follows;

a) Views of domestic industry

- i. The exclusion of certain products sought by M/s Henkel Adhesives Technologies India Pvt Ltd is unsubstantiated and should not be accepted. Henkel initially requested exclusion of “food-safe TDI having isomer content in 80:20 imported for manufacture of food safe adhesives” and have subsequently changed the request for exclusion to “TDI having specific migration limit of 0.01 mg/kg of food and adherent to the EU Regulation 10/2011 for use in adhesives intended for food contact application. Henkel did not share the details of their imports from subject countries and merely resorted to exclusion requests of a product claimed to have imported by them. The Authority may confirm the position taken in the Disclosure statement viz. certain exclusions from PUC in the final finding.
- ii. It is reiterated that what is important in view of the entire contention by Henkel is the fact that there is no difference in the TDI produced by DI and that is imported into India from subject countries. Domestically produced TDI is like article to the dumped TDI from subject countries in terms of chemical properties, uses, technology etc. Hence, no further exclusion other than what is already provided in the PUC definition should be permitted by the Authority in the final finding also.

- iii. The domestic industry has suffered material injury on account of dumping from subject countries and there is a causal relationship between the two as envisaged in the AD Rules based on facts.
- iv. No individual margin should be determined for Hanwha Chemical Corporation as the entity that exported the subject goods to India and that filed the EQ Response is Hanwha Fine Chemical Corporation and not Hanwha Chemical Corporation. Entire questions in the EQ Response was answered upon by keeping HFCC as the producer/exporter and in such a scenario the Authority did not have any information viz. HCC before it to grant individual margin to HCC.
- v. ADD should be imposed in terms of fixed quantum determined in USD for the purpose of final finding as well. It is submitted that fixed quantum of duty is adopted in majority of investigations by the Authority as the same form is found to be more effective. Any other form of duty in a product like TDI, wherein significant volume of imports take place is imposed as reference price or so, the anticipated remedial effects of any intended protection by way of ADD would all be vitiated and the entire exercise may turn to be futile. Fixed quantum of duty shall work as a minimum protection and a reference price form would only enable the importers and exporters to easily adopt practices to loophole any duty. The DI has already suffered serious financial losses on account of dumping and any form of duty other than fixed quantum in USD will derail its recovery from injurious dumping.
- vi. Post POI performance has no bearing on a fresh investigation. The request of certain interested parties to examine the post POI data, especially to advocate reference prices, is not contextual to the requirements of a fresh investigation. It has been the consistent practice of this Authority not to examine post POI performance in a fresh investigation. The Agreement provided for Reviews to examine developments in the post POI period and considering post POI data in the very fresh investigation may lead to premature and distorting conclusions. This position in the AD Agreement has been identified and upheld by the WTO Appellate Body and we place our reliance on the same. The extracts of the relevant AB Report is enclosed below;

"81. In our view, the Anti-Dumping Agreement takes into account the possibility of such major changes occurring at a late stage of the POI, or even after the POI, not by allowing investigating authorities to pick and choose a subset of data or sub-periods of a POI according to their subjective considerations, but by review mechanisms. Article 11.1 of the Anti-Dumping Agreement is categorical that "[a]n anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury." In furtherance of this general rule, Article 11.2 requires investigating authorities in certain circumstances, including at the request of an interested party after a reasonable period of time, to "review the need for the continued imposition of the duty". The Anti-Dumping Agreement, in sub-paragraphs 1 through 3 of Article 9.3, also lays down that the anti-dumping duty collected shall at no point in time exceed the dumping margin and that any such excess shall be refunded. Therefore, if a major change that occurs during or after the POI has reduced the margin of dumping or eliminated the dumping altogether, these provisions of the Anti-Dumping Agreement ensure that the exporter's legitimate interests are safeguarded" (European Communities – Anti-Dumping Duties On Malleable Cast Iron Tube Or Pipe Fittings From Brazil- WT/DS219/AB/R Dated 22 July 2003

- vii. The Disclosure statement shows that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports of subject good into India from subject countries. It also demonstrates that there exists a causal relation between the dumped imports of the subject goods originating in or exported from subject countries and the injury suffered by the domestic industry. This warrants imposition of definitive anti-dumping duties on all such imports of subject goods into India. We further request the Authority to confirm the provisional duties imposed also and to recommend final duties in terms of fixed quantum in USD.

b) Views of other interested parties

- i. DGAD has considered Hanwha Fine Chemical cost of production for 11 months except SG&A and Financial Cost and ignored the Hanwha Chemical Corporation cost of production for 1 month of the POI. DGAD has considered Hanwha Chemical Corporation SG&A and Financial Cost for 1 month for construction of COP.
- ii. The facts of one year shut-down of the Petitioner's production facility in the Calendar Year 2014 owing to which imports were required to fill in the gap between Indian demand and Indian supply is not taken into consideration.
- iii. The Authority should consider only the old plant for injury analysis as the new plant has clearly resulted in inefficiencies.

- iv. In the context of price depression/suppression, the Authority was required to assess whether the decline in the Petitioner's prices observed by the Authority was attributable to subject imports at all. The underutilization of the capacities of the Petitioner is attributable to its inherent inefficiency and cannot, in any way, be attributed to the imports from the subject countries.
- v. The Authority has not established a clear and indicative causal link between the alleged injury suffered by the Petitioners and the allegedly dumped imports from the subject countries. Sudden and Substantial capacity expansion, Plant Shut-down of the Petitioner in 2014, Inherent problems of establishment etc. are the cause of injury and needs examination in the context of causal link.
- vi. The Authority must note that the only appropriate form of duty, given the unique factual situations of the present investigation, is benchmark form of duty.
- vii. Various submissions on the excessive confidentiality claimed by the domestic industry including the transaction-wise DGCI&S import data may be addressed in the final finding.
- viii. Authority may determine the normal value for the Chinese exporters on the basis of their records but not on the basis of constructed normal value.
- ix. It is reiterated that there is no injury to the domestic industry and there is absence of causal link in the current investigation. In view of the provisions of Para (ii) of Annexure II to the Anti-dumping Rules, the domestic industry is required to first establish that the imports have increased significantly in the POI. It is submitted that the price undercutting in ranges have been kept confidential in the current investigation whereas the same are disclosed in ranges in all other investigations. We request for their disclosure in the final findings.
- x. The domestic prices are moving in the different direction of their own than the prices of subject imports and the import prices have no bearing on the domestic prices. The current investigation may please be terminated on this ground also. *The WTO Appellate Body in China-Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from US* has found that the domestic industry is required to provide reasons as to how the pricing trends played a role in affecting the domestic prices.
- xi. The increase in the cost of the domestic industry is due its inefficiency and closure of its plant for the significant part of the period of investigation due to its instability. The domestic industry is required to demonstrate that the reduction in the domestic prices is attributable and due to the effect of dumped imports.
- xii. The cost of depreciation, interest and wages has substantially increased over Injury Investigation Period. Therefore, the reasons for the increase in the cost of the domestic industry for the subject goods are the increase in the cost of depreciation, interest, wages and overheads as a result of increase in the capacity of the domestic industry by 50000 MT.
- xiii. It is submitted that there is an absence of analysis of other factors that have caused injury to the domestic industry in the current investigation. Factors such as Losses to the domestic industry in POI are due to increase in capacity, increase in cost due to instability of one of its plant, decline in prices of major raw materials needs to be considered for this.
- xiv. Insufficient non-confidential version of the petition has hampered our right to file adequate rebuttals and assist Designated Authority. Such an approach vitiates the object and purpose for which opportunities are provided to the interested parties. This has led to breach of natural justice.
- xv. Recommendation of Provisional Duty not in accordance with the specific requirement of Section 9B. Accordingly, a request was made to withdraw the recommendations. The disclosure statement is silent as to how pre-conditions of Section 9B were met. In view thereof, it is prayed that the Final Findings may not confirm preliminary findings in terms of requirements of Rule 20.
- xvi. Petitioner has not been able to show that there is any dumping and consequent injury to the domestic industry. Annexure II (ii) and (iv) makes it mandatory for the Authority to carry out the examination of the impact of the allegedly dumped imports on the domestic industry within the parameters and guidance prescribed. Detailed submissions substantiating that the parameters show improvement are reiterated.
- xvii. Excessive and impermissible confidentiality has been claimed and allowed by the Designated Authority contrary to specific jurisprudence declared by Hon'ble Supreme Court in the case of Reliance Industries Ltd. Vs. Designated Authority (supra). Further methodology adopted to reach conclusions relating to non-cooperating exporters has been kept confidential despite the fact that it is settled law that the Designated Authority has no right to claim confidentiality. None of the said submissions are dealt with in terms of the requirement of law.

- xviii. Designated Authority has not provided the segregated DGCI&S data in soft copy. Pleadings of the case do not record that any party had claimed confidentiality under any other law on such soft copy of the data. Non supply of the same has resulted in breach of natural justice.
- xix. Reliance was placed on WTO Appellate Body Report in DS 397 European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China, obligating an authority assess the “good cause” and whether the request was sufficiently substantiated. Except quoting the same, the Designated Authority has not dealt with the submission. It is prayed that “reference price” basis duty is the most appropriate duty in the event a decision is taken not to terminate the present proceedings. An ex-parte determination on the form of duty would result in breach of natural justice. The benchmark form of duty is the only appropriate form of duty in the present facts and circumstances.
- xx. Henkel has provided the regulations of EU and US which show that other jurisdictions do maintain, with good cause, a specific regulation and standard that identifies a risk posed by certain products including TDI when used in food-contact applications. These products could contain carcinogenic, mutagenic substances or nano particles and this risk must be mitigated. In the present case, as a global and local supplier, Henkel is required to adhere to these standards.
- xxi. GNFC has created a situation where it cannot/will not supply the subject goods to Henkel owing to its inability to provide the relevant certifications and comply with the required tests, and now it wants to place an undue burden on the Respondent wherein they have to pay antidumping duties and import the same. When GNFC has not completed its own due diligence and where it is clearly unable/ unwilling to supply the product required by Henkel, it appears highly prejudicial for the Authority to not grant exclusion for such a limited product.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

135. It is noted that the comments on Disclosure statement filed by the interested parties are primarily reiterations and reproductions of their earlier submissions in the context of Disclosure statement. All relevant opposing views and submissions are inter alia addressed under the appropriate sections in this final finding which are self-explanatory based on evaluation of the relevant facts and also in view of the relevant rules and jurisprudences to be followed by the Authority. Nevertheless, certain specific comments on the Disclosure statement raised by the parties are addressed as follows;
 - i. With regard to the contention of HCC concerning average Cost of Production of HFCC and HCC, it is noted that during the POI, HCC has not exported any subject Goods, therefore, Cost of Production has been calculated based on 11 months data of HFCC. Since, HFCC were merged with HCC, therefore, SG&A expenses were considered for the merged company i.e. HCC in order to arrive the cost of sales of the company.
 - ii. With regard to the contention of HCC that averaging the dumping/injury margin is not justified, it is noted that individual margin is determined for the producer/exporter that has been investigated for the purpose of individual margins. However, assigning exporters based duty would amount to granting multiple margins to HCC who is the producer of the subject goods. Accordingly, weighted average dumping and injury has been assessed which will culminate in formulation of duty for HCC.
 - iii. With regard to the contention of BASF that the Authority has neglected the factual situations surrounding the import of the subject goods and the Injury analysis conducted by the Authority, it is noted that various examination of facts relevant for the case as provided in this final finding shows that observation of BASF are devoid of any merit. Injury parameters are examined and views are taken looking at the facts and verified information of the case.
 - iv. With regard to the contention of BASF that one year shut-down of the Petitioner’s production facility in the Calendar Year 2014 owing to which imports were required to fill in the gap between Indian demand and Indian supply is not taken into consideration, it is noted that the period mentioned is prior to the POI. In any case, demand supply gap is not any justification for dumping and the duties are not against imports per se but to remove the injurious elements of dumping only.
 - v. With regard to the contention that the Authority should consider only the old plant for injury analysis as the new plant has clearly resulted in inefficiencies, it is noted that injury is determined for the domestic industry. Further, for determining NIP, best utilisation over the injury period has been considered concerning raw materials, utilities etc as provided in detail under the relevant section in this finding. It is also ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production.
 - vi. With regard to the request that Authority may determine the normal value for the Chinese exporters on the basis of their records but not on the basis of constructed normal value, it is noted that normal value for China PR is determined as provided in the rule. It is also noted that no exporter from China PR, who have exported the PUC during the POI, did participate in the present investigation.

- vii. With regard to the contention that the increase in the cost of the domestic industry is due its inefficiency and closure of its plant for the significant part of the period of investigation due to its instability, it is noted that the Authority has ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production.
- viii. With regard to the contention that insufficient non-confidential version of the petition has hampered our right to file adequate rebuttals and assist Designated Authority, it is noted that confidential claims were permitted subject to the provisions of Rule 7 where ever applicable.
- ix. With regard to the contention that recommendation of Provisional Duty not in accordance with the specific requirement of Section 9B, it is noted that provisional duties were recommended as per Rule 12 of the AD Rules by fulfilling all the requirements which was imposed later under Rule 13.
- x. With regard to the contention that petitioner has not been able to show that there is any dumping and consequent injury to the domestic industry, it is noted that various discussion in this final finding specifically addresses all aspects of dumping and consequent injury to the domestic industry.
- xi. With regard to the claims that “reference price” basis duty is the most appropriate duty in the present case, it is noted that the appropriate form of duty based on facts of the case alone shall be recommended in case any such duties are required to be imposed.
- xii. With regard to the claim of Henkel that the Authority’s analysis pertaining to its claim for exclusion of foods safe TDI is incorrect, inappropriate and fails to consider the submissions put forward, the Authority notes that Henkel in its comments on Disclosure statement stated that food safe TDI grades are currently imported from other countries by them. Present investigation has no bearing on imports of TDI from any such other countries. However, Henkel could not show whether there were any import of food safe TDI from subject countries during the POI and how such imported product were different from the TDI produced by domestic industry. Exclusion is considered by the Authority when facts show that the imported material is not like article to the domestically produced goods. As long as the imported TDI and that domestically produced are alike as provided in the Rule, no exclusion can be permitted and accordingly the claim of Henkel is not considered.
- xiii. With regard to the contention of the applicant that no individual margin should be determined for Hanwha Chemical Corporation, it is noted that the facts of exports by HFCC/HCC had been duly verified and it was found appropriate to determine for HCC.
- xiv. With regard to the contention that no individual margin should be given to Hanwha Chemical Corporation due to non- cooperation by M/s TAJ AL Mulook General Trading LLC, it is noted that exports from TAJ AL Mulook were not been considered for determination of individual dumping margin, however, dumping determination for rest of the exporters of the group were made based on the verified data.

N. CONCLUSIONS ON INJURY AND CAUSATION

136. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:
- I. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value, resulting in dumping.
 - II. The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
 - III. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

O. INDIAN INDUSTRY’S INTEREST & OTHER ISSUES

137. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from Iran in any manner and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain multiple sources of supply.

P. RECOMMENDATION

138. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a. The product under consideration has been exported to India from subject countries below their normal values.
- b. The domestic industry has suffered material injury.

- c. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from subject countries. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link thereof in terms of the Anti-Dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury concerning the imports of subject goods originating in or exported from subject countries. Therefore, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from subject countries in the form and manner described hereunder.

139. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of Definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) and in the currency as specified in column (10) of the Table below, is recommended to be imposed from the date of the Notification which may be issued by the Central Government in this regard.

DUTY TABLE

| Sl. No. | Sub-heading | Description of Goods | Country of Origin | Country of Export | Producer | Exporter | Amount | Unit | Currency |
|---------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | China PR | China PR | Any | Any | 0.26 | Kg | US\$ |
| 2 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | China PR | Any country other than those subject to Anti dumping Duty | Any | Any | 0.26 | Kg | US\$ |
| 3 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Any country other than those subject to Anti dumping Duty | China PR | Any | Any | 0.26 | Kg | US\$ |
| 4 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Japan | Japan | Any | Any | 0.15 | Kg | US\$ |
| 5 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Japan | Any country other than those subject to Anti dumping Duty | Any | Any | 0.15 | Kg | US\$ |
| 6 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Any country other than those subject to Anti dumping Duty | Japan | Any | Any | 0.15 | Kg | US\$ |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 7 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Korea RP. | Korea RP. | Hanwha Chemical Corporation | a) PP and Y International Co. Ltd. b) Everlite Korea Co., Ltd. c) IMS Corporation | 0.22 | Kg | US\$ |
| 8 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Korea RP | Korea RP | BASF Company Ltd. | BASF Company Ltd. | 0.31 | Kg | US\$ |
| 9 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Korea RP | Korea RP | Any combination other than mentioned in Sl. No.7 &8 above | | 0.44 | Kg | US\$ |
| 10 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Any country other than those subject to Anti dumping Duty | Korea RP. | Any | Any | 0.44 | Kg | US\$ |
| 11 | 29291020 | Toluene di-isocyanate | Korea RP. | Any country other than those subject to Anti dumping Duty | Any | Any | 0.44 | Kg | US\$ |

140. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 28th March, 2017, however duty recommended above would be applicable from the date of imposition of provisional anti-dumping duty as per Section 9A(2) of the Custom Tariff Act 1975.
141. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

SUNIL KUMAR, Additional Secy. & Designated Authority